हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 जनवरी, 1975

खण्ड 1, अंक 12

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 15 जनवरी, 1975

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(12)1
नियम 45 के अधीन पटल पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उतर	(12)32
कार्य–मंत्रणा समिति का छठा प्रतिवेदन	(12)37
अनुसूचित जातियों तथा अुनसूचित आदिम जातियों के कलयाण सम्बन्धी वर्तमान समिति की पदावधि 31–3–76 तक बढ़ाना समबन्धी वर्तमान समिति की पदावधि 31–3–76 तक बढ़ाना	(12)40
दी हरियाणा ऐप्रोप्रिए ान (नं. 2) बिल, 1975	(12)47
अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त) 1974–75	(12)81
वर्श 1969–70 के अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(12)84

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 15 जनवरी, 1975

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा, विधान भवन, सैक्टर–1, चंडीगढ़ मे 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

Mr. Speaker: Question Hour.

Labour Courts in the State

***1131. Sh. K.N. Gulati::** Will the Minister for Development be pleased to state:-

(a) the total number of Labour Courts functioning in the State at present; and

(b) the total number of Labour Tribunals functioning in the State at present?

Labour Minister (Col. Maha Singh):

(a) One.

(b) One.

श्री के.एन. गुलाटीः जैसे मंत्री महोदय ने बताया कि एक लेबर कोर्ट है और एक लेबर ट्रिब्यूनल है। तो क्या यह बताएंगे कि इनके हैडक्वार्टर्ज कहां हैं और उनके काम को एक ही जज देखता है या डिफरैट ?

कर्नल महा सिंहः लेबर कोर्ट का हैडक्वार्टर तो रोहतक में है और इंडस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल का हैडक्वार्टर फरीदाबाद में है। इनके काम को एक ही प्रिजाइडिंग आफिसर देखता है। एक जगह खाली है उसको सरकार जल्दी भरने की कोि ा ा कर रही है।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि लेबर की तकलीफ को देखते हुए इनके हैड क्वार्टर्ज या तो एक जगह कर दिये जाएं या दूसरा आदमी मुकर्रर कर लिया जाए ताकि लोगों को तकलीफ न हों ?

कर्नल महा सिंहः इस समय इनके आफिस दो जगह हैं, एक रोहतक में और दूसरा फरीदाबाद में। जैसे मैंने अभी बताया कि एक पोस्ट खाली है। इसे फाइनैंि ायल स्ट्रीनजैसी की वजह से नहीं भरा गया था। अब इसे जल्दी भरा जाएगा।

श्री अमर सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि लेबर कोर्ट में 31 दिसम्बर, 1974 तक कितने केसिज पैंडिंग थे और एक साल तक के कितने केस पैंडिंग हैं ?

कर्नल महा सिंहः इसके लिये सैपरेट नोटिस चाहिए।

चौधरी चांद रामः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि न्यायालयों और न्यायाधीकरण को क्या कोई ऐसी हिदायतें हैं कि इतने केसिज को इतने समय में जरूर निपटाया जाए ?

कर्नल महा सिंहः जल्दी से जल्दी निपटाने की हिदायतें हैं और कोि ा ा भी यही की जाती है कि सब केसजि जल्दी से जल्दी निपटाए जाएं।

श्री गिरी ा चन्द्र जो ीिः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो जगह खाली है वह लेबर कोर्ट की हैं या इंडस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल की है ?

कर्नल महा सिंहः लेबर कोर्ट की।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि यह पोस्ट कब से खाली है औरकब तक भरी जाएगी ?

कर्नल महा सिंहः यह जुलाई 1972 से खाली हैं और जैसे मैंने अर्ज किया कि फाइनैि ायल स्ट्रीनजैंसी की वजह से इसको खाली रखा हुआ था। अब सरकार इसे जल्दी भरना चाहती है।

श्री के.एन. गुलाटीः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि चूंकि लेबर की तादाद भी बढ़ी है और केसिज की तादाद भी बढ़ी है तो क्या एक–एक और लेबर और ट्रिब्यूनल कोर्ट मुकर्रर किए जाएंगे ?

कर्नल महा सिंहः अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब में दे चुका हूं कि एक लेबर कोर्ज हैं और एक ट्रिब्यूनल कोर्ट हैं और सरकार के यह विचाराधीन था कि एक और लेबर कोर्ट फरीदाबाद में भुरू की जाए लेकिन फाइनैंि ायल स्ट्रीनजैंसी की वजह से उसको भुरू करना मुनासिब नहीं समझा।

चौधरी चांद रामः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इन कोर्टस को जो केसिज की डिसपोजल है, क्या सरकार उससे संतुश्ट है ? अगर नहीं तो क्या केसिज को डिसपोज करने की रफ्तार को एक एक और कोर्ट खोल कर बढ़ाया जाएगा ?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Government will consider it.

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि आपने जो ट्रिब्यूनल लगाया हुआ है, इसकी टर्म पक्की है या टैम्पोरेरी हैं ?

चौधरी बंसी लालः मुस्तकिल तौर पर है।

Weaving and Spinning Mill

***1189. Sh. Amar Singh:** Will the Minister for Industries be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Weaving and Spinning Mill at Hansi in Hissar District, if so, the time by which it is likely to be implemented?

Industries Minister (Sh. Harpal Singh): Haryana State Co-operative Supply and Marketing Federation Ltd., Chandigarh, is installing only a spinning mill at Hansi which may take about 3 year for completion, depending on the availability of funds.

चौधरी चांद रामः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि एक स्पीनिंग मिल कोआप्रेटिव सैक्टर में सन् 1965–66 में कायम करने के लिए उकलाना में जमीन ले ली गई थी ?

श्री हरपाल सिंहः उकलाना में एक स्कीम थी। उसके लिये जो फंड्ज थे वह लोगों से कलैक्ट करने थे जोकि पूरे नहीं हो सके इसलिये उसका लाइसैंस कैंसिल हो गया था।

श्री अमर सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इसके लिए क्या कोई जमीन एकवायर करने का काम भ्रुरू कर दिया गया है ?

श्री हरपाल सिंहः अभी इनको लाईसैंस मिला है और इस पर जल्दी ही काम भ्रुरू करने वाले है।

चौधरी चांद रामः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि उकलाना में जो मिल लगना था उसमें सरकार ने क्या उधम किया और इस हांसी वाले में क्या करेंगी ? यह मिल कोआप्रेटिव सैक्टर की तरफ से लगाया जा रहा है या सरकार की तरफ से ?

श्री बनारसी दास गुप्ताः हांसी में जो स्पीनिंग मिल लगना है इसको 'हाफैड' की तरफ से लगाया जा रहा है। इसका लाइसैंस मिल चुका है लेकिन अभी प्लानिंग कमी ान से इसकी स्वीकृति लेनी है।

Loans and Grants by the Harijan Welfare Department

***1192. Ch. Dal Singh:** Will the Minister for Social Welfare and Taxation be pleased to state:-

(a) the district-wise amount sanctioned as loans and grants by the Haryijan Welfare Department to Harijans in the State during the year 1973-74; and

(b) the district-wise amount disbursed to Harijans out of the amount referred to in part (a) above during the year 1973-74?

Social Welfare & Taxation Minister (Sh. Shyam Chand): (a) & (b) A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

(a) Sr. No.	Name of District	Amount Sanctioned	
		Loans	Grants
1	Ambala	53850	219800

2	Bhiwani	24850	159600
3	Gurgaon	36500	192290
4	Hissar	56300	310900
5	Jind	25650	121700
6	Karnal	37550	162030
7	Kurukshetra	33100	158700
8	Mohindergarh	35100	119200
9	Rohtak	44000	170420
10	Sonepat	24550	119800
(b) Sr. No.	Name of District	Amount Sanctioned	
		Loans	Grants
1	Ambala	51450	217970
2	Bhiwani	24450	159100
3	Gurgaon	36000	189500
4	Hissar	54500	307300
5	Jind	24650	119000
6	Karnal	36350	159730
7	Kurukshetra	32500	156400
8	Mohindergarh	34500	118700

9	Rohtak	40800	164050
10	Sonepat	23400	100000

चौधरी दल सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि सन् 1973–74 के अन्दर कितने लोन और कितनी ग्रान्ट्स सैंक ान की गई थी ?

श्री भयाम चन्दः यह सारी स्टेटमैंट दे रखी हैं, उसमें से देख लें।

चौधरी दल सिंहः मैं यह पूछना चाहता हूं, जैसे कि इन्होंने जवाब में हर एक जिले की फिग्गर्ज दी हुई है, उनसे पता चलता है कि लोन सैक ान ज्यादा हुए है और डिसबर्स कम हुए हैं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री भयाम चन्दः स्पीकर साहब, जो स्टेटमैंट हमने दी है उससे यह पता चलता है कि एक दो हजार रूपया कम हैं। जहां पर डिसबर्स करना होता है वहां कई लोग लोन लेने नहीं आते। ककई केसिज की वैरिफिके ान से पता चलता है कि उन्होंने ग्रान्ट ली हुई हैं तो उनको भी लोन नहीं देते।

चौधरी फूल सिंह कटारियाः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमे हरिजन कितने है। और बैकवर्ड कितने हैं ?

श्री भयाम चन्दः यह सारा सवाल हरिजनों का है।

चौधरी दल सिंहः रोहतक के लिए आपने 44000 रूपया लोन सैंक ान किया और डिसबर्स किया 40800 ओर इसी प्रकार से ग्रान्ट्स जो हैं वह सैंक ान हुई 170420 और डिसबर्स हुई 164050 तो इसका क्या कारण है ?

श्री भयाम चन्दः अगर किसी को एक साल या दो साल पहले ग्रान्ट दी हो और after verification if we find that he has got earlier then we do not given additional grant.

चौधरी पीर चन्दः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि एक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा कितना रूपया दिया जाता है और कम से कम कितना ?

श्री भयाम चन्दः हर एक स्कीम के लिए एक लिमिट फिक्स है और यह सारी इनफर्मे ान एक डाकुमैंट में दी हुई है जोकि हर मैंबर को भेज रखी है।

चौधरी फूल सिंह कटारियाः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि बैकवर्ड क्लासिज को भी इसमें लोन दिया जाता है, अगर दिया जाता है तो कितना ?

श्री भयाम चन्दः इसके लिए सैपरेट नोटिस दे दें फिर बता देंगे कि कितना दिया जाता है।

चौधरी दल सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि ग्रान्ट्स देने का क्या क्राइटेरिया है यानी किस किस बात का ख्याल रखा जाता है ?

श्री भयाम चन्दः पहले हम एप्लीके ांज इनवाइट करते हैं। उसके बाद हर एक जिले में अंडर दि चेयरमैनि ाप आफ डी. सी. कंसरंड एक कमेटी बनी हुई है, वह प्रायरिटी के हिसाब से देती हैं।

चौधरी पीर चन्दः क्या वजीर साहब बतायेंगे कि मकान बनाने के लिए हरिजनों के लिए कितनी ग्रांट दी जाती है ?

श्री भयाम चन्दः मैंने अर्ज किया है कि हमने हर एक एम.एल.ए. साहब को एक बुकलैट भेज रखा है जिस में हर एक स्कीम के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। यह उसे पढ़ लें। वह पब्लिक डाकूमैंट है।

चौधरी चांद रामः क्या वजीर साहब बतायेंगे कि जो 1973–74 का बजट प्रोविजन था उनकी पूरी रा ि ा तकसीम कर दी गई या नहीं ?

श्री भयाम चन्दः स्पीकर साहब, सबको पता है कि फायनैं ाल स्ट्रीनजैंसी की वजह से हर एक डिपार्टमैंट पर कट लगाया गया और उस हिसाब से इस पर भी कट लगा है।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि कुल कितना अमांउट था और कट कितना लगा है ?

श्री भयाम चन्द: स्पीकर साहब, बजट सब मैंबर साहिबान के सामने पे ा किया गया था, यह उसमें देख लें।

श्री अमर सिंह: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि हाउसिंग के लिए कितनी ग्रांट्स 1973–74 में दी गई है ?

श्री भयाम चन्द: स्पीकर साहब, डिस्ट्रिक्टवाइज टोटल अमांउट पूछा था, वह इनको दे दिया है।

चौधरी फूल सिंह कटारिया: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि जो रकम है यह बहुत कम है, इसलिए यह रकम बढ़ाने के लिए कन्सीडर करेंगे ?

श्री भयाम चन्द: बजट इनके पास है, जितना पैसा पास करेंगे उतना दे देंगे।

चौधरी ि ाव राम वर्मा: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि हरिजनों को मकान बनाने के लिए कितना लोन और ग्रांट दी जाती है और किस हिसाब से दी जाती है ?

श्री भयाम चन्द: मकान बनाने के लिए दो हजार रूपया देते हैं।

श्री अमर सिंहः क्या वजीर साहब बतायेंगे कि 1975–76 में जिलावार कितने मकान बनाने की स्कीम है ?

श्री भयाम चन्दः स्पीकर साहब, जब बजट पास होगा और हमें पैसा मिलेगा तो पता लगेगेा कितने बन सकते हैं।

चौधरी चांद रामः क्या वजीर साहब बतायेंगे कि 1966 से पहले जब पंजाब में हरिजन कल्याण विभाग पर कोई कट नहीं था तो हरियाणा बनने के बाद यह कट क्यों लगाया गया है ?

श्री भयाम चन्दः स्पीकर साहब, जिस जमाने की यह बात करते हैं उस वक्त तो हरिजन बच्चों पर फीस भी लगा दी थी।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, पंजाब के बारे में आपको भी याद होगा क्योंकि आप भी वहां होते थे कि हरिजन कल्याण विभाग पर कभी कट नहीं लगाया गया। यह हो सकता है कि किसी वजह से कभी कुछ पैसा लैप्स हो गया हो लेकिन कट कभी नहीं लगा। तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि हरियाणा बनने के बाद क्यों कट लगा ?

श्री भयाम चन्दः स्पीकर साहब, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि इनके जमाने में तो हरिजन बच्चों पर फीस भी लगा दी गई थी। (विघ्न)

चौधरी दल सिंहः क्या वजीर साहब के नोटिस में यह बात है कि एक ही आदमी ने दो–दो दफा ग्रांट और लोन लिया हो ?

श्री भयाम चन्दः मेरे नोटिस में तो ऐसी बात नहीं है लेकिन अगर उनके नोटिस में है और लिख कर हमारे नोटिस में लायेंगे तो इनक्वायारी करवा लेंगे और देख लैंगे।

राव बंसी सिंहः क्या वजीर साहब बतायेंगे कि और जिलों के मुकाबला में महेन्द्रगढ़ जिला को इस बारे में कम पैसा क्यों दिया गया है, कया एप्लीके ांज कम आई थी या और कोई वजह है ?

श्री भयाम चन्दः हर एक जिला को पापुले ान के बेसिज पर पैसा दिया जाता है।

श्री अमर सिंहः क्या वजीर साहब बतायेंगे कि उनके नोटिस में ऐसी मिसालें हैं कि जिन हरिजनों का स्टैंडर्ड आफ लिविंग पहले ही ठीक है उनको ग्रांट्स और लोन का पैसा दिया गया है ?

श्री भयाम चन्दः लोन और ग्रांट देने के लिए जो आमदनी की लिगिट रखी गई है, उसके मुताबिक ही दिया जाता है।

चौधरी दल सिंहः वजीर साहब ने फरमाया है कि नाम बताओ तो मैं बताना चाहता हूं कि श्री फकीर चंद, एकस एम.एल. ए. नरवाना, फकीरिया सन आफ रानियां, नरवाना, फकीर चंद विलेज कालवां और उकसी औरत ने कर्ज लिया है और यह एक ही आदमी है जिसने यह पैसा लिया है जिसकी आज तक पेमैंट नहीं हुई हैं और डी.सी. जींद ने 1972 में इस बारे मे लम्प सम रिकवरी के आर्डर भी कर दिये थे। तो क्या यह कर्जा उसे चार दफा इसलिये दिया गया है कि वह एक मिनिस्टर का अपने आपको रि तेदार कहता है ?

श्री भयाम चन्दः अब आपने बताया है तो इसकी इनक्वायरी करवा लेंगे।

चौधरी चांद रामः क्या वजीर साहब बतायेंगे कि कट जो लगाया गया वह कितने परसैंट लगा और उसके बाद भी 1973–74 में इस मद में कोई सेविंग हुई या नहीं ?

श्री भयाम चन्दः स्पीकर साहब, वैरीफिके ांज के बाद जिनको ग्रांट या लोन न दिया गया हो, वह रकम किसी जिला में दो हजार और किसी जिला में तीन हजार लैप्स हुई है और कोई सेविंग की बात नहीं है।

***1212. Ch. Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Education be pleased to state the terms and conditions of service of the Vice-Chancellor of Kurukshetra University, Kurukshetra, together with his date of appointment and qualifications?

ि ाक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमति प्रसन्नी देवी): विवरण सदन के सम्मुख प्रस्तुत है।

STATEMENT

(a) Terms and conditions of Service:

i. Pay equal to the pay last drawn by him as Chief Justice of the Assam & Nagaland High Court less the gross pension sanctioned by Government, subject to a maximum of Rs. 3000 per mensem.

ii. Sumptuary allowance at the rate of Rs. 150/- per mensem.

iii. T.A./D.A. according to the rules and regulations of Kurukshetra University.

iv. The use of University staff car for official purposes.

v. Rent free house in the University campus, partially furnished.

vi. Medical facilities under the All India Services (Medical Attendence) rules 1954 as were available to Shri S.K. Dutta before his retirement.

vii. Leave according to Kurukshetra University leave and Casual leave Regulations.

viii. Benefit of Contributory Provident Fund.

ix. He is a whole-Time Upa-Kulapati (Vice-Chancellor) and cannot engage himself directly of indirectly in any trade or business whatsoever without the prior permission of the Chancellor.

x. Any issues not covered by these orders are to be decided by the Chancellor in his absolute discretion an may appear just and fair to him and his decision shall, be final.

(b) Date of appointment: 16-2-1970

(c) Qualification:

i. B.A. (Honours in Economics & Political Science) Calcutta;

ii. B.Sc. (London) with "Government" as a special subject;

iii. Barrister-at-Law of the Middle Temple, London, 1933;

iv. LL.D. (Honoris Causa) Dibrugarh University 1970.

(d) Experience:

i. Worked as Principal, Government Law College, Gauhati from 1937 to 1948.

ii. Worked as Dean of Faculty of Law, Gauhati, University from 1948 to 1950.

iii. Remained Member, Court and Executive Council, Gauhati University from 1948 to 1961.

iv. Worked as legal Remembrancer and Secretary Legislative and Judicial Department, Govt. of Assam from 1950 to 1955.

v. Worked as District and Sessons Judge from 1955 to 1961.

vi. Worked as Judge Assam and Nagaland High Court from 1961 to 1968.

vii. Worked as Chief Justice of the above Court from 1968 to 1970 (till his retirement).

चौधरी राम लाल वधवाः क्या वजीर साहब तायेगें कि उनकी टर्म कब तक है?

ि ाक्षा मंत्री(श्री माडू सिंह मलिक): पहले उनकी टर्म तीन साल के लिये थी उसके बाद तीन साल के लिये और ऐक्सटैंड हो गई । अब वह 15 फरवरी, 1976 को खत्म होगी।

चौधरी दल सिंहः क्या वजीर साहब बतायेगें कि इसवक्त वाइस–चांसलर साहब की उमर कितनी है?

श्री माडू सिंह मलिकः इस वक्त बता नहीं सकता क्योंकि पता नहीं है।

चौधरी चांद रामः क्या वजीर साहब बतायेगें कि क्या जो मौजुदा वाइस–चांसलर है उनको हिन्दी आती है?

श्री माडू सिंह मलिकः जी हां, वह संस्कृत भी पढ़े हैं।

चौधरी चांद रामः संस्कृत तो पढ़े होगें लेकिन क्या उनको हिन्दी आती है जो हमारे प्रदे ा की भाशा है?

श्री माडू सिंह मलिकः वह हिन्दी पढ़ सकते है और बोल सकते है।

चौधरी बंसी लालः हिन्दी आये या ना आये, He has proved to be the best Vice-Chancellor.

चौधरी राम लाल वधवाः उनको आई0जी0 पुलिस लगा दिया जाये ज्यादा बैटर है। (हंसी)

Chaudhri Chand Ram: He is the best Police Officer.

श्री ओम प्रका ा गर्गः क्या वजीर साहब बतायेगें कि जब से यह वाइस–चांसलर आये है, कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी का डिस्पिलिन और इन्तजाम बहुत अच्छा है या नहीं?

श्री माडू सिंह मलिकः स्पीकर साहब, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी सारे हिन्दुस्तान में सबसे जयादा डिस्पिलंड यूनिवर्सिटी है।

चौधरी चांद रामः क्या यह हकीकत है कि वहां पर एक लड़की मिस गुप्ता को, जो रिसर्च पढ़ रही थी, बगैर किसी बात के बगैर नोटिस के , होस्टल छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया?

श्री अध्यक्षः यह सप्लीमैंट्री इस क्वै चन एराइज नहीं होता है A

चौधरी रामलाल वधवाः क्या वजीर साहब बतायेगें कि इस वाइस–चांसलर की टर्म में कितने लड़के ऐक्सपैल हुये और कितने ब्लैकलिस्ट हुये?

Mr. Speaker: Order please. Not a supplementary to this question. The question was aboutthe terms, conditions and qualifications of the Vice-Chancellor.

Supply of Canal Water

***1227. Chaudhri Shiv Ram Verma:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to State-

(a) whether full water supply is being made to the canals in the state;

(b) if not, the extent of shortage of water supply being made to the Western Jamuna Canal System.

(c) Whether there is any likelihood to meet this shortage during the current Rabi Season; and

(d) whether the outlets of Nardak Distributary of the Western Jamuna Canal system are likely to be remodelled, if so, by which time?

सिंचाई एवं विद्युत राज्य मंत्री(सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा):

(क) जी नहीं।

(ख) रबी 1974–75 के दौरान 7–1–1975 तक लगभग 32000 क्युसिक दिनों की कमी थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) अभी तक नरदक डिस्ट्रिब्यूटरी सिस्टम के मोघों को रिमॉडल करने की कोई योजना नहीं है।

चौधरी ि ाव राम वर्माः क्या वजीर साहब बतायेगें कि उन्होने कहा कि रबी की फसलमें पानी बढ़ने की उम्मीद नहीं है तो फिर पैदावार पूरी होने को कैसे आ ाा की जा सकती है?

सरदार हरमोन्द्रि सिंह चट्ठाः स्पीकर साहब, जमुना दरिया के ऊपर कोई डैम नहीं है। जितना पानी उस में ऊपर से आता है, वह दे रहे है। इन–ऐी ान आगुमैंटे ान टयुबवैल्ज इस साल पिछले साल से एक महीना पहले चलाये थे ताकि ज्यादा पानी मिल सके। तो जमना में जितना पानी आता है वह देते है, कोई स्टोर वो वहां है नहीं कि उससे निकालकर देदें।पिछले साल भाखड़ा में पानी ज्यादा था और वहां से पांच–छः हजार क्यूसिक्स जमना साईड में कन्वर्ट कर दिया था ताकि ज्यादा पनी मिले।

चौधरी चांद रामः क्या वजरी साहब बतायेगें कि उन्होने कहा कि उस पर डैम नही है तो यह डैम किसने बनाना है?

सरदार हरमोन्द्रि सिंह चट्ठाः इस डैम के बारे मे पहले भी बात आई थी। यह सैन्टर गवर्नमैंट ऑफ इंडिया के पास है। यह डैम हरियाणा और यू0पी0 का संाझा बनना है, इसलिए इस बारे में गवर्नमैंट आफ इंडिया ने अभी डिसीजन देना है।

चौधरी पीर चन्दः क्या वजीरसाहब बतायेगें कि पिछले साल के मुकाबले में इसमें साल पानी ज्यादा दिया जायेगा?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः स्पीकर साहब, फिर वही बात आई है। जमना में जितना पानी उपर से आएगा, उतना ही दिया जायेगा।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि पानी का भाार्टेज होने के कारण फसल कम होने का सरकार का क्या अनुमान है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः अगर परमात्मा ने बारि ा एक–आध ओर कर दी तो फसल ज्यादा हो जायेगीं।

चौधरी ि ाव राम वर्माः स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने पार्ट ' डी' का जवाब दिया है कि नरदक डिस्ट्रिब्यूटरी सिस्टम के मोघों को री–माडल नहीं किया जाएगा। मैं उन्हे बताना चाहता हूं कि इन में बहुत कम पानी निकलता है, अगर मोघे री–मॉडलिगं किये बिना रहगये और किसान को पूरा पानी नहीं मिला तो यह किसान के साथ न्याय नहीं होगा? क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि मेरे गांव में भी जो एक छोटा मोघा है और जो पूरा पानी नहीं दे

रहा है, उसको री–माडल क्यों नही किया जा रहा, सरकार को ऐसा करने में क्या रूकावट है?

सरदार हरमोन्द्रि सिंह चट्ठाः जब चकबन्दी हुई थी तो उस वक्त ये मोघे ठीक किये गये थे। अगर आनरेबल मैम्बर किसी पार्टिकुलर मोघे की बात करते है कि उसमें पूरा पानी नहीं आता तो उसको एग्जामिन कर लेगें। नारमली अगर एक आदमी चाहे कि मेरा मोघा इधर से उधर ि ाफ्ट कर दें उधर से इधर ि ाफ्ट कर दें, वह हम नहीं करेगें। जो कानून की बात है वह कानून के मुताबिक ही होगी।

मलिक सतराम दास बतराः क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि रबी सीजन में आगुमैंटे ान कैलान से और वैस्टर्न जमना कैलान से कितना–कितना पानी मिला है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः डैफिनिट नहीं कह सकते, लेकिन हम ज्यादातर आगुमैटै ान नहर ही चलाते है। इसमें जितना पानी आता है वह डाइवर्ट कर देते है।

श्री धजा रामः क्या यह हकीकत है कि हांसी ब्रांच और सुन्दर ब्रांच में 1 अप्रैल से 40 परसैट कट लगाई जा रही है, अगर ऐसा है तो इसके क्या कारण है?

सरदार हरमोन्द्रिर सिंह चट्ठाः कोई स्पै ाल कट लगाने की सम्भावना नहीं है और न ही हमने अन्दाजा लगाया है

कि किस वसाईड पर सपै ाल कट लगेगा। जो कपैसिटी फिक्सड है प्वांयट 9 की, उसके मुताबिक पानी देते है।

चौधरी ि ाव राम वर्माः स्पीकर साहब, वैस्टर्न जमना कैनाल को आगुमैंट करने के लिये जो आगुमैंटे ान नहर बनाई गई है, उस में जमीन से पानी निकाल कर डाला जाता है लेकिन जो हमारेपास फालतू पानी बढ़ा है, उसको वैस्टर्न जमना कैनाल सिस्टम में क्यो नहीं डाला जाता और इस तरह से पानी क्यों नही बढ़ाया जाता?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(श्री बनारसी दास गुप्त): आज कल ताजेवाला हैड से जो हमें पानी मिलता है वह 34–35 सौ क्युसिक के करीब है और मुनकपुर में जो पानी पहुंचता है वह 4000क्युसिक के लगभग है। कुल मिलाकर हजार या आठ सौ क्यूसिक पानी मूनकपूर में जाकर, बढ़ जाता है, यह आगुमैंटे ान कैनाल के द्वारा बढ़ा है । हमारे पास इससे ज्यादा साधन नहीं है जिससे ज्यादा पानी बढ़ाया जा सके।

चौधरी चांद रामः जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि जमना पर डैम बनाने के लिए सरकार भारत सरकार से पिछले सात सालों से बातचीत कर रही है। क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि यह बातचीत क्यों मुकम्मल होने में नही आती?

मुख्यमंत्री(चौधरी बंसी लाल): 15–20 साल हो गये है बातचीत करते हुये क्या करें, ये 7 साल से बता रहे है?

श्री अमर सिंहः क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि सुन्दर ब्रांच के हैड पर 64 परसैंट इरीगे ान है और टेल पर 6 या 7 परसैंट? अगर ऐसा है तो इस डिस्पैरिटी को कैसे दूर किया जाए?

श्री बनारसी दास गुप्तः यह प्र न इससे पैदा नहीं होता, आप इसके लिये अलग नोटिस दें।

चौधरी दल सिंहः क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि वैस्टर्न जमना कैनाल के पानी को कितने ग्रुप बनाकर तकसीम किया जा रहा है?

श्री बनारसी दास गुप्तः वैस्टर्न जमनाके दो ग्रुप है – एक दिल्ली ग्रूप और एक हांसी ग्रुप। हांसी ग्रुप की आगें दो ब्रांचे है – एक हांसी ब्रांच , एक सुन्दर ब्रांच। इसी प्रकार दिल्ली ग्रुप में एक भलोट–सब ब्रांच और दिल्ली ब्रांच है।

चौधरी ि ाव राम वर्माः स्पीकर साहब, वैस्टर्न जमना के उपर बांध बनाने की बात थी लेकिन अब वह पुरानी हो गई है। मैं जानना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार की ओर से बांध बनाने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे है।

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, सैन्ट्रल गवर्नमैंट पर इस बात का प्रै ार डालते आये है कि किसाऊ डैम को जल्दी

बनाया जाये लेकिन अब यह डैम किसाऊ में नहीं बन सकेगा क्योंकि अरस्टवाईल पंजाब गवर्नमैंट ने इस में इन्ट्रैस्ट नहीं लिया। पहले जो किसाऊ डैम की साईट थी उसके थोड़ा नीचे यू0पी0 वालों ने हाईड्रोलिक प्लांट बिजली का लगा लिया है और जो पहला किसाऊ डैम था वहां तक कैचमैंट एरिया डैम का हो गया है। अब तो दो चार मील उपर जाएगा, नये सिरे से छानबीन होगी। यह हमारे आने से पहले का है जिस वक्त ये करणधार थे।

चौधरी ि ाव राम वर्मा: क्या मुख्य मंत्री महोदय बतायेगें कि कब तक इसकी आ ाा की जा सकती है कि इस पर काम भाुरू हो जाएगा?

चौधरी बंसी लाल: यह मैं नही बतला सकता।

चौधरी चांद राम: स्पीकर साहब, इन्होने कहा के ये करणधार थे। मैं पूछना चाहता हूं कि जब हरियाणा प्रान्त पंजाब प्रान्त से अलग बना था उस वक्त से लेकर, हरियाणा बनने के बाद चौधरी बंसी लाल ने क्या काम किया है?

Mr. Speaker: Not a supplementary to this question.

चौधरी बंसी लाल: हरियाणा बनने के बाद, मेरे आने के बाद सवा तीन हजार क्यूसिक पानी अपने रिसोर्सिज से ज्यादा एड कर दिया, मैं यह कर दिया।

चौधरी ि िव राम वर्मा: क्या मुख्य मंत्री महोदय तबायेगें कि जो पानी बढ़ा है वह भाायद आगुमैंटे ान ट्यूबवैल्ज लगने से बढ़ा होगा लेकिन इसका जो असर किसानों पर पड़ा है, जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करने के लिए सरकार ने क्या सोचा है?

चौधरी बंसी लाल: पर्टिकुलर ट्युबवैल पर या, पर्टिकुलर किसान पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। कुछ अर्से के बाद जब 10 साल या 20 साल हो जाते है तो पानी थोड़ा बहुत नीचे चला जाता है। फिर जब बारि ा हो जाये तो री–चार्ज हो जाता है।

चौधरी चांद राम: क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि जमना पर डैम बनाने के लिए हरियाणा बनने के बाद सरकार ने क्या काम किया है?

चौधरी बंसी लाल: जब आनरेबल मैंबर जवाब को समझते ही नहीं तो मेरा कोई कसूर नहीं। मैं इसका जवाब क्या दूं?

चौधरी चांद राम: क्या वजीरे सिंचाई बतायेगें कि जो आगुमैंटे ान ट्यूबवैल बन गये है उन की वजह से प्राईवेट ट्यूबवैलों पर जो असर पड़ा है उस को ठीक करने के लिए सरकार ने क्या कदम कठाए है?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्षमहोदय, कई बार हाउस में यह स्पश्ट किया जाचुका है कि आगुमैंटे ान ट्यूबवैल बनने से

प्राईवेट ट्यूबवैलों पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा है, कुछ मामूली ट्यूबवैल है जिन पर थोड़ा बहुत असर पड़ा है। अधिक प्रभाव इस लिये पड़ा है कि कई साल से ड्राई–साइकल चल रही है जिससे जमीन में पानी री–चार्ज नहीं हो रहा।

Mr. Speaker: the hon. Minister had stated this in the House earlier also.

चौधरी चांद रामः जो थोड़ा बहुत असर पड़ा है, उसके बारे में गवर्नमैंट क्या कर रही है?

Mr. Speaker: This has also been replied.

चौधरी चांद रामः एक्सपर्टस की इस बारे में रिपोर्ट है, जब तक वह रिपोर्ट हाउस में डिस्क ान के लिए नहीं आयेगी तब तक सैटिस्फैक ान नहीं हो सकती। इस पर हाफ एन आवर डिस्क न हो सकती है।

Mr. Speaker: When a question has already been replied in this House, how can I allow it to be asked again?

चौधरी राम प्र ाादः क्या मुख्य मंत्री बतायेगें कि 9 महीने की सरकार ने, जब राव बीरेन्द्र सिंह की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौधरी चान्द राम थे, उन्होने 9 महीने में क्या काम किया?

Mr. Speaker: Order please. Not a supplementry to this question.

चौधरी बंसी लालः चौधरी चान्द राम का तो राव बीरेन्द्र सिंह ने अबो र्न कर दिया था चार–साढ़े महीने के बाद ही.....(हंसी)

चौधरी चांद रामः मैं तो तीन महीने रहा और खुद ही निकला था। तीन महीने के बाद खुद ही निकला था। मेरे को इन्वाईट किया गया लेकिन मैं नहीं गया। मैं केवल तीन महीने रहा.....(ाोर)

श्री अमर सिंहः क्या मुख्य मंत्री महोदय बतायेगें कि अबो र्न होस्पिटल में हुआ था या प्राईवेट तौर पर करवाया गया था?

चौधरी बंसी लालः उसके बाद ऐसा हुआ कि राव बीरेन्द्र सिंह गवर्नर के पास गये ओर वहां इस्तीफा दिया। अस्तीफा देकर फिर औथ लेकर आ गये। दोबारा आए तो ये दफ्तर में बैठे कागल निकाल रहे थे.....(हंसी) अबो र्न माल को फौरन ही फैंका जाता है.....(हंसी व भाोर)

Mr. Speaker: Order please.

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, चौधरी चांद राम की तरफ से सप्लीमैंटरी है कि क्या चीफ मिनिस्टर साहब ऐसी बात करेगें?.....(व्यवधान तथा भाोर).....

चौधरी बंसी लालः चौधरी दल सिंह जी अगर अ योरैंस चाहते है तो मैं यह दूंगा नहीं क्योंकि यह समझते है कि चौधरी चान्द राम जी को छोड़कर ये भाग जायें। यह उनकी आपस की बात है, मैं झगड़े में क्यों पड़ूं?

चौधरी चांद रामः मैं छोड़ कर या भाग कर आप के पास तो आ नहीं सकता।

चौधरी बंसी लालः मैंने तो दरवाजे बन्द कर रखे है(हंसी)..... मैं दरवाजे खोलूं तब ये आ सकेगें ऐसे नही..... (हंसी)

Mr. Speaker: No discussion now, Next question please.

Amount spent on Construction of Roads.

***1259. Chaudhri Prabhu Ram:** Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) the year-wise total amount spent on construction of roads during the period from May, 1968, to 31st December, 1974 and

(b) the year-wise total length of the roads, in kilometers constructed during the period as referred to in part (a) above?

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma)

(a)		
1	May 1968 to 3/69	243.00 Lakhs
2	1969-70	579.00 Lakhs
3	1970-71	1200.00 Lakhs
4	1971-72	2200.00 Lakhs
5	1972-73	1080.00 Lakhs
6	1973-74	640.00 Lakhs
7	1974-75(upto 11/74 (figures for 12/74 have not yet been finalised	214.00 Lakhs
	Total	6156.00 Lakhs
(b)		
1	May 1968 to 3/69	350 Kms.
2	1969-70	670 Kms.
3	1970-71	2010 Kms.
4	1971-72	3292 Kms.
5	1972-73	1150 Kms.
6	1973-74	608 Kms.
7	1974-75 upto	140 Kms.

	11/74	
	Total	8420 Kms.

चौधरी चांद रामः क्या वजीर साहब बतायेगें कि अब तक कितने परसैंट गांव रोड्ज से लिंक किये गये है? क्या यह भी बताने की कृपा करेगें कि गवर्नमैंट ने जो सौ फीसदी गांव रोड्ज से लिंक कर देने का दावा किया था उस बीच में क्यों छोड़ दिया गया?

Pandit Chiranji Lal Sharma: Mr. Speaker, Sir, the Government have so far linked about 64% villages in the whole of the State with link roads. The Chief Minister had no doubt made a statement that all the villages will be connected by link roads by 26th January, 1973 but for paucity of funds the progress has been slowed down.

Chief Minister(Chaudhri Bansi Lal): Progress was slowed down at that time not because of paucity of funds but we changed the priority to irrigation and power. We spent Rs. 61.56 crores in about five years on the roads and then the same amount was transferred to irrigation and power side. That was given priority.

चौधरी फूल चन्द(मुलाना): क्या मंी महोदय बतायेगें कि इन सड़को में से कितनी सड़कें ऐसी है जिन पर कलवर्टस नहीं बने और सब गांवों को कब तक रोड्ज से जोड़ दिया जायेगा?

Pandit Chiranji Lal Sharma: So far as connecting of all villages with roads is concerned, it all depends upon availabiltiy of funds and no specific date can be given. So far as construction of culverts is concerned, it is being given priority on roads connected with villages. Regarding the exact number of culverts constructed, this information cannot be given. If the hon. Member is particular, he may give a notice and I will collect the information.

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने अभी बताया है कि 1968 से 1974 तक कितने किलोमीटर लम्बी सड़कें बनी है। क्या वे बताने की कृपा करेंगें कि ऐसी रोड्ज भी उनके नोटिस में है जहां मैटीरियल तो पड़ा हुआ है लेकिन वे अधूरी पड़ी हुई है?

Pandit Chiranji Lal Sharma: There are very many roads all over the State which are incomplete. On some of them only earthwork has been done, on some of them soling has been done while on other partly soling has been done and partly metalling has been done. We do have notice of it and we are trying to consolidate such roads which are lying scattered that way.

चौधरी ि ाव राम वर्माः क्या मंत्री महोदय के इल्म में है कि जोसड़कें इन्होने बनाई हैउनके बीच में कही एक किलोमीटर कहीं आधा किलोमीटर ओर कहीं दो सौ मीटर के गैप्स पड़े है ओर उनकी वजह से लोगों को बड़ी तकलीफ है? क्या वे

बताने की कृपा करेगें कि बीच में जो गैप्स रह गये है उनको बनाने का भीघ्र प्रयत्न करेगें?

Pandit Chiranji Lal Sharma: Certainly, Sir, we have notice of this fact that there are gaps. Some are due to protracted litigation because of writs about acquisition of land. Government will certainly give priority to the construction of such gaps.

चौधरी दल सिंहः क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेगें कि 1969–70 से लेकर आज तक जो–जो सड़कें बनाई गई है, उनको पहले ही कंप्लीट क्यों नहीं किया गया और बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ कर क्यों उनको आगे बनाते गये? क्या कारण है कि बहुत सी सड़कें आज इनकंप्लीट पड़ी है?

Pandit Chiranji Lal Sharma: Mr. Speaker, Sir, there was a crash programme. There was a provision of Rs. 92 crores for the whole of the State. As the Chief Minister has announced we laid stress on water, irrigatiion and power and, therefore, the purpose was left incomplete. These will be completed in due course as and when funds are available.

चौधरी फूल सिंह कटारियाः क्या मिनिस्टर साहब बतायेगें कि जंहा मैटीरियल पड़ा हुआ है और ड्रौट एरिया भी है वहां प्रायरिटी देने का विचार है?

Pandit Chiranji Lal Sharma: I have already submitted that where soling has been done andmaterial is lying we will try to consolidate such roads.

श्री अध्यक्षः इंगिल ा में जवाब देते हो इसलिए उनकी समझ में नहीं आता।

चौधरी चांद रामः क्या वजीर साहब के नोटिस में यह बात है कि कुछ ऐसी जगहें भी है जहां एक सड़क से तो एक प्वायंट से दूसरे प्वायंट का फासला केवल 11 मील का है लेकिन दूसरे पक्के रोड़ से फासला 55 मील का है। एक आध मील के गैप की वजह से यह इतना चक्कर पड़ता है। मिसाल के तौर पर रादौर मुस्तफाबाद को ही ले लें। वह गन्ना प्रोड्यूसिंग एरिया भी है। तो क्या मिनिस्टर साहब उस रोड को पूरा करने की कृपा करेगें?

पंडित चिंरजी लाल भार्माः स्पीकर साहब, आनरेबल मैंबर का क्वै चन जो है वह रादौर मुस्तफाबाद और लाडवा मुस्तफाबाद रोड़ के बारे में है। मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था। वे भाायद उस वक्त त ारीफ नहीं फरमा रहे थे। स्पीकर साहब, यह बात ठीक है कि ऐसी –ऐसी जगहों की जो सड़कें है अगर उन्हे कंप्लीट कर दिया जाये तो खासा रिलीफ लोगों को मिल सकता है लेकिन दिक्कत यह हे कि वे डुप्लीकेट लिंक रोड्ज है। जहां वे एक तरफ एक गांव से एक रोड से कनेक्टिड है। तो ज्यों ही फंडज अवेलेबल होगें ऐसी सड़कों को कंप्लीट करने में हम प्रायरिटी देगे।

चौधरी ि ाव राम वर्मा: क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेगें कि जहां सड़कों पर मिट्टी का काम हो चुका है, पुलियां बन चुकी है , सोलिंग हो चुकी है और मैटिीरियल वहां पड़ा हुआ है, सिर्फ पत्थर उपर डालकर ईंजन चलाना है, ऐसी सड़कों को प्रायरिटी देगें? इसी तरह की एक सड़क किरमच और दूसरी बहनी खुर्द के पास से गई है लेकिन वहां जाकर वह रूक गई है ं। एक लगभग तीन किलोमीटर और दूसरा आधा मील का टुकड़ा है। इसके न बनने से अगले गांव वालों को बड़ी तकलीफ है। क्या मिनिस्टर साहब उसे बनवाने की कृपा करेगें?

पंडित चिंरजी लाल भार्मा: स्पीकर साहब, जिस सड़क पर सोलिंग हुई हो और कंप्लीट स्टोन मैटल पड़ा है, उसको कंसोलिडेट कने में हम प्रायरिटी देंगे। जहां तक बहनी खुर्दवाली रोड का सम्बन्ध है मुझे पता नहीं कि क्यों वह आधे मील का टुकड़ा ना–मुकम्मल पड़ा है। इसका कोई कारण होगा। I will examine it.

श्री ओम प्रका ा गर्ग: क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेगें कि जिन सड़कों के अगेन्सअ मार्किट कमेटी ने , भूगर केन सोसाइटीज ने ओर विलेजर्ज ने अपना भोयर दाखिल किया हो लेकिन सकें कई साल से अधूरी पड़ी हों,उनको प्रायरिटी देंगें?

पंडित चिंरजी लाल भार्मा: स्पीकर साहब, पहले मार्किटिंग कमेटी की सड़कों के लिए स्पै ाल अमांउट ईयरमार्क होता था लेकिन अब वह मार्किटिंग कमेटी का पैसा कंसोलिडेटिड

फंड में चला जाता है। अगर आनरेबल मैंबर किसी स्पैसिफिक रोड के बारे में इन्फार्मे ान चाहते हैजिसके लिए मार्किटिंग कमेटी या भाुगरकेन कमेटी ने पैसा दे रखा हो तो उसके बारे में ये अलग से नोटिस दे दें, I will get the information.

चौधरी मनफूल सिंहः स्पीकर साहब, छूछकवास से झज्जर रोड साढ़े चार मील तो बन चुकी है लेकिन दो अढाई मील के करीब बाकी है ओरयह तीन साल से इसी तरक पड़ी हुई है। क्या मिनिस्टर साहब उसे जन्दी तामीर करवाने की कृपा करेगें?

Pandit Chiranji Lal Sharma: It all depends upon the availability of funds. I am not in a position to give categorical assurances as to when these will be completed.

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, घमाना से तो ाम बाया रतेरा एक ऐसी सड़क हे जो पुरानी बिच्छु रोड़ी से बनी हुई है। बहुत थोड़ा पैसा उस पर खर्च करना पड़ेगा। वह फैमिन एरिया में भी है। क्या मिनिस्टर साहब उसे लज्दी बनवाने की कृपा करेगें?

Pandit Chiranji Lal Sharma: This supplementary does not arise out of this question.

चौधरी चांद रामः मिनिस्टर साहब को यह इल्म है कि यह जो स्टेटेमैंट सी0एम0 की वे बताते है यह सी0एम0 की स्टेटमैंट नहीं थी बल्कि राज्यपाल महोदय के अभिभाशण में और बजट स्पीच में यह बात थी कि 100 परसैंट गांव रोड्ज से लिंक कर दिये जाएंगे। लेकिन बाद में वह प्रायरिटी चेंज कर दी गई।

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रायरिटी तो नहीं बदल जाएगी जैसे कि वह प्रायरिटी बदल गई थी?

Chaudhri Chand Ram: That becomes the decision of the House.

Pandit Chiranji Lal Sharma: No. the Governor's Address does not become the decision of the House. That reflects the policy of the Government which can change depending uon the circumstances.

Mr. Speaker: Next question.

Loans Sanctioned by the Haryana Financial Corporation

***1269. Dewan Hans Raj Suri:** Will the Minister for Industries be pleased to state the number of loans sanctioned by the Haryana Financial Corporation during the years 1973-74 and 1974-75 together with the number of loans which were disbursed?

Industries Minister(Shri Harpal Singh): The information is as under:-

Year	Sanctions		Disbursements		
	No. of Units	Amount Rs.	No. of Units	Amount Rs.	The 319 units in 1973-74 & 231 in 1974-75 fto whom the loans were

					disbursed include partly disbursed cases also where part disbursements were made in the previous year
1973-74	316	64247470	319	35080280	
1974-75 Upto 31-12-74	259	79915267	231	29978720	

चौधरी चांद रामः क्या वजीर साहब बतायेगें कि हरियाणा में जो वित्त निगम है और ऋण देती है, उसमें अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिए कितनी धन राि ा सुरक्षित रखी गयी है ताकि वह भी इन्डस्ट्री के मैदान में आ सकें?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, यह फाइनैन् ाल कारपोरे ान पार्लियामैंट एक्ट के अन्डर बनायी गयी है। उसमें जो रूल्ज है या जो प्रोविजन है, उसके मुताबिक ही देते है।

चौधरी फूल चन्द(मुलाना): क्या वजीर साहब बतायेगें कि फाइनैन्‍ ाल कारपोरे ान बनने के बाद हरिजनों को कितना लोन दिया गया है?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, यहां हाउस में हरिजनों के बारे में बार–बार बात की जाती है। मैं इस बात को साफ करना चाहता हूं कि सारे हाउस में कोई भी मैंबर यह बताये कि किसी हरिजन ने लोन के लिए अप्लाई किया हो ओर उसको प्रैफरैन्स न दिया गया हो। हम प्रैफरेन्स देने के लिए तैयार है। हम चाहते है कि वे इन्डस्ट्री लगायें। कोई भी इनस्टान्स दें कि किसी भी हरिजन ने इन्डस्ट्री के लिए लोन लेना हो और न मिला हो। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, हम भी चाहते है कि इन्डस्ट्री में हरिजनों को भी ले आयें अप–लिफ्ट करे। अभी परसों ही मुख्यमंत्री महोदय ने कहाकि हम हरिजन मैंबरों की एक कमेटी बनाने जा रहे है। वह कमेटी इन सारी बातों को देखेगी। इस कमेटी में हमारे इन्डस्ट्री डिपार्टमैंट के अफसर भी होगे और एम0एल0ए0 भी होगे। जो यह कमेटी रिकमैन्डै ान गवर्नमैंट को देगी, उस पर हम फैसला करेगे।

चौधरी चांद राम: क्या वजीर साहब बतायेगें कि अगर यह कारपोरे ान पार्लियामैंट के एक्ट के मातहत बनी हे तो उस कोई स्पैसिफिक रिजर्वे ान करने में बार है, कांस्टीच्यु ानल बार है?

श्री अध्यक्षः अगर कोई एप्लीके ान आयेगी तो ही लोन दिया जायेगा वे तो 'न' करने के लिए तैयार ही नहीं।

मुख्यमंत्री(चौधरी बंसी लाल): अलाटमैंट करने में फायदा क्या है, वे यह तो बतायें?

चौधरी चांद रामः अगर अलाटमैंट करेगें तो एक दो केस मैं मिलेगा भी।

चौधरी बंसी लालः अभी आनरेबल मिनिस्टर ने एक बात कह दी कि किसी भी हरिजन ने एप्लाई नहीं किया। एप्लाई करेगा तो उसे प्रैफरेन्स देगें। अलाटमैंट करना ओर न करने के माने क्या है, इससवाल के पूछने के माने क्या है, मैं यही नहीं समझा।

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब यहां वे वैसे ही भाोर मचा रहे है।सारी स्टेट में कोई भी कम्पलैन्ट नहीं है कि किसी के साथ ठीक ट्रीटमैंट न हुआ हों।

चौधरी दल सिंहः क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि सन् 1973–74 में और सनृ 1974–75 में कौन–सी यूनिट को सबसे ज्यादा लोन दिया गया?

श्री हरपाल सिंहः इस वक्त मैं नहीं बता सकता लेकिन मैंबर साहबान को इतना जरूर बताना चाहता हूं कि हमारी कारपोरे ान ने जितना अच्छा काम किया है उतना अच्छा भाायद ही किसी स्टेट की कारपोरे ान ने किया हों यह कारपोरे ान सन

1967 में बनायी गई थी। इस साल जो हमें प्रोफिट हुआ वह 1591957 रूपये हुआ। सन 1968–69 में 17 लाख 82 हजार 827 रूपये का हुआ। सन 1969–70 में 2137005 रूपये का हुआ। सन 1970–71 में 2025225 रूपये के करीब हुआ। सन 1971–72 में 2320332 रूपये हुआ। सन 1972–73 में 2722835 रूपये हुआ और सन 1973–74 में 4077493 रूपये हुआ।

चौधरी बंसी लालः एक एडी ानल बात ओर बतांऊ। कई सालों से इस कार्पोरे ान का मैंनेजिंग–डायरैक्टर भी हरिजन है।

चौधरी ि ाव राम वर्माः अभी मंत्री महोदय ने कहा कि हम हरिजनों को उद्योगों की तरफ ले जाना चाहते हैं तो मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हरिजनों को उद्योगों की तरफ ले जाने के लिए,उनका उधर ध्यान खीचनें के लिए उन्हे क्या–क्या आकर्शण दे रहे है?

श्री अध्यक्षः अभी–अभी उन्होने कहा था कि कमेटी बनायी जायेगी। उसमें एम0एल0ए0 और इन्डस्ट्री डिर्पामैंट के अफसर भी होगें। वह कमेटी डिपार्टमैंट को रिकमैंडे न करेगी।

श्री ओम प्रका ा गर्गः क्या मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेगें कि हरियाणा में जो इन्डस्ट्री का बढ़ावा हुआ है, इसमें फाइनैन्ा ाल कारपोरे ान का कितना हाथ है?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, हरियाणा फाइनैन ाल कारपोरे ान में गवर्नमैंट का सिर्फ 66 लाख 51 हजार रूपये का भोयर है बाकी पैसा फाइनैं ाल इन्स्टीच्यु ानज से लोन लेती है। अब तक कोई 15 करोड 77 लाख 23 हजार 980 रूपये इन्डस्ट्रीयल यूनिट लगाने के लिए लोन दिया गया है।

चौधरी दल सिंहः क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि जो फाइनैं ाल कारपोरे ान सैन्ट्रल ऐजेन्सी से लोन लेती है, उसका सूद क्या है और जो फाइनैन ाल कारपोरे ान देती है,उसका सूद क्या है?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब,उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फाइनैन ाल कारपोरे ान बैकवर्ड एरियाज में नौ परसेन्ट पर दे रही है ओर दूसरे एरियाज में 11 परसैन्ट पर पैसा दे रही है। नौ परसैन्ट से 11 परसैन्ट पर पैसा दे रही है।

श्री हरि सिंहः क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि रोहतक में जो चमड़े की फैक्टरी चौधरी चांद राम जी ने लगवाई हुई है वह बन्द क्यों पड़ी है? वह लोन कंहा से लिया गया है?.....(हंसी)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अमर सिंहः क्या मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेगें कि किसी इनडस्ट्रीयल यूनिट को लोन सैक ान करने का क्या काइटेरिया है?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, पहले एप्लाई करना पड़ता है।जहां पर उसने इन्डस्ट्री लगानी हो, वह बताकर उसको फाइनैन्स ाल कारपोरे ान को एप्लाई करना पड़ता है। कारपोरे ान के टैक्नीकल आदमी चैक करते है कि क्या यह जो स्कीम है यह ठीक है, इसकी वायबिलटी है या नहीं। दूसरे यह भी देखते है कि जमीन का टाइटल क्लीयर है या नहीं । ये सब बातें देख कर लोन देते है।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब पहली बात तो यह है कि मैंने कोई लोन नहीं लिया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि वित्त निगम ने जो लोन दिया है उसमें ऐसे केसिज कितने है जो डिफाल्टर हो गये हों, जिन का लोन वापिस नहीं हो सकता हा?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, यह खु ाी की बात है कि कोई भी हमारा बैड डैट नहीं है। सारा कर्जा वापिस हो रहा हैं।

Hospitals in the State

***1277. Shri Jagjit Singh Tikka:** Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) the totalnumber ofmobile hospitals in the state togetherwith the number of allopathic and Ayurvedic Hospitals, searately out of them. and

(b) the number of other hospitals besides the special dental clinics in the state where the sevices of Dental specialists are available?

गृह एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री(श्रीमती भाारदा रानी): (क) राज्य में केवल एक ही चलता फिरता ऐलोपैथिक हस्पताल है।

(ख) अलग से कोई भी वि ोश सरकारी डैन्टल क्लीनिक्स स्थित नहीं है। ये हस्पतालों के ही अंग है। ऐसी क्लीनिक्स 37 सरकारी हस्पतालों में स्थित है।

श्री जगजीत सिंह टिक्का: क्या मंत्री महोदया यह बताने का कश्ट करेगी कि मोरनी हिल्ज में जो पहले मोबाइल डिस्पैंसरी चालू करने की स्कीम थी, वह कब तक चालू हो जायेगी?

श्रीमती भाारदा रानी: अध्यक्ष महोदय, मोरनी हिल्ज में बड़ी अच्छी स्थिर डिस्पैंसरी बन गयी है। अब वहां पर मोबाइल डिस्पैंसरी बनाने की कोई योजना नहीं है।

चौधरी दल सिंह: क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेगी कि सन 1975–76 के साल में कितनी आयुर्वेदिक ओर कितनी एलोपैथिक डिस्पैंसरीयां खोलने का विचार है?

श्रीमती भाारदा रानी: कोई भी नही।

चौधरी पीर चन्द: मेरे हल्के में हसनगढ़ गांव है वहां पर हस्पताल की बिल्डिग भी है, क्या वहां पर डिस्पैंसरी खोलने का विचार है?

श्रीमती भारदा रानीः अध्यक्ष महोदय, यह क्वै चन मोबाइल हास्पिटल और डैन्टल क्लीनिक से ताल्लुक रखता है। इन दानेां के बारे में कोई भी चीज पूछं लें।

चौधरी दल सिंहः क्या मंत्री महोदया यह बताने का कश्ट करेगीं कि जीन्द में डैंटल सर्जन कई महीनों से क्यों नही है? क्या वहां पर डाक्टर भेजने की तजवीज है ओर अगर है तो कब तक है?

श्रीमती भारदा रानीः हमारी सूचना तो यह है कि जीन्द में डैन्टल सर्जन है।

चौधरी दल सिंहः सूचना गलत है।

श्रीमती भारदा रानीः वह छुट्टी चला गया होगा!..... (हंसी)

चौधरी फूल सिंह कटारियाः क्या मंत्री महोदया यह बताने का कश्ट करेंगी कि झज्जर में डैन्टल सर्जन नहीं है, वहां पर कब तक भेजन का विचार है?

श्रीमती भारदा रानीः झज्जर में डैन्टल सरजन नहीं है यह हमारे नोटिस में है। वहां जल्दी ही भिजवानें की कोि ा ा करेगें।

श्री ओम प्रका ा गर्गः क्या मंत्री कहोदया यह फरमायेगी कि अगर जींद में कोई डैन्टल सर्जन नहीं है तो चौधरी

दल सिंह जी के दांत किसी और जगह कढ़वा दिये जायेगें? ..... (हंसी).....

श्रीमती भारदा रानीः हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज पर बहुत से ऐसे हास्पिटलज है जहां पर दांत निलवाने का इन्तजाम है। 37 हास्पिटल्ज में ऐसा प्रबन्ध है। उनमें से किसी में भी चौधरी दल सिंह दांत निकलवा सकते है।

चौधरी ि ाव राम वर्माः क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि जो चलता फिरता ऐलापैथिक हस्पताल है, उसमें डैन्टल क्लीनिक भी जोड़ दिया जायेगा?

श्रीमती भारदा रानीः अध्यक्ष महोदय, यह जो क्वै चन था, यह चलते–फिरते अस्पताल के बारे में था। एक चलते–फिरते अस्पताल के अलावा हमारे पास तीन चलती–फिरती डिस्पैंसरियां भी है। लेकिन न ही चलते फिरते अस्पताल में और न ही इन चलती–फिरती डिस्पैंसरियों में डैंटल क्लीनिक है। .....(व्यवधान व भाोर).....

श्री अमर सिंहः क्या आनरेबल मिनिस्टर साहिबा यह बतायेगीं कि 31 दिसम्बर, 1974 तक इस मोबाइल हास्पिटल में कितने पे ैन्ट्स का इलाज किया गया?

श्रीमती भारदा रानीः अध्यक्ष महोदय, मोबाइल हास्पिटल के तो कैम्पस लगते है। मोबाइल डिस्पैंसरियों में कितने पे ैन्ट्स आये, यह फिगर्ज मेरे पास है। कैम्पस में कितने मरीजों का इलाज

हुआ, यह सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन मोबाइल हास्पिटल की ओर से बहुत ज्यादा कैम्प लगाये गये है।

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, इन कैंम्पों में 30–31 हजार पे ोन्ट्स हरेक कैम्प में आये है। किसी एक आध मे कम या ज्यादा हो सकते है वरना इन कैम्पस में 30 ओर 32 हजार पे ौन्टस की रेंज रही है।

Smoking and Taking of tea in government Offices and Schools

***1132. Shri K.N. Gulati:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to prohibit smoking and taking of tea in Government offices and schools in the State during their working hours; and

(b) if so, the time by which it is likely to be implemented?

Chief Minister (Chaudhri Bansi Lal):

(a) Smoking is already prohibited in schools in the State during working hours. There is, however, no proposal under consideration of the government to prohibit taking of tea in the deration of the Government to prohibit taking of tea in the offices of the Government and schools in the state during working hours.

(b) In view of (a) above, the question does not arise.

चौधरी ि ाव राम वर्मा: मुख्य मंत्री महोदय यह बतायेगें कि कम से कम स्कूलों में क्या वे हुक्का, बीड़ी या सिगरेट रोकने पर विचार करेगें?

चौधरी बंसी लाल: इसका तो मैंने पहले ही जवाब दे दिया है कि स्कूलों में स्मोकिंग प्रोहिबिटिड है।

श्री के0एन0गुलाटी0: स्पीकर साहब, इसमें भाक नहीं कि दफ्तरों में काम सैटिसफैक्टरी होता है लेकिन दफतरों के अन्दर जयादा प्रोग्रैसिव काम चलाने के लिये क्या वे इस बात पर विचार करेगें? इससे ऐम्पलाईज का अन–नेसैसरी पैसा जाया होता है जब वे किसी को चाय पिलाते है या सिगरेट पे ा करते है। जब मिनिस्टरों के पास लोग जाते है तो वे भी चाय पिलाते है। इसलिये मिनिस्टरों का ओर ऐम्पलाईज का पैसा बचाने के लिये ओर दफतरों का और ज्यादा प्रोग्रैसिव काम चलाने के लिये अगरअब तक कोई ऐसी पाबन्दी नहीं है तो आईन्दा के लिये इस पर विचार करेगें?

चौधरी बंसी लाल: स्पीकर साहब, अगर ऐम्पलाईज अपना पैसा बचाना चाहते है तो चाय न पीयें। जबरदस्ती तो उनको कोई पिलाता नही है।

Possesion of Residential Plots

***1213. Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Social Welfare and Taxation be pleased to state-

(a) whether the possession of residential plots has been given in secto 19 and 21 at Faridabad to those persons who have paid full amount for the same; and

(b) if not, the reasons, therefor together with the time by which the possession is likely to be given to them?

Social Welfare and Taxation Minister (Shri Shyam Chand):

(a) No.

(b) The possession of the plots could not be given because the demarcation work is still in hand. It will be given soon after completion of demarcation.

चौधरी राम लाल वधवा: मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगें कि क्या यह बात ठीक हे कि लोगों से पैसे लिये हुये तीन–तीन साल हो गये है लेकिन उन्हे अब तक प्लाटस का कब्जा नहीं दिया गया? ये मिडल क्लास के लोग है जिन्होने पैसे भरे हुये है, इस बात को देखते हुये इनको कब तक पोजै ान दे देगें?

श्री भयाम चन्द: स्पीकर साहब, जिन लोगों की जमीन थी , वे लोग हाई–कोर्ट गये हुये है। अभी कई केसिज में फैसला नहीं हुआ है। वहां से फैसला होने के बाद दे देगें।

***1215. Chaudhri Dal Singh:** Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state-

(a) whether the lining work of Sunder Sub-Branch has been started;

(b) if so, whether Gau Ghats for the cattle have been constructed at appropriate places; and

(c) the number and names of places where the 'Ghats' as referred to in part(b) above have been constructed?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha):

(a) Yes, in reach at RDO-16137.

(b) Not yet.

(c) Question does not arise in view of (b) above.

Karnal Co-operative Sugar Mill

***1228. Chaudhri Shiv Ram Verma:** Will the minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether the construction of Karnal Co-operative Sugar Mill has been started;

(b) if so, since when togetherwith the progress made in the said work;

(c) the time by which the machinery of the said mill is likely to be set up;

(d) the total estimated expenditure that is likely to be incurred on this mill till it starts working to its full capacity; and

(e) whether the arrangement to provide the said amount has been made?

सहकारिता एवं स्थानीय प्र ाासन राज्य मंत्री (चौधरी गोवर्धन दास चौहान):

(ए) हां।

(बी) 21 नवम्बर, 1974 से। जहां तक प्रगति का सम्बन्ध है विवरण विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत है।

(सी) सप्लायर्ज के साथ एग्रीमैंट अनुसार चीनी मिल 30 नवम्बर, 1976 तक पूर्ण हो जायेगी।

(डी) लगभग 525 लाख रूपये।

(ई) प्रबन्ध किया जा रहा है।

विवर्णिका

अभी तक निर्माण कार्य में निम्नलिखित प्रगति हुई है:—

1. जनरल स्टोर ओर वर्क ाप की खुदाई का कार्य पूर्ण हो गया है।

2. जनरल स्टारे और वर्क ाप की बुनियाद में चूने का मसाला पूरा हो गया है।

3. चीनी गोडाउन के कालम की खुदाई पूर्ण हो गई है।

4. चीनी गोडाउन की बुनियाद में चूने का मसाला पूर्ण हो गया है।

5. जनरल स्टोर की बुनियाद ओर नींव का ईंटों का कार्य पूर्ण हो गया है।

6. फैक्टरी बिल्डिंग की नींव की खुदाई आरम्भ हो चुकी है।

चौधरी ि ाव राम वर्माः मंत्री महोदय ने यह कहा है कि रूपये का प्रबन्ध किया जा रहा है, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगें कि कब तक रूपये का प्रबन्ध हो जायेगा?

चौधरी गोवर्धन दास चौहानः यह जल्दी ही हो जायेगा।

चौधरी ि ाव राम वर्माः जल्दी का मतलब समझा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा? .....(व्यवधान).....

Chief Minister(Chaudhri Bansi Lal):- As soon as possible.

चौधरी ि ाव राम वर्मा: जल्दी का मतलब तो स्पश्ट कर दे?

चौधरी बंसी लाल: क्या ऐज सून एज पौसीबल से भी जल्दी (चीनी मिल) बनवाना चाहते है?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री(श्री बनारसी दास गुप्त): अध्यक्ष महोदय, फाइनैंि ायल कारपोरे ान आफ इंडिया से हमारा लोन सैक ान हो चुका है और आज से कोई तीन–चार दिन पहले ही हमें स्वीकृति की चिट्ठी मिली है। इसलिये बहुत जल्दी ही पैसे का प्रबन्ध हो जायेगा।

चौधरी ि ाव राम वर्मा: स्पीकर साहब, जवाब में यह बताया गया है कि इस मिल पर 525 लाख रूपये खर्च होगा, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगें कि यह मिल कितना गन्ना रोज पीड़ेगी और कितनी चीनी रोज तैयार होगी?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, मेरे पास दोनों मिलों की अलग–अलग केपैसिटी है। करनाल की 1400 टन प्रतिदिन और सोनीपत की 1200 टन प्रतिदिन कैपेसिटी होगी।

चौधरी चांद राम: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगें कि मिल लगाने के लिये जो म ाीनरी खरीदनी है, वह खरीदी जा चुकी है और अगर खरीदी जा चुकी है तो कहां से खरीदी गयी है?

चौधरी चांद रामः यह म ीनरी कौन सी है?

श्री बनारसी दास गुप्तः इन्डीजीनियस म ीनरी है और गवर्नमैंट आफ इंडिया के पब्लिक सैक्टर में है।

चौधरी पीर चन्दः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगें कि जब दोनो मिलों के चलने से चीनी भी बहुत ज्यादा पैदा होगी तो चीनी का रेट भी कुछ कम किया जायेगा?

श्री बनारसी दास गुप्तः चीनी का भाव तो गवर्नमैंट आफ इंडिया तय करती है।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, जींद के आस–पास मीठा पानी है, वहां पर कई हजार ट्यूबवैल लगे हुये है और साथ ही वैस्टर्न जमुना का पानी भी लगता है, क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये सरकार जींद के अन्दर जो एक डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर भी है, कोई कोआप्रेटिव भ्गर मिल लगाने के लिये विचार रखती है। अगर रखती है तो कब तक लगा देगें?

श्री बनारसी दास गुप्तः फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है। इन दोनों मिलों के बाद हमने पलवल में एक मिल लगाने के लिये ऐप्लाई किया हुआ है। उसके बाद फिर दूसरी जगहों के लिये सोचेगें।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगें कि म ीनरी खरीदते वक्त इस बात का ध्यान

रखा गया है कि प्राइवेट फर्मो में इससे भी सस्ती म ीनरी मिलती है?

श्री बनारसी दास गुप्तः अध्यक्ष महोदय, इसके लिये बाकायदा टैन्डर इन्वाईट किये गये थे और जिसने लोऐस्ट टैन्डर कोट किया, उससे यह म ीनरी खरीदी जा रही है।

चौधरी चांद रामः इस बात को ध्यान में रखते हूये कि चीनी बैस्ट आईटम फार ऐक्सपोर्ट है और फारेन ऐक्सचेंज कमाती है, न केवल पलवल में बल्कि कुरूक्षेत्र में और हरियाणा के दूसरे ऐसे इलाकों में जहां पर गन्ना उत्पन्न होता है, मिल लगायी जायेगी? क्या ऐसी किसी तजवीज पर विचार करेगें?

श्री बनारसी दास गुप्तः जैसे मैंने अभी निवेदन किया है कि फिलहाल तो तीसरी मिल पलवल में लगाने का विचार है। उसके बाद देखेगें और जैसी आव यकता होगी, उसके लिये कार्यवाही करेंगें।

Amount Sanctioned to the Director, Public Instruction for furniture and library books etc.

***1236. Shri Amar Singh:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) the total amount sactioned by the Government to the Director Public Instruction for articles of furniture, library, art and craftrs etc. year-wise from 1972 to date;

(b) the criteria, if any, adopted by the D.P.I. to purchase furniture, library books and sttionery;

(c) whether any complaint was received by the Government regarding the purchase mentioned in part (a) above, if so, a copy of the complaint be laid on the Table of the House; and

(d) the district-wise total amount spent by the D.P.I. on furniture, exercise books?

ि ाक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री(रीमती प्रसन्नी देवी):

(क) एक विवर्णिका सदन की टेबल पर प्रस्तुत है जिसमें वांछित जानकारी दी हुई है।

(ख) जब तक ि ाकायत बारे पूर्ण ब्यौरा न दिया जाये, ि ाकायत की प्रति विधान सभा में प्रस्तुत नहीं की जा सकती है।

(ग) सरकार द्वारा अभ्यास पुस्तकों की खरीद पर कोई रा ि ा खर्च नहीं की जाती है जिला–वाईज फर्नीचर की खरीद पर व्यय की गई रा ि ा का ब्यौरा एकत्र करने काफी समय तथा परिश्रम लगेगा और इससे कोई वि ोश लाभ भी न होगा।

विवर्णिका

क.	वर्श	कन्टीजैन्सी	फर्नीचर	लाईब्रेरी पुस्तकें	आर्ट तथा क्राफ्ट मैटीरियल

	1972–73	12.11	10.73	7.06	2.02
	1973–74	12.74	7.59	5.31	3.07
	1974–75	22.33	6.68	2.54	3.02

(ख) फर्नीचर की खरीद

जैसा कि पंजाब वित्त नियमावली वाल्यूम–II के परिि ाश्ट 14 तथा 17 में निर्दिश्ट है, फर्नीचर की खरीद के लिए निम्मनलिखित सूत्रों को प्राथमिकता दी है:–

1. जेल।

2. राजकीय उद्योगिक प्रि ाक्षण केन्द्रों, राजकीय देहाती कला प्रि ाक्षण केन्द्रों।

3. रेट कन्ट्रैक्ट फर्म।

4. नियंत्रक भण्डार, हरियाणा (केवल छोटी–छोटी खरीद को छोड़कर)

5. उपरोक्त चारों स्त्रोतों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर स्थानीय खरीद।

6. विभिन्न–2 विभागीय कमेंटियों के माध्यम से।

पुस्तकों की खरीद

1. विद्यालय की लाईब्रेरी के लिए पुस्तकें

सामान्यतः इस विभाग द्वारा अनुमोदित पुस्तकें निदे ाालय स्तर पर सरकार द्वारा बताई गई बल्कि खरीद समिति के माध्यम से ही खरीदी जाती है।

2. जिला लाईब्रेरी

पुस्तकों की खरीद जिला लाईब्रेरी कमेटी द्वारा की जाती है। जिसमें प्रधान उपायुक्त होते है।

3. महाविद्यालय लाईब्रेरी

विभिन्न विशयों के मुख्यों की फिारि ा के आधार पर पुस्तकें प्राचार्यों द्वारा कोटे ान मंगवा कर खरीदी जाती है।

4. स्टे ानरी वस्तुओं की खरीद

स्टे ानरी वस्तुओं की खरीद नियन्त्रक लेखन तथा सामग्री विभाग द्वारा की जाती है। और फिर इसकी सप्लाई विभागों को की जाती है।

श्री अमर सिंहः आनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने अपने जवाब में बताया है कि 1972–73 में 10.73, 1973–74 में 7.59 लाख और 1974–75 में 6.68 लाख रूपये का फर्नीचर खरीद गया है और पार्ट 'बी' में यह भी बताया है कि जेल्ज, गवर्नमैंट इंस्डिट्रयल ट्रेंनिग इन्स्टीच्यू ान्ज , फर्म्ज, कन्ट्रोलर आफ स्टोर्ज,

लोकल परचेल और थरू परचेल कमेटीज स्पै ीयली कांस्टीच्युटिड बाई दी डिपार्टमैंट से फर्नीचर परचेज किया गया है। क्या आनरेबल मिनिस्टर साहिबा यह बतायेगी इसकी ब्रेक–अप क्या है यानी कितना फर्नीचर जेल्ज से, कितना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीच्यु ान्ज से और कितना थरू परचेज कमेटीज (स्पै ाली कांस्टीच्यूटिड बाई दी डिपार्टमैंट) द्वारा परचेज किया गया है?

ि ाक्षा मंत्री (श्री माडू सिंह मलिक): स्पीकर साहब, इसकी अलग–अलग फिगर्ज तो नहीं दी जा सकती लेकिन मैं यह बता दूमं कि लोकल परचेज तब करते है जब हमें तीनों जगह से नान–अवेलेबिलिटी सर्टीफिकेट आ जायें कि हमारे पास फर्नीचर नहीं है।

चौधरी ि ाव राम वर्मा: मंत्री महोदया ने 'डी' के जवाब में बताया है कि जो परिश्रम लगेगा उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि परिश्रम से तो स्वास्थ्य अच्छा बनता है, वे परिश्रम से क्यों घबराती है? (हंसी)

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

Mr. Speaker: Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन के पटल पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Buses with the Haryana Roadways

***1260. Chaudhri Prabhu Ram:** Will the Minister for Development be pleased to state:-

(a) the total number of buses with the Haryana Roadways in the month of May, 1968 togetherwith the increase made therein upto the 31st December, 1974; and

(b) the percentage of increase made during the said period in the distance covered daily by the Haryana Raodways togetherwith the length of the distance as it was in the year 1968 and as it rose in the year 1974, separately?

विकास मंत्री (कर्नल महा सिंह):

(क) मई, 1968 में हरियाणा राज्य परिवहन में बसों की संख्या 590 थी। 31 दिसम्बर, 1974 तक 1018 बसें और बढ़ाई गई।

(ख) मध्यमान प्रतिदिन तय की गई दूरी जो 1968 में 1.24 लाख किलोमीटर थी, से बढ़कर 1974 में 3.83 लाख किलोमीटर हो गई। यह वृद्धि 209 प्रति ात है।

Financial Aid under the State Aid to Industries Act

***1270. Dewan Hans Raj Suri:** Will the Minister for Industries be pleased to state:-

(a) the number of units to which financial aid has been given during the year 1974&75 under the State Aid to

Industries Act together with then number of such units five years ago; and

(b) the comparative figures of the amount of aid disbursed under the said Act for the years 1968 and 1974.

उद्योग मंत्री (श्री हरपाल सिंह) :

	वर्श	इकाईयों की संख्या
(क)	1974–75 (वित्तीय वर्श) 1969–70 (वित्तीय वर्श)	अब तक भ्ाुन्य 734
(ख)	–1968 (1–1–1968 से 31–12–1968 तक) –1974(1–1–1974 से 31–3–1974 तक)	रू0 2308150 रू0 2935550

X-Ray Facilities in Hospitals

***1278. Shri Jagjit Singh Tikka:** Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) the number of hospitals in the State where X-Ray facilities are available at present and whether there is any scheme under consideration of the Government to extend the same;

(b) if so, the time by which and the names of hospitals to which this facility is expected to the extended together with the district-wise names of hospitals where this facility is available so far; and

(c) whether the X-Ray facilities were available at the time of the formation of the State; if so, the names of the hospitals where it was available?

उद्योग मंत्री(श्री हरपाल सिंह):

(ए) 1.	सिविल हस्पताल	42
2.	ई.एस.आई. हस्पताल	3
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	12
4.	औशधालय	2
5.	टी.बी. क्लीनिक	6

2. लेकिन जब कभी और जहां कही एक्सरे सुविधा को बढ़ाने की आव यकता होगी, एक्सरे म ीन दे दी जायेगी।

(बी) कोई निर्धारित समय नहीं दिया जा सकता।

विवरणी जिन स्थानों में एक्सरे की सुविधायें दी गई है सदन के पटल पर रखी जाती है।

(सी) हां, यह केवल 17 स्थानों पर उपलब्ध थी।

इन स्थानों की विवरणी जाहं पर एक्सरे सुविधायें उपलब्ध थी, सदन के पटल पर रखी जाती है।

ANNEXURE "A"

List of Institutions where X-Ray facilities are available in Haryana Hissar District

1. Civil Hospital, Hissar.
2. T.B. Hospital, Hissar.
3. Civil Hospital, Hansi.
4. Civil Hospital, Sirsa.
5. Civil Hospital, Tohana.
6. Civil Hospital, Dabwali.
7. Civil Hospital, Adampur.
8. Civil Hospital, Fatehabad.
9. Primary Health Centre, Odhan.
10. Primay Health Centre, Barwala.

Rohtak District

11. Civil Hospital, Rohtak.

12. T.B. Clinic, Rohtak.

13. Civil Hospital, Jhajjar.

14. Civil Hospital, Bahadurgarh.

Gurgaon District

15. Civil Hospital, Gurgaon.

16. Civil Hospital, Palwal.

17. Civil Dispensary, Hodel.

18. Civil Hospital, Ferozepur Jhirka.

19. Civil Hospital, Nuh.

20. T.B. Clinic, Gurgaon.

21. Primary Health Centre, Pataudi.

22. B.K. Hospital, Faridabad.

23. Primary Health Centre, Ballabgarh.

24. E.S.I. Hospital, Faridabad.

District Karnal

25. Civil Hospital, Karnal.

26. T.B. Clinic, Karnal.

27. Civil Hospital, Panipat.

28. P.H.C., Nilokheri.

29. E.S.I. Hospital, Panipat.

District Ambala

30. Civil Hospital, Ambala.

31. T.B. Hospital, Ambala City.

32. Civil Hospital, Jagadhri.

33. Civil Hospital, Kalka.

34. Civil Hospital, Naraingarh.

35. Civil Hospital, Yamuna Nagar.

36. P.H.C. , Sadhaura.

37. P.H.C., Rai Pur Rani.

38. Civil Hospital, Ambala Cantt.

39. E.S.I. Hospital, Yamuna Nagar.

District Narnaul

40. Civil Hospital, Narnaul

41. T.B. Clinic, Narnaul.

42. Civil Hospital, Mohindergarh.

43. Civil Hospital, Rewari.

44. P.H.C., Kanina.

45. P.H.C. , Bawal.

District Bhiwani

46. Civil Hospital, Bhiwani.

47. Civil Hospital, Loharu.

48. Civil Hospital, Tosham.

49. Civil Hospital, Dadri.

50. Mobile Dispensary, Bhiwani.

District Kurukshetra

51. Referral Hospital, Kurukshetra.

52. Civil Hospital, Kaithal.

53. Civil Hospital, Shahabad.

District Sonepat

54. Civil Hospital, Sonepat.

55. Civil Hospital, Gohana.

56. P.H.C., Ganaur.

District Jind

57. Civil Hospital, Jind.

58. Civil Hospital, Narwana.

59. Civil Hospital, Safidon.

60. P.H.C., Julana.

61. T.B. Clinic, Jind.

Medical College, Rohtak & attached Hospital with M.C. Rohtak

62. Medical College Hospital, Rohtak.

63. Civil Hospital, Beri.

64. Primary Health Centre, Dighal.

65. C.R. Mobile Hospital.

ANNEXURE "B"

Name of the Hospitals where X-Ray facilities were available at the time of the formation of the Haryana State (1-11-1966)

Hissar District

1. Civil Hospital, Hissar.

2. T.B. Hospital, Hissar.

3. Civil Hospital, Sirsa.

Rohtak District

4. Civil Hospital, Rohtak.

5. Civil Hospital, Bahadurgarh.

Gurgaon District

6. Civil Hospital, Gurgaon.

7. B.K. Hospital, Faridabad.

Ambala District

8. Civil Hospital, Ambala.

9. Civil Hospital, Naraingarh.

10. Civil Hospital, Jagadhri.

Jind District

11. Civil Hospital, Jind.

Bhiwani District

12. Civil Hospital, Bhiwani.

Kurukshetra District

13. Civil Hospital, Kurukshetra.

Sonepat District

14. Civil Hospital, Sonepat.

Karnal District

15. Civil Hospital, Karnal.

16. Civil Hospital, Panipat.

17. Medical College Hospital, Rohtak.

कार्य–मंत्रणा समिति का छठा प्रतिवेदन

Mr. Speaker: I have to report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various items of business.

15—00 बजे

"The Committee met in the Chamber of the Speaker on Tuesday, the 14th January, 1975, at 3.30 P.M.

The Committee, after some discussion, recommended that the business on the 15th and 16th January, 1975, be transacted as follows-

15th January, 1975 at 2.00 P.M.

1. Questions Hour.

2. Sixth Report of the Business Advisory Committee.

3. Motion regarding extension of term of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes upto 31st March, 1976.

4. The Haryana Appropiation Bill, 1975 on Budge (2 Hours).

5. Discussion and Voting on Supplementary Estimates (Third Instalment) for the year 1974-75.

6. Discussion and voting on Excess Demands over Grants for the year 1969-70.

16th January, 1975 at 2.00 P.M.

1. Questions Hour.

2. Private Members Business.

Home Minister (Shri K.L. Poswal): Sir, I beg to move-

that this Houses agrees with the recommendations contained in the Sixth Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker: Motion moved-

that this Houses agrees with the recommendations contained in the Sixth Report of the Business Advisory Committee.

चौधरी चांद राम(बबैन–अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस हाउस की मौजूदा सिंटिग के बाद यह छठी रिपोर्ट है जो हमारे सामने है। गवर्नमैंट को अख्तियार है जिस वक्त भी चाहे प्रोग्राम फिक्स कर सकती है लेकिन इसे बिट्स में लाना, कभी एक–दो दिन का कर लिया फिर एक–दो दिन का प्रोग्राम बना लिया, कभी हाउस दो बजे बैठेगा, कभी हाउस साढ़े नौ बजे बैठेगा, कभी हमारे रूल्ज बदले जाते है ओर कहा जाता है कि स्पीकर की मर्जी से यह रूल चेंज किया जाता है, स्पीकर साहब, मैंबर साहिबान को इससे बड़ी तकलीफ होती है। जैसा कि पार्लियामैंट में होता है, उनका इकट्ठा प्रोग्राम बन जाता है जिससे मैंबर्ज को पता होता है कि किस दिन हाउस कितने बजे बैठेगा, अगर यह हो जाए तो सदस्यों को काफी सुविधा रहेगी।

मुख्य मंत्री(चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, सिर्फ एक दिन टाइम बदला है ओर उस दिन भी बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में चौधरी दल सिंह, चौधरी ि ाव राम वर्मा, चौधरी मनफूल सिंह भाामिल थे ओर इनकी सलाह से बदला गया था।

चौधरी चांद रामः सब यह कहते है कि वहां पर हम जो कहते है, हमारी बात मानी नंहीं जाती।

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, अगर वे यह कहते है कि जो हम कहते है हमारी बात नहीं मानी जाती तो यहां पर चौधरी ि ाव राम वर्मा, चौधरी दल सिंह, राव दलीप सिंह, चौधरी मनफूल सिंह बैठे है कोई खड़ा होकर कह दे कि इन्होनें कोई बात कही हो और वह बात मानी नहीं गई हो।

चौधरी मनफूल सिंहः स्पीकर साहब, टाईम की बाबत इत्तेफाक राय से फैसला होता है।

चौधरी दल सिंहः टाईम की पाबन्दी की बाबत मैंने कहा था।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, मैं कोई गलत बात नहीं कहता। चोधरी हरद्वारी लाल के खिलाफ जिस दिन मो ान मुव हुई थी उस दिन भी मैंने कहा था।

श्री अध्यक्षः आपने जो प्वायंट उठाया है, आप उसी पर बोले।

चौधरी चांद रामः स्पकर साहब, मैं खुद ही आपके जजबात का ख्याल रखता हूं। लेकिन स्पीकर साहब, अगर पूरे सै ान का प्रोग्राम एक ही बार आ जाये तो कितना अच्छा रहे। मैंबरों को भी इसमें सुविधा रहेगी। अब तो यह होता है कि पहले दो दिन का बिजनैस तय कर लिया, दो दिन के बाद फिर बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुला ली और फिर दो दिन का बिजनैस तय कर लिया। जैसा पार्लियामैंट में होता हे अगर वैसा हो जाये तो क्या हर्ज है?

चौधरी बंसी लालः बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी क्यों अखर रही है?

चौधरी चांद रामः पूरे सै ान का अगर एक ही बार आ जाये तो क्या हर्ज है?

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, मेरी एक सबमि ान हैं। यहां पर चौधरी हल सिंह, चौधरी ि ाव राम वर्मा, चौधरी मनफूल सिंह राव दलीप सिंह सब यहां बैठे है। अगर इनकी कोई बात न मानी गई हो तो यह खड़े होकर कहें कि हमारी बात नहीं मानी गई हैं । जो यह कहते है वही प्रोग्राम बनता है। आज तक जैसे इन्होने कहा वही प्रोग्राम बना हैं।

चौधरी मनफूल सिंहः स्पीकर साहब, यह बात बिल्कुल ठीक है।

श्री अध्यक्षः बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी हाउस की एक कमेटी है। जैसे कि दूसरी कमेटीज हैं, इस कमेटी को अख्तियार है कि वह एक मीटिंग करे, दो मीटिग्ंज करे या चार मीटिग्ंज करें। जो भी बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिमैंडे ांज होती है, वे यूनानिमस हो जाएं उसी को हम मानकर चलते रहें।

समाज कल्याण एवं कराधान मंत्री(श्री भयाम चंद): स्पीकर साहब, असल बात यह है कि वहां ये कुछ ओर बात करते है ओर इनको आकर गलत बता देते है। (हंसी व विघन).....

Chaudhri Dal Singh: I protest. I never tell lie to my leader.

चौधरी बंसी लालः हमने आपका कोई सुझाव न माना हो, क्या आप यह कहते हो?

श्री अध्यक्षः बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी में जो फैसला होगा, उसी को मानकर मैं चलूंगा।

श्री के0एन0 गुलाटीः स्पीकर साहब, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। चौधरी चांद राम किन मैंबरों की तरफ से बोल रहे है इसका हमें पता नहीं है?

चौधरी चांद रामः मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं।

चौधरी बंसी लालः अगर यह अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहे है तो चौधरी दल सिंह से यह कहलवा दें कि बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी में सारे फैसले यूनानिमस नहीं होते। इनकी कोई डिस्सैन्टिग राय हो तो चौधरी दल सिंह बतला दे।

चौधरी मनफूल सिंहः वहां जो भी फैसले होते है वे इत्तेफाक राय से होते हैं।

श्री अध्यक्षः बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी जो फैसला करती है, उसी के मुताबिक टाईम चेंज होता है। स्पीकर अपनी मर्जी से टाईम चेंज नहीं करता। बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग होती है , उस में चेयर पाबन्दी नहीं कर सकती। वह हाउस की एक कमेटी है ओर वह खुद फैसला करती है कि एक दफा में फैसला करना है या दो दफा में करना है।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, मैं कोई चैलेन्ज नहीं कर रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि अगर एक दफा सारा प्रोग्राम आ जाए तो मैंबरों को सुविधा हो जाये।

Mr. Speaker: Order please. The question has been decided now.

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं.....

Mr. Speaker: Order please, Not in this manner. All the members are respectable members of the House and they

attend various committees. This is not the method to make suggestion.

चौधरी बंसी लालः यह सुझाव किसको दे रहे है। इनकी पार्टी के मैंबर है, उनको यह सुझाव दे दें।

Mr. Speaker: Question is-

That this House agrees with the recommendations contained in the Sixth Report of the Business Advisory Committee.

The Motion was carried.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण सम्बन्धी वर्तमान समिति की पदावधि 31—3—1976

Social Welfare and Taxation Minister(Shri Shyam Chand): Sir, I beg to move-

"Whereas a Committee called "the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes "consisting of nine members was constituted for one year in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 30th March 1973; and

Whereas the term of the Commiottee was further extended by one year upto 31st March 1975 in prusuance of a motion passed by Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 18th January, 1974; and

Whereas it is expendient that for the purposes explained in the motion passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting on the 30th Marcxh 1973, the Committtee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, should also function for the year 1975-76.

Now therefore, this House resolves that the term of the existing Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes which expires on the 31st March, 1975 be extended by a year i.e. upto 31st March 1976 for performing the functions as enunciated in the resolution passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 30th March 1973"

Mr. Speaker: Motion moved-

"Whereas a Committee called "the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes "consisting of nine members was constituted for one year in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 30th March 1973; and

Whereas the term of the Commiottee was further extended by one year upto 31st March 1975 in prusuance of a motion passed by Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 18th January, 1974; and

Whereas it is expendient that for the purposes explained in the motion passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting on the 30th Marcxh 1973, the Committtee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, should also function for the year 1975-76.

Now therefore, this House resolves that the term of the existing Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes which expires on the 31st March, 1975 be extended by a year i.e. upto 31st March 1976 for performing the functions as enunciated in the resolution passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 30th March 1973"

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। यहां पर इस कमेटी की मियाद के लिये एक्सटैं ान मांगी गई है। अगर तो पिछले साल की रिपोर्ट हमारे सामने आती तब तो इस एक्सटैन् ान की जस्टीफिके ान थी और अब जबकि हमारे सामने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई तो फिर इस एक्सटैन् ान की क्या जस्टीफिके ान है?

श्री अध्यक्ष: रिपोर्ट भी आ रही हैं। भाायद 17 जनवरी को इस हाउस के सामने आ रही है।

चौधरी दल सिंह(जींद): स्पीकर साहब, मेरी गुजारि ा है कि यह जो कमेटी थी, यह आज से दो साल पहले बनाई गई थी ओर उसके अन्दर तकरीबन सारे के सारे हरिजन मैंबर भी है और यह कमेटी हरिजनों की भलाई के लिये बनाई गई है। दो दफा पहले भी एक्सटैन् ान मांग चुके है और आज फिर इस के लिये एक्स्टैन् ान मांग रहे है। हमें इस बात की समझ नहीं आती कि इतनी देर तक इस कमेटी ने अपना काम क्यों नहीं खत्म किया? इस कमेटी के मैम्बर साहिबान को आने–जाने के लिए

टी0ए0, डी0 ए0 दिया जाता है इसलिये बहुत खर्चा पड़ता है सरकार के ऊपर। आखिर ऐसी कौन सी वजूहात है जिसके कारण यह कमेटी इतने टाइम के अन्दर अपनी रिपोर्ट देने में असमर्थ रही है या फिर गवर्नमैंट की ही हिदायतें है कि यह रिपोर्ट अभी पे ा न की जाए। यह बड़ी अजीब सी बात है कि एक तरफ तो हम हरिजनों की भलाई के लिये कह रहे है कि हरिजनों की भलाई होनी चाहिये और दूसरी तरफ यह हो रहा है कि अभी तक जो काम इस कमेटी ने किया है, उसको सदन के सामने लाने में हिचकचा रहे है। आखिर इसके कारण क्या है? यह जो एक साल का अर्सा देकर रिपोर्ट को इस सदन के सामने पे ा करवाया जाये ताकि लोागों को इस सरकार के कारनामों का, सरकार के दिमाग का पता चल सके कि आखिर यह सरकार जोकि हरिजनों की भलाई का दम भरती है, उनकी भलाई के लिये कोई कदम उठाने जा रही है। तो मैं गुजारि ा करूंगा कि इस कमेंटी को ज्यादा से ज्यादा दो महीने का और टाईम दिया जाये। इस साल का वक्फा बहुत ही लम्बा है। दो महीने से ज्यादा समय न दिया जाये।

चौधरी ि ाव राम वर्मा(नीलोखेड़ी): अध्यक्ष महोदय, यह कमेटी आज से दो साल पहले, एक साल के लिये बनाई गई थी ताकि वह ि ाडयूल्ड कास्ट ओर ि ाडयूल्ड ट्राइब्ल लोगों के हित के लिये अपनी रिपोर्ट दे और वह रिपोर्ट अभी तक हमारे सामने इस सदन में नहीं आई है। इस कमेटी की मियाद पिछले साल बढ़ा दी गई थी और आज दो साल बीत जाने के बावजूद भी इस

कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जिसके लिये एक साल की मियाद और मांगी जा रही हैं यह कमेटी 30 मार्च, 1973 को बनाई गई थी और 18–1–74 को इसकी मियाद फिर एक साल बढ़ा दी गई। न तो पिछले साल की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और न ही इस साल की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अगर इन दोनों सालों की रिपोर्ट हमारे सामने आती तो हम यह समझ पाते कि इस कमेटी ने हरिजनों की भलाई के लिये कितना काम किया है ओर यह पता चलता कि ये इस क्षेत्र में कितना आगे बढ़े है। इस देरी से यह पता चलता है कि इन्होनें हरिजनेां की द ाा सुधारने के लिये अपने कोई भी सुझाव अभी तक नहीं दिये है। अभी तक हम बिल्कुल अंधेरे में है कि इस कमेटी ने क्या काम किया है। यह बहुत जरूरी था कि अब तक यह रिपोर्ट हमारे सामने आती और फिर हम यह सोचते कि इस कमेटी की मियाद बढ़ानी ठीक है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, हमें कुछ नहीं पता कि कब तक यह मियाद बढ़ती रहेगी। हरिजनों के बारे में तो इस सरकार का कोई काम नहीं है, केवल बहकावा ही बहकावा है कि हम हरिजनों की भलाई के लिये यह कर रहे है, वह कर रहे है।

अध्यक्ष महोदय, एक बार सन 1972 में मैनें यह कमेटी बनाने का सुझाव सरकार को दिया था। उस वक्त मेरा यह सुझाव नहीं माना गया लेकिन सन 1973 में गवर्नमैंट आफ इण्डिया के कहने पर यह कमेटी बना दी गई थी। यह रिपोर्ट एक साल में हमारे सामने आनी चाहिये थी। पता नहीं क्या कारण है, समझ

नहीं पा रहा कि गवर्नमैंट ओर कितने समय तक डिले करती रहेगी। आखिर कब तक यह लोगों को बहकाती रहेगी? कब तक लोगों को लारों मैं रखेगी? मैं यह समझता हूं कि यह लारे जो है, यह ठीक नहीं है। फाइनल न सहि, कम से कम प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो हमारे सामने आनी चाहिये थी ताकि हम यह देखते कि कितना काम हो रहा हैऔर किस रूख से काम हो रहा हैं, यह विचारधारा किधर चल रही है? मेरा तो यह ख्याल है कि अभी तक इस कमेटी ने अपनी कोई रिकमैंडे ान भी नहीं भेजी होगी। इससे यह पता चलता है कि दो साल बीत जाने के बाद भी एक कदम इन्होने आगें नही बढ़ाया है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। दो साल में तो यह काम पूरा हो जाना चाहिये था। इस लिये मैं समझता हूं कि यह जो एक साल की और मियाद मांगी जा रही है, यह बहुत जयादा है। ज्यादा से ज्यादा तीन महीने की मियाद इस कमेटी को ओर दे दी जाये और इस समय के अन्द कमेटी को रिपोर्ट देने के लिये यह सदन डायरैक्टिव दे कि इतने समय के अन्दर वह रिपोर्ट दे।यह रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत कर दी जाये तब तो हम यह समझेंगें कि हरिजनों की भलाई के लिये कुछ भीघ्र कर सकेंगें लेकिन सरकार की बातों ही बातों से यह काम होने वाला नहीं है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस में सं ाोधन करके एक साल की मियादा को कम किया जाये ओर ज्यादा से ज्यादा तीन महीने इस कमेटी को दिये जायें, जिसमें वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुात करें।

सिंचाई एवं विद्युत मंत्री(श्री बनारसी दास गुप्त): अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की हैरानी है कि यह मैंबर साहिबान किस पर नुक्ताचीनी कर रहे है, किस पर आरोप लगा रहे है। इस हाउस के सम्मानीय सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई जिसने इस बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, तो ये जो सरकार के उपर आरो लगा रहे है कि सरकार बहकावे में रख रही है, लारे दे रही है, सरकार यह कर रही है, वह कर रही है। मुझे समझ नहीं आता कि इस में सरकार बीच में कहां से आ गई? मैंबर साहिबान को सदन में बोलने से पहले देख लेना चाहिये कि यहां किस विशय पर बोला जा रहा है ओर उन्हे बोलना क्या है? यह जो नुक्ताचीनी है, यह तो एक प्रकार से सदन की नुक्ताचीनी है। इस सदन मं सरकार के उपर तभी आरोप लगाया जा सकता है जबकि कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई हो ओर उसके बाद सरकार अमल न करती हो, आखिर यह किस पर नफताचीनी कर रहे हैं?

चौधरी ि ाव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह कह दिरया कि यह सदन की नुक्ताचीनी कर रहे थे। यह सदन की नुक्ताचीनी कैसे कही जा सकती हैं? यह जो कमेटी है, यह सदन ने बनाई है। सरकार जब इसके लिये तैयार न होगी तो कमेटी भी सेचेगी कि चलो ठीक है। सरकार उसकी रिकमैंडे ान को इम्पलीमेंट करने के लिये तैयार नहीं है। (ाोर).....

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह ख्याल है कि यह मर्यादा भंग का प्रस्ताव भी हो सकता है।

श्री के0एन0 गुलाटी(फरीदाबाद): स्पीकर साहब, जो भी मो ान हमारे सामने आता है उसके पीछे एक सदभावना होती है। यह जो मो ान आया है यह भी एक बड़ अच्छा मो ान है। यह कमेटी 1972 में बनाई जानी थी लेकिन एक साल लेट बनी। मैं तो चाहता हूं कि इसे उसी वक्त पांच साल के लिये बना देना चाहिये था। ये जो इसकी मुखलफित कर रहे है ये तो सिर्फ अखबारों में अपना नाम लाने के लिये कर रहे है। यह बात ठीक नहीं है, मैं इस मो ान के हक में हूं।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, यह जो अखबारों वाली बात कर रहे है क्या यह मैंबर के ऊपर एसप ान नहीं है?

श्री अध्यक्ष: इन्होने किसी मैंबर का नाम तो नहीं लिया।

श्री के0एन0गुलाटी: जब हम चाहते है कि हरिजनों का भला हो और भले के लिये ही यह कमेटी बनाई गई थी तो इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिये, इसलिये मैं पूरजोर सिफारि ा करता हूं कि इस कमेटी की टर्म 1976–77 के लिये भी बढ़ा दी जाये।

चौधरी चांद राम(बबैन–अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब,इसके बावजूद कि हम यह पढ़ते है कि हरिजनों की भलाई के लिये यह कमेटी की एक्सटैं ान मांगते है.....

श्री अध्यक्षः यह रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है ओर वह बिजनैस एडवाइजरी कमेटी के सामने भी आई थी। यह 17 तारीख को प्रैजेंट हो रही है। इसलिये आप इस बात को ध्यान में रख कर बोले।

चौधरी चांद रामः पार्लियामैंट और सैंटर में इस बात का फैसला हुआ कि हरिजनों की भलाई के लिये एक कमेटी बनाई जाये और उसकी मियाद एक साल रखी गई है। अगर वे यह समझते कि यह कमेटी दो साल या तीन साल के लिये होगी तो ऐसी पाबन्दी पहले ही लगा देते। लेकिन उन्होने यह पाबन्दी लगाई थी कि आए साल कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी का चुनाव होगा। अगर आप पार्लियामैंट को देखें तो वहां साल के बाद चेयरमैंन भी बदला जाता है ओर मैंबर भी बदले जाते है। इस हाउस ने इस कमेटी के मैंबर चुने थे, नामीनेट नहीं किये थे। हाउस का कमेटी के मैंबरों को चूनने का राइट है लेकिन मैं बर चुनने की बजये यहां पर यह मो ान आ गया कि जो पहले मैंबर चुने हुए है उनको एक्सटैं न दे दी जाये। इस कमेटी को बने हुये 24 महीने हो गये है। यह जिस काम के लिये कमेटी को एक्सटैं ान दे रहे है वह काम कमेटी 31 मार्च तक भी तो कर सकती है। अभी तो पिछली टर्म के भी दो अढ़ाई महीने बाकी पड़े हैं हरिजन संघर्श मिति के आन्दोलन के बारे में 17 दिसम्बर 1973 को चीफ मिनिस्टर साहब का स्टेटमैंट आया जिसमें इस कमेटी का भी जिक है कि हाउस ने एक कमेटी बना रखी है। यह कमेटी

हरिजनों के उत्थान के लिये बनाई गई है जो यह देखेगी कि हरिजनों के साथ न्याय हुआ है या उनको रियायतें मिलती है या नहीं। तो चीफ मिनिस्टर सहब के इस ब्यान के उपर हमने आन्दोलन वापिस ले यिा। लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट तो क्या आनी थी, ये तो अभी उसके लिये ओर एक्सटैं न मांग रहे है। इसके अलावा एक और कमेटी बनी थी उसकी भी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। इसमें बात कुछ भी नहीं है, थोड़ी इनफर्मे ान हर महकमें से लेनी है कि फलां–फलां जगह पर जो काम था वह तुमने पूरा कर दिया या नहीं और दूसरी बात यह है कि तरक्की के लिये अगर कोई लीाकूना रह गया है, उसके लिये सुझाव देना है तो इसमें ऐसी कौन सी बात है जो इतनी देर लग रही हैं बनारसी दास जी गुप्त जैसे आदमी जो स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान रह चुके है, हर बात पर यह कह देते है कि यह प्रितिलेज का क्वै चन है तो हमको तो इनसे डर लगने लग गया।

Mr. Speaker: The Hon'ble member is asking from whom? (ाोर) मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपकिस से किस कमेटी के बारे में पूछ रहे हैं? यह कमेटी तो हाउस के मैंबरो की है।

चौधरी चांद रामः मैं तो आप से पूछ रहा हूं । हमारे राइट्स के प्रोटैक्टर आप है। यहां एक मो ान आया है, क्या मो ान पर हम जुबान बन्दी कर लें? हम कुछ बोलें भी न? यहां

एक मो ान आया है ओर उसको हम अपोज कर रहे है। अगर अपोज करने में.....(ाोर).....

Mr. Speaker: You can certainly oppose, but from whom are you asking? Whom are you addressing? कमेटी के मैंबरों को या गवर्नमैंट को?

चौधरी चांद रामः जो मूवर है, हम मूवर से कह रहे है कि यह उसे मूव नहीं करना चाहिये क्योकि उन मैंबरों ने अपना पूरा काम नहीं किया और उनकी जगह पर दूसरे मैंबर आनेचाहिये। हम यह इसलिये कह रहे है ताकि ये मैंबर जल्दी काम करें। अब भी 31 मार्च तक टाईम पड़ा है। आपपने कहा है कि कुछ रिपोर्ट आ गई है और कुछ नहीं आई तो अभी 31 मार्च तक टाइम पड़ा है इसके बाद जब फिर सै ान आएगा गवर्नमैंट किसी वक्त भी दूसरी कमेटी बनवा सकती है। गवर्नमैंट के मन में भाायद आ गया हो कि नया चेयरमैन और नई कमेटी आ जाएगी, लेकिन वह तो गवर्नमैट का अख्तियार है या रूलिंग पार्टी का अख्तियार है। हमारी अपोजी ान का तो एक ही मैंबर है। जहां तक मुझे पता है, अगर मैं गलती नहीं करता, वह है चौधरी पीर चन्द और बाकी जो मैंबर है वे या तो कांग्रेस पार्टी के है या वे है जो गवर्नमैंट को स्पोर्ट करते है। इसलिये मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप मूवर का सलाह दें कि यह एक्सटैं ान का प्रस्ताव न लांए बल्कि इस कमेटी को हिदायत करें कि वह इस काम को 31 मार्च तक पूरा कर दे।

मुख्य मंत्री(चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, यह रैपिटी ान बन्द होनी चाहिये, हाउस का टाईम जाया हो रहा है। जो बात इन्होने कहनी थी वह तो कह ली हैं।

चौधरी चांद राम: 31 मार्च, 1975 तक यह कमेटी रिपोर्ट करे ओर इसकी एक्सटैं ान न की जाये। इसके बाद हाउस दूसरी कमेटी बनाए।

Social Welfare and Taxation Minister(Shri Shyam Chand): Mr. Speaker, Sir, this Committee was constituted by the Vidhan Sabha on the pattern of Parliament. Parliament also constituted one Standing Committee for the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Nine members were elected by this August House and and two M.L.As from opposition Benches are also Members of this Committee. I don't know how many sittings this Committee has held? But I think they are doing their work satisfactorily and you know, Sir, that there are more than 50 Departments, which this Committee has to examine. They have to see to the representation of scheduled castes and scheduled tribes in recruitment and promotion and other socio-economic matters. I think it will take some time.

About the pressure of the Government, as Mr. Dal Singh pointd out that there may be some pressure from the Government, I wish to assure this august House that I have never asked any member of this Committee, what he is doing or what they are doing.

Further, I submit, Sir, this Committee was constituted for the purpose by the members of this House and if the term of the Committee is being extended by one year that is by majority vote. So he should not grudge, if Mr. Chand Ram does not become member of this Committee.

चौधरी चांद रामः अगर आप नोमीनेट करें, मैं तब भी नहीं आऊंगा।

श्री भयाम चन्दः इनकी चार वोटें है और मैंबर इलैक्ट होने के लिये 9 मैंबर चाहिये। (विघन्)

एक आवाजः अब तो इनकी तीन बोटें रह गई है।

चौधरी बंसी लालः रोज आगे सीट मांगा करता था, अब तो यह मामला बन्द कर रखा है (हंसी व भाोर)

चौधरी चांद रामः हमारी आल इंडिया लैवल की पार्टी है और उसे इलैक ान कमि ान ने रिकोगनाइज कर रखा है..... (ाोर).....आप सीट न दें तो दूसरी बात है।

श्री अध्यक्षः आर्डर प्लीज। जो पार्टीज हाउस के बाहर रिको गनाइज्ड है उनका हाउस के अन्दर भी रिकोगनि ान जरूरी नहीं है। मैं उस पार्टी को रिकोगनाइज करूंगा जो हाउस के अन्दर है। (ाोर)

चौधरी चांद रामः रूल्ज के मुताबिक ही हमने यह लिख कर दिया था कि हम चार मैंबर है ओर हमें अलग से सीट दी जाये। (ाोर) अब तो तीन रह गये है (ाोर)

Mr. Speaker: I am acting according to the Rules. There is no Party or Group recognised except the Congress.....

श्री भयाम चन्दः स्पीकर साहब, यह किस चीज पर बोल रहे है?

I don't know whether he is speaking on a point of order or making submission?

Mr. Speaker: Please Continue.

Shri Shyam Chand: Sir, he calls himself a great parliamentarian, always speaks without the permission of the Chair. When he has to say something, he stands up and puts silly questions.

Chaudhri Chand Ram: Silly q uestions.....Is it parliamentary?

Shri Shyam Chand: Yes.....It is parliamentary expression.

Mr. Speaker: Order please.....No interruptions.....

Shri Shyam Chand: He referred to agitations कि इन्होने कोई आंदोलन किया था। हमें तो पता नहीं कि वह किस

लिये किया था और I don't know on what grounds he has withdrawn it, यह अपने आप से पूछ ले। with these words, I will now request this august House to pass this resolution.

Mr. Speaker: Question is-

"Whereas a Committee called "the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes "consisting of nine members was constituted for one year in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 30th March 1973; and

Whereas the term of the Commiottee was further extended by one year upto 31st March 1975 in prusuance of a motion passed by Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 18th January, 1974; and

Whereas it is expendient that for the purposes explained in the motion passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting on the 30th Marcxh 1973, the Committtee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, should also function for the year 1975-76.

Now therefore, this House resolves that the term of the existing Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes which expires on the 31st March, 1975 be extended by a year i.e. upto 31st March 1976 for performing the functions as enunciated in the resolution passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 30th March 1973"

The motion was carried.

दी हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 2) बिल, 1975

Finance Minister(Shri Ram Saran Chand Mittal): Sir, I beg to introduce the Haryana Association (No.2) Bill, 1975.

I also beg to move-

That the Haryana Appropriation (No.2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Appropriation (No.2) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी दल सिंह(जींद): स्पीकर साहब, सदन के सामने इस वक्त अप्रोप्रिये ान (नं0 2) बिल पे ा है और सरकार इसके जरिये 4841163806 रूपये 1975–76 के दौरान खर्च करने के लिये मन्जूर करवा रही है। इस बिल के अन्दर एग्रीकल्चर के लिये जो रकम रखी गई है वह है 91613300 रूपये। स्पीकर साहब, यह बहुत अहम मदद है क्योंकि इस दे ा की 85 फीसदी और खास तौर से हरियाणा की 90 फीसदी आबादी खेती पर गुजारा करती है। इसलिये मैं तो समझता हूं कि खेती के लिये जो रकम रखी गई है वह थोड़ी है क्योंकि अगर हम खेती की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान नहीं देगें तो उसका नतीजा यह होगा जो आज हमारे सामने है हमारे साथी बहुत कुछ कहते है कि इस में बहुत तरक्की

कर दी लेकिन जो इस बारे में सही पोजी ान है वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं ताकि यह भाई समझ सकें महसूस कर सकं कि हरियाणा में खेती के मामला में कोई खास कार्यवाही नहीं की गई है। यह ठीक है कि सरकार ने बिजली के बहुत खम्बे लगा दिये इसकी एक्सटैं ान कर दी लेकिन बिजली की पैदावार नहीं की है बल्कि उस बिजली को फैलाया है जिसका नतीजा यह हे कि हरियाणा का सत्याना ा.....

श्री अध्यक्षः आप इसमें यह देखें कि रैपीटी ान न हो जो पहले कह चुके है।

सिंचाई एवं बिजली मंत्री(श्री बनारसी दास गुप्त): स्पीकर साहब, आप इनकी गवर्नर एड्रैस पर जो स्पीच है उसे निकलवा कर देख लें जोउस वक्त बातें कही थी, वही बातें अब निकलेगी। (विघन)

चौधरी दल सिंहः आप भी अपनी पिछली स्पीचें निकलवा कर देख लो (विघन) तो मैं अर्ज कर रहा था कि देखना यह है कि हरियाणा प्रांत में खेती की पैदावार कितनी बढ़ी है। हरियाणा प्रांत जैसा कि आप जानते है। 1 नवम्बर 1966 में बना और उसके बाद एक सरकार आई जा`चार महीने रह सकी और चार महीने के अन्दर कोई सरकार कोई काम नहीं कर सकती। उसके दूसरी सरकार आई और वह सरकार विरोधी दल की सरकार थी जो तकरीबन एक साल तक रही। उसके बाद यह

मौजूदा सरकार आई जो उसके बाद से लगातार चली आ रही है। अब देखना यह है कि आया जिस तरह हमारे ये साथी कहते है कि हमने बहुत तरक्की खेती में कर दीख वाकई सच है या नहीं? तो इसके बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं ओर अपनी तरफ से कोई आंकड़े पे ा नहीं करूंगा बल्कि इसी सरकार के आंकड़े पे ा करना चाहता हूं जो जाहिर करेगें कि इनके आने के वक्त से लेकर आज तक हरियाणा में खेती के मामला में कोई काम नहीं हुआ हैं।

श्री बनारसी दास गुप्तः यह आंकड़े पहले ही आपके रिकार्ड पर है।

चौधरी दल सिंहः यह वह नहीं है उनके अलावा है। मैं 1967–68 के साथ कम्पेरेजन करना चाहता हूं क्योंकि उस वक्त विरोधी दल की सरकार थी और उसके बाद यह सरकार आई थी। तो 1967–68 में चावल की का त 2 लाख 17 हजार हैक्टैयर में होती थी औरउसके चार साल बाद 1972–73 में जब इस सरकार ने चार साल तक काम कर लिया चावल की खेती के नीचे कुल रकबा 340300 हैक्टेयर हो गया यानि चार साल में 123300 हैक्टेयर रकबा बढ़ा। बाजरा की फसल 1967–68 में 385000 हैक्टेयर जमीन में का त होती थी और 1972–73 में इसकी 904000 हैक्टेयर में का त हुई यानी चार साल में 681000 हैक्टेयर ज्यादा बाजरा की का त हुई। इसी तरह से आप गेहूं को ले लें तो यह चार साल में तकरीबन 12 लाख हैक्टेयर में ज्यादा

बोया गया । अब आप खाद को दखें। खेती की पैदावार करने के लिय खाद एक बहुत ही जरूरी साधन है। 1967–68 में 47024 टन खाद इस्तेमाल किया गया हरियाणा के अन्दर और 1972–73 में चार साल के बाद इसका इस्तेमाल बढ़ कर 93892 टन हो गया। इसके बाद आप ट्रैक्टर्ज को लें क्योंकि खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये ट्रैक्टर्ज का बड़ा योगदान है क्योंकि अगर ट्रैक्टर्ज ज्यादा होगें तो वाही ज्यादा होगी और जब वाही ज्यादा होगी तो पैदावार भी ज्यादा होगी, साफ बात है। तो मै। अर्ज करता हूं कि 1968–69 में हरियाणा में 9403 ट्रैक्टर्ज होते थे ओर इनके चार साल के राज के बाद इनकी तादाद 1972–73 में 14114 हुई यानी पांच हजार से ज्यादा ट्रैक्टर्ज का इस्तेमाल बढ़ा। अब आप अधिक उपजाऊ बीजों के तहत जो एरिया जेरे का त आयाजहां अच्छे बीज डाल कर खेती की गई, उसके बारे में देख लें। चावल के मामला में 1968–69 में 13 हजार हैक्टेयर में अच्छे बीज डाल कर चावल की का त की गई और 1972–73 में यह एरिया बढ़ कर तीन लाख हैक्टेयर हो गया इसी प्रकार आप गेहूं को लें। उसी साल गेहूं की 250000 हैक्टेयर में बढ़िया बीज डालकर फसल पैदा की गई जबकि 1972–73 में 1209050 हैक्टेयर में बढिया बीज डालकर फसल पैदा की गई। फिर आप टयूबवैल्ज की तरफ आयें। यह मानते है कि 1968–69 में हरियाणा में 29000 थे ओर अब कहते है कि ये 146110 है यानी एक लाख से ज्यादा इनकी तादाद बढ़ गई। इसके अलावा सरकार ने कई करोड़ रूपये नहरें बनाने के लिये खर्च किये। तो यह सब कुछ करने के बाद ओर करोड़ों

रूपयें खर्च करने के बाद इन चार सालों में जो पैदावार बढ़ी वह भी आप देख लें। 1967–68 के अन्दर जब कि विरोधी सरकार थी 39 लाख 70 हजार टन अनाज पैदा हुआ था और 1972–73 में 40 लाख 72 हजार 900 टन हुआ। इस तरह से चार सालों में 1 लाख 29 हजार टन ज्यादा पैदा कर सके है। बावजूद इसके कि लाखें एकड जमीन ज्यादा का त करते है, नहरों का जाल बिछा दिया गया और अनाज जो पैदा हुआ वह आपके सामने है। बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी डिवैल्पमैंट के नारे देते है लेकिन पैदावार कुछ भी नहीं। इस साल 38 लाख टन अनाज पैदा हुआ है जबकि 1967–68 में 39 लाख 70 हजार टन अनाज पैदा हुआ था। इस साल तो उससे भी कम पैदा हुआ। अगर पूछा जाये तो कहते है कि कुदरती बात है, भगवान ने बारि ा नहीं की। भगवान की तो बात ही नहीं है, यह सरकार ही निकम्मी है। एक तरफ तो कहते है कि भगवान ने बारि ा नहीं की और दूसरी तरफ डींग मारते है– नहरों की, बड़ी–बड़ी का त की, बिजली की, टयूबवैल्ज की। यह फिगर दी है। यह सरकार की अपनी फिगर है। मुझे हैरान है कि 6 साल के राज के बाद, अरबों रूपया खर्च करने के बाद यह सरकार एक टन अनाज भी हरियाणा के अन्दर फालतू पैदा नहीं कर सकी। फिर कहते है कि हमने बड़ी तरक्की की है। मैं कहता हूं कि इस तरक्की से हम बाज आये। एक बात तो यह हुई। दूसरी बात यह है कि जो चीजें अनाज पैदा करने की है, उनकी कीमतें आसमान को छू रही है। खद की कीमत 20 रूपये से बढ़ कर 105 रूपये कट्टा हो गई है। 500 परसैन्ट फालतू कीमत बढ़ी है।

टयूबवैल की 190 परसैन्ट, ट्रैक्टर की कीमत 50 परसैन्ट फालतू बढ़ी है। जब इतनी ज्यादती किसान के साथ हो तो सरकार किसान की पैदावार क्यों उचित भाव पर न खरीदें। स्पीकर साहब, 1966–67 में 100.37 पैसे फी क्विंटल अनाज बिकता था।

Pandit Chiranji Lal Sharma: No,No.

Chaudhri Dal Singh: This is in the book "statistical abstract of 1973-74". You can see it and examine it, 1973 में 86.84 पैसे थी और दूसरी तरफ आप देखें किसान के उपर कितना खर्चा बढ़ा है, कोई ठिकाना नहीं। सरकार ने अरबों रूपया नहरों पर खर्च किया, बिजली पर खर्च किया, खाद के उपर किया, ट्रैक्टरों के उपर किया लेकिन तब भी यह हालत है। पिछले चार सालों में किसान की पैदावार की कीमत घटी है बढ़ी नहीं। इसके दो ही तरीके है। स्पीकर साहब, अगर सरकार किसान की पैदावार की उचित कीमत दे तभी वह अपनेखर्चे को सप्लीमैंट करसकता है। अगर एक गाय कादूध निकालने वालाल आदमी दूध निकालता रहे और उसको चारा न दे तो वह गाय आगे के लिए दूध देने वाली नहीं है। यही हाल किसान का है, अगर सरकार उसको सहूलियात नहीं देती तो वह पैदावार करने वाला नहीं। अगर सरकारपैदावार बढ़ाना चाहती है तो उसके साथ हमदर्दी करनी पड़ेगी। हमदर्दी नहीं तो पैदावार नहीं। पैदावार की उचित कीमत सरकार बे ाक न दे लेकिन अगर उसको जायज कीमत पर एग्रीकल्चर का सामान मिले तो सबसे अच्छी बात है। उसको

इन्सैंटिव दो। उसके लिए पैदावार के जराये पैदा करो जिससे किसान की पैदावार दूगनी हो जाए ताकि जहां 20 क्विंटल अनाज पैदा हो, वहां 40क्विंटल बढ़ जायें। कोई बात नहीं, भाव न बढ़ायें लेकिन खाद वगैरा उचित कीमत पर दे। बिजली के खम्भे लगाने से काम नहीं चलेगा। मुनाफा नहीं दे सकते तो सामान देना पड़ेगा, तभी पैदावार बढ़ सकती है। इसके दूसरी तरफ 500 परसैंट कीमतें बढ़ गई है, किसान खाद नहीं खरीद सकता। पिछले साल खाद ब्लैक में बिकी। लोगों को खाद नहीं मिलती थी लेकिन इस साल खाद की कीमत बढ़ जाने से बाजार में खाद के ढेर पडे हुये है, कोई लेता नहीं क्योंकि किसान इतनी मंहगी खाद खरीद नही सकता। हरियाणा के उपर खाद के सूद का खर्चा 72 लाख रूपये हैं । जहां सरकार 72 लाख रूपया सूद का देती है वहां किसान को सबसिडी क्यों नहीं देती, सरकार इस बात का ऐलान करे कि हम किसानों को सबसिडी देगें, फिर देखो कितनी खाद उठती है? लेकिन अगर यही नीति रही तो पेदावार नहीं बढ़ सकती।ये किताबों में आंकड़े छापते रहेगें। सब किताबों में ही रह जाएगा असलीयत में कुछ नही होगा? हरियाणा की सरकार पिछले 6 सालों में एक टन अनाज नहीं बढा सकी। इसका कारण यह है कि सरकार किसान को खु ा नहीं कर सकती। आज किसाान की बुरी हालत है, छोटे–छोटे होल्डर है जिनका गुजारा नहीं चलता। या तो सरकारउनको पैदावार की उचित कीमत दे, अगर नहीं दे सकती तो जायज कीमत पर ऐसे जराये पैदा करे, ऐसे साधन पैदा करे जिससे किसान की पैदावार दुगनी हो जाए। तब भाव बढ़ाने

की जरूरत नहीं। वाकई ही यह सोचने वाली बात है, इस पर सरकार गौर करे। स्पीकर साहब, मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा प्रान्त में टैक्सों ने कितनी कीमतें बढ़ा दी है। हर जगह टैक्स, हर बात पर टैक्स, बड़ी हैरानी है, जनता परे ाानी में है ओर इधर सरकार कहती है कि बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया गया। जिस बजट में एक तो 17 करोड़ रूपये का घाटा हो ओर दूसरी तरफ सरकार कहे कि कोई टैक्स नहीं है, कितनी हैरानी की बात है। जब असैम्बली का सै ान खत्म होगा तो एक महीने के अन्दर राज्यपाल महोदय से आर्डिनैंस ले आयेगें कि टैक्स लगेगा क्योंकि ये मैजोरिटी मे है, पास करवा लेते है। आज कहते है कि टैक्स नहीं लगाया गया। अगर इनके दिल में सच्चाई है और टैक्स लगाना है तो डरते क्यों है? लेकिन पीछे से घुस कर टैक्स लगाना ठीक नहीं है। यह प्रजातन्त्र की बात है। यह काम प्रजातन्त्र के हिसाब से होना चाहिये। 1967–68 के अन्दर ऐन्टरटेनमैंट टैक्स 50 लाख 14 हजार था। 1972–73 में 1 करोड़ 90 लाख 26 हजार हो गया। इस तरह से 1967–68 में भाो टैक्स 42 लाख, 95 हजार था और 1972–73 में बढ़कर 1 करोड़ 6 लाख 14 हजार हो गया। यानी 4 सालों में 58 लाख 19 हजार रूपये प्रान्त के अन्दर भाो टैक्स बढा । पैसेंजर एंड गुड्ज टैक्स की भी यही हालत है। 1967–68 में 2 करोड़ 77 लाख, 99 हजार था और 1972–73 में 1 करोड़ 2 लाख 52 हजार हो गया। इस तरह 61 लाख 57 हजार रूपया अकेले स्पिरिट टैक्स में बढोतरी हुई। हमारी स्टैट का सैल्ज टैक्स 1967–68 में 5 करोड़ 70 लाख

29 हजार था और 1972–73 में 12 करेाड़ 25 लाख 53 हजार हो गया। इस तरह चार सालों में.....(विघन)

Revenue Minister(Pandit Chiranji Lal Sharma): Mr. Speaker I rise on a point of Order. My Point of order is that this discussion on Budget and then on the Demands has been going on for the last four days and it is nor the Appropriation Bill before the House. The figures that are being given by the hon. Member is a repetition because the same were given by a Member of his party yesterday, Whether this repetition is allowed?

Mr. Speaker: I have already said in the beginning of his speech that there should be no repetition of arguments by any hon. Member on points which have already been raised either on discussion on Budget or discussion on Demands for Grants.

Pandit Chiranji Lal Sharma: And as such, this being your findings the figures being given by the hon. Member amount to a repetition.

चौधरी दल सिंहः चलो मैं छोड़ देता हूं। एक फिगर रह गई है, वह कह देता हूं। सैन्ट्रल सैल्ज टैक्स 1967–68 में 3 करोड़ 57 लाख, 82 हजार था और 1972–73 में 8 करोड़ 6 लाख 33 हजार हो गया। इस तरह 4 सालों में 4 करोड़ 48 लाख, 61 हजार रूपये का अधिक टैक्स मिला। रजिस्ट्रे ान फी इस सरकार ने 6 परसैंट से बढ़ा कर 10 परसैंन्ट कर दी। मार्किटिंग फी, स्पीकर साहब, पहले 20 पैसे थी लेकिन अब 200 पैसे कर दी गई

है। टवन्टी हन्डर्ड यानी दो हजार परसैन्ट इन्क्रीज इसमें हुई है। हमने तो अपनी जिन्दगी में पहले कभी न तो ऐसा देखा और न सुना। किसी तारीख के अन्दर भी इस तरह की बात पढ़ने को नहीं मिलती कि हिन्दुस्तान की किसी स्टेट ने पहले इतनी ज्यादा इक्रीज किसी आईटम में की हो। इन्होने अगर यह तो हजार गुनी इक्रीज की है तो मिनिस्टर साहब बड़ी खु ाी से जवाब दें। (विधन)

श्री ओम प्रका ा गर्ग: स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। इस बिल के उपर सिर्फ दो घंटे की डिसक ान है। मेरे आनरेबल दोस्त को लगभग आध घंटा बोलते हो गया है जबकि अभी बहुत सारे मैंबर साहबान बोलने वाले है। तो मेरी यह रिकवैस्ट है कि जरा इस बात का ध्यान रखा जाये।

Mr. Speaker: Quite Correct. But the Member himself has put the me limit.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, यह जो वर्श 1974–75 का सप्लीमैंटरी बजट है इस पर भी अभी डिसक ान होनी है। अगर दोनों डिसक ांज इकट्ठी कर दी जायें तो बोलने वाले को भी आसानी होगी और समय की भी बचत हो सकती है। .....(विघन)

श्री अध्यक्ष: रूल्ज के हिसाब से यह इक्ट्ठी नहीं हो सकती।

चौधरी दल सिंहः तो स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि मार्किटिंग फीस 20 पैसे से बढ़ाकर 200 पैसे की गई है। अगर ये हिसाब लगाएं तो यह दो हजार परसैंट ज्यादा है। (विधन)..... इसी तरह से बस फेयर तीन सौ परसेंट बढ़ा है। एक नई चीज, स्पीकर साहब मैं आपको और बताता हूं। यह पार्टी कहती है कि हम महात्मा गांधी के पैरोकार है। दिखाई भी देता है कि ये नकली पैरोकार हैं। महात्मा गांधी तो कहते थे कि –'

'Liquour ruines a man mentally, physically, morally and economically.'

परन्तु यहां तमा ाा ही और है। भाराब की कंजम्प ान, स्पीकर साहब, सन् 1967–68 के अन्दर 2979801 लीटर होती थी लेकिन 1972–73 में यह बढ़ कर 4507969 लीटर हो गई । 25 लाख लीटर भाराब की बढ़ोतरी चार साल के अन्दर , इस सरकार के वक्त में हुई है। स्पीकर साहब, यह सिर्फ कंटरी लिकर की फिगर थी। बाहर से जो भाराब आती है उसकी खपत सन 1967–68 में 149354 लीटर थी लेकिन 1972–73 में यह 717121 लीटर हो गई। चार वर्श में 567767 लीटर भाराब ये बाहर के मुल्कों से हरियाणा प्रान्त के अन्दर लाये है। इसी तरह से स्पीकर साहब, आप बीयर की फिगर्ज देख लें। 1967–68 में 331794 लीटर बीयर इस्तेमाल हुई जबकि 1972–73 में 1453833 लीटर इस्तेमाल हुई है।

कृशि मंत्री(चौधरी भजन लाल): तरक्की ही हुई हैं।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब बड़े खु ा हो रहे है और कहते है कि तरक्की हुई है। अगर यह तरक्की है तब तो मैं कहूंगा कि ये दे ा का बेड़ा गर्क करना चाहते है। महात्मा गांधी जी के पैराकार हेाते हुये अगर ये इस तरह की बात कहते है तो लानत है इस सरकार के उपर। (विघन)

चौधरी फूल चन्द(मुलाना): स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। मेरी सबमि ान यह है कि इन्होनें जो डैरोगेटरी रिमाक्र्स इस्तेमाल किये है कि 'दे ा का बेड़ा गर्क करना चाहते है'' they should be expunged.

Chaudhri Dal Singh: They are not derogatory. Anyway, let the hon, Speaker decide it. It does not matter.

Mr. Speaker: Please wind up.

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, इस तरह से 1122039 लीटर बीयर हरियाणा में ज्यादा इस्तेमाल हुई है।

जहां तक, स्पीकर साहब, सिविल लिबर्टी का ताल्लुक है, उसका हिसाब यह है कि तमाम म्युनिस्पिल कमेटीज सुपरसीडिड हैं। तमाम जिला परिशदें ऐबोलि ड है और तमाम मार्किटिंग कमेटियां भी लगभग खत्म है। उनमें काम चलाने के लिए ये अपने चट्टे–बट्टे रखते है। आज हालत यह है कि किसी मार्किटिंग कमेटी का काम तसल्लीबख्भा नहीं है। म्युनिसिपल कमेटी का काम तो भाायद कहीं तसल्लीबख्भा हो क्यौंकि वहां ऐड–मिनिस्ट्रेटर है

लेकिन जहां तक मार्किटिंग कमेटी का सम्बन्ध है, उनका तो बेड़ा ही गर्क है। इन्होनें हरियाणा प्रान्त की बिल्कुल तसल्ली कर रखी है।

श्री ओमप्रका ा गर्ग: स्पीकर साहब, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि दो घंटे की टाईम लिमिट है लेकिन बोलने वाले अभी बहुत से मैंबर साहबान है।

Chaudhri Dal Singh: Only one minute.

Mr. Speaker: The hon. Member himself is a party to this decision.

चौधरी दल सिंह: स्पीकर साहब, मैं केवल एक मिनट और लूंगा। ऐजुके ान डिपार्टमैंट के अन्दर स्पीकार साहब सन 1972 से 367 एम्पलाईज ऐसे है जो सैन्टर के है। वे ऐडमिनिस्ट्रे न के तौर पर तो हरियाणा प्रान्त के तहत है लेकिन उनका सारा खर्चा भारत सरकार देती हैं परन्तु मजे की बात यह है कि उनको न तो हरियाणा प्रान्त के बैनिफिट मिलते है और न ही सैन्टर के मिलते है। स्पीकर साहब, मेरी गुजारि ा यह है कि उनके बारे में सरकारएक फैसला करे कि जो सैन्टर के 367 मुलाजिम ऐजुके ान डिपार्टमैंट के अन्दर है, जिन्होने रिप्रैजैन्टे ान दी है, आया वे हरियाणा प्रान्त के बैनिफिटस ले सकते है या सैन्टर के बैनिफिटस ले सकते है। अगर हरियाणा सरकार उन्हे नहीं चाहती तो भी साफ लफजों में कहे ताकि वे सैन्टर में चले जायें। यह गुजारि ा करते हुये , स्पीकर साहब,

अगर आप और टाईम नहीं दते तो मैं बैठ जाता हूं। आपका मैं म कूर हूं कि आपने मुझे टाईम दिया। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री के0एन0गुलाटी(फरीदाबाद): स्पीकर साहब आपका बहुत–बहुत धन्यवाद जो अपने मुझे बोलने के लिये मौका दिया। जहां तक इस ऐप्रोप्रिए ान बिल का सम्बन्ध है यह बिल्कुल ठीक है। जहां तक डिफरैन्ट डिमांडज के लिए पैसा देने की बात है, यह भीठीक है, क्योंकि हर डिमार्टमैंट अनथक कोि ा ा करता है कि गवर्नमैंट का पैसा पब्लिक इन्ट्रैस्ट के लिए खर्च हो । लेकिन चूंकि हम लोग भी फील्ड में काम करते है, काम होता हुआ देखते है इसलिये मैं कुछेक बातें सुझाव के रूप में आपकी मार्फत हाउस के सामने रखना चाहता हूं ताकि डिपार्टमैंट के आफिसर्ज और आनरेबल मिनिस्टर साहबान उनकी तरफ ध्यान दे।

स्पीकर साहब, जनरल एडमिनिस्ट्रे ान के लिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे देखने में आया है कि कुछ ऐम्पलाईज काफी–काफी देर तक टैम्परेरी तौर पर चलते रहते है। मिसाल के तौर पर सो ाल वैलफेयर डिपार्टमैंट की बात मैं आपको बताता हूं। एक अनस्टार्ड क्वै चन का जवाब मुझे मिला है। उसके मुताबिक 92 ऐम्पलाईज परमानैन्ट हे और 135 टैम्परेरी है जो कि काफी सालों से काम कर रहे है। तो मेरी गुजारि ा है कि हर डिपार्टमैंट में, चाहे वह सो ाल वैलफेयर हो चाहे पब्लिक हैल्थ हो, उनके लिए एक लिमिट तय हो जाए कि मैक्सिमम दो साल या

तीन साल के अन्दर–अन्दर वे बकायदा परमानैन्ट हो जाएगें ताकि ऐम्पलाईज को इससे कुछ सहूलियत मिले।

स्पीकर साहब, मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि एस0डी0ओ0 (सिविल) और एस0डी0एम0 के पास बड़ा वर्क लोड है। मै सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि एस0डी0ओ0 (सिविल) और एस0डी0एम0 की पोस्ट्स अलग–अलग कर दी जाये तो वर्क लोड भी कम हो जायेगा और तेजी से काम भी होगा।

स्पीकर साहब, मैं कई दफ्तरों में अक्सर जाता रहता हूं। ठीक है, काम तो चलता है लेकिन कुछ–कुछ रिप्रैजैन्टे न काफी देर तक पड़े रहते है। उनका न तो 'न' में और न ही 'हां' में जवाब मिलता है। अगर हर रिप्रैजैन्टे ान फस्ट डे पर ऐकनौलेज कर दिया जाए, उसके बाद भले ही महकमा कुछ देर के लिए उसे अपने पास रख ले, तो उससे लोगों को कम से कम यह तसल्ली मिल जाये कि उनके लेटर की पहुंच का जवाब तो आ गया है।

इसके बाद, स्पीकर साहब, मेरी अर्ज यह है कि सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने फरीदाबाद को 'ए' क्लास सिटी करार दिया है ओर वह अपने ऐम्पलाईज को सी0सी0ए0 देती है। अगर इसी तरह स्टेट सरकार भी उसे 'ए' क्लास सिटी मानकर सी0सी0ए0 अपने ऐम्पलाईज को दे दे तो ठीक रहेगा।

होम डिपार्टमैंट के मुताल्लिक, स्पीकर साहब, मेरी गुजारि ा यह है कि मैं मानता हूं कि हमारे यहां ला एंड आर्डर बिल्कुल ठीक है ओर बहुत अच्छे ढंग से यहां ला एंड आर्डर चलता है। मेरे फरीदाबाद में दो थाने है, एक पांच सैक्टर में और एक 15 सैक्टर में। उन दानों थानों को मथुरा रोड़ डिवाईड करता है। एक थाना मथुरा रोड के इधर है तो दूसरा थाना मथुरा रोड के उधर है लेकिन दूर–दूर के देहात ओर भाहर बड़े अजीब ढुंग से उन थानों के साथ लगे हुये है। तो मेरी गुजारि ा है कि बहुत बेहतर होगा यदि उस मथुरा रोड को ही डिवाईडिंग लाईन मानते हुये नीरैस्ट पुलिस स्टे ान एण्ड नीयरैस्ट प्लेस के हिसाब से उस तरफ के देहात और भाहरी हल्के उस तरफ के थाना को दे दिए जाएं ओर इधर वाले देहात ओर भाहरी इलाके इधर वाले पुलिस स्टे ान को दे दिए जायें।

स्पीकर साहब, मैं रैवंन्यू डिपार्टमैंट के बारे में इतना कहना चाहता हूं कि हर तहसील में रजिस्टरी होती है। ये रजिस्टरियां 60 परसैन्ट गरीब लोग कराते हैं गरीब लोग 20–25 हजार रूपये तक की रजिस्टरियां करवाते है। उनसे भी रैडकास या स्माल सेंविग का गवर्नमैंट के इन्ट्रैस्ट की चीज है। लेकिन मैं आपकी मार्फत इतना अर्ज करना चाहता हूं कि डिस्कि ानरी वर्ड को उड़ा दिया जाये। जो फरीदाबाद में 20–25 हजार रूपये तक की रजिस्टरी कराये उससे कोई डोने ान न लिया जाये क्योंकि कई दफा डिस्की ान की पावर का मिस–यूज भी होता है। जो

धनाढ्य लोग है अगर वे कोई चीज बेचते है या लेते है उनसे कोई फिक्स्ड अमाउन्ट डोने ान के जरिए ले ली जाये। अच्छे काम के लिए है , ली जाये। उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है।

स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत टैक्सै ान के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूं। मैं अपने फाइनैन्स मिनिस्टर साहब की अटैं न ड्रा करना चाहता हूं । आज के जमाने में जहां सारे भारत मे हाउस टैक्स व प्रापर्टी टैक्स एक है, प्रौफे ानल टैक्स नहीं हैं। ठीक है, हमारे लीडर आफ दी हाउस ठीक ही सोचते है, बेहतरी के लिए ही सोचते है। लेकिन मैं एक सुझाव के तौर पर कहूंगा कि आउस टैक्स, प्रौफे ानल टैक्स को मर्ज करके प्रोपर्टी टैक्स में रिवाइज कर दिया जाये ओर अगर उसकी दरें भी बढ़ाना चाहते है तो वह भी बढ़ा दी जाये लेकिन तीनों टैक्सों को एक कर के प्रोपर्टी टैक्स रिवाइज्ड टैक्स में ले लें तो बड़ी अच्छी बात हो जायेगी।

भाराब बन्द करने के बारे में भी मैने एक सुझाव दिया था और आज फिर देता हूं। डिवैल्पमैंट टैक्स लगाकर इस कमी को पूरा कर लिया जाये। जितना अब रैवेन्यू आता है उसको पूरा करने के लिए उसका नाम डिवैल्पमैंट टैक्स हो जाये। ऐसा करने से भाराबबन्दी मुमकिन हो सकती है। बाकी तो जो कुछ होगा वह सैन्टर की तरफ से होगा लेकिन स्टेट्स भी अपने–अपने तौर पर अच्छे ढंग से सोचें तो यह भाराब बन्द हो सकती है।

जैसा कि मिनिस्टर साहब ने कहा कि सेल्ज टैक्स सेल पर नहीं है परचेज पर है। यह ठीक है कि ग्राहक से सेल्ज टैक्स लिया जाता है। क्यों नही इस परचेज टैक्स में कनवर्ट कर दिया जाये या दिल्ली के बराबर इसके रेट्स कर दिये जायें? हरियाणा की मंडी दिल्ली से चलती हैं तब हम दिल्ली की मंडी को कम्पीट कर सकेगें।

स्पीकर साहब, कल फाइनैन्स मिनिस्टर साहब ने भी मेरा हवाला दिया। उन्होनें चाइल्ड टैक्स की बात कह। मुझे खु ाी है कि उन्होने इस प्वांयट को टच तो किया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर सैन्टर सरकार, स्टेट सरकार एक एम0एल0ए0 की आवाज को सुनें तो यह जो सैन्टर ने एक करोड़ रूपया रखा है यह पैसा बच सकता है। तीसरा इ ा होते ही टैक्स लगा दें। अगर तीसरे इश्ु पर टैक्स लगा दें और जो फैसिलिटीज दी जाती है, वे भी विदड्रा कर ली जायें, अगर यह रूल्ज बन जायें,एक्ट बन जाये तो पैसा भी बच जायेगा और आबादी पर भी पाबन्दी लग जायेगी। कोई तीसरा बच्चा बनायेगा तो उस पर चाइल्ड टैक्स लगा दिया जाये।फैमिली प्लानिंग सिस्टम को बन्द किया जाये।

श्री ओम प्रका ा गर्ग: स्पीकर साहब मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। यह जो प्रोपोजल गुलाटी साहब रख रहे है टौर फाइनैन्स मिनिस्टर साहब ताईद करते है, ये दोनों बुढ़े आदमी है। अगर ऐसा करना है तो सोच–समझ कर करना।

श्री के0एन0गुलाटीः स्पीकर साहब, मेरे दिमाग में यह प्वांयट आ चुका है। विद ड्यू रिस्पैक्ट मैंने लगातार यह कहा है ओर इसे मैं जारी रखूंगा। सैन्टर में भी इसके लिये कोि ा ा करूंगा कि चाइल्ड टैक्स लगाया जाये और फैमिली प्लानिंग स्कीम बन्द की जाये।

स्पीकर साहब अब मैं एजुके ान के बारे में इतना कहना चाहता हूं हमारे यहां मदर टीचर्ज 70 के करीब है। वे पांच साल से काम कर रही है। उनके साथ बड़ी हार्डि ाप हो रही है। वे बड़ी गरीब फैमिली से हैं। सरकार ने जहां एजुके ान डिपार्टमैंट में 700–1100 के सिलैक ान ग्रेड लैक्चरार को दिये है, वहां इन गरीबों का भी भला किया जाये। वे तो पहले भी गुजर कर रहे थे और अब भी कर रहे है। ये 70 परिवार जो पूअर फैमिली की गर्ल्ज है जिनकी सर्विस पांच साल से उपर हो गई हैउनको रैगूलर सर्विस में ले लिया जाये। वे फुल टाई पर फुल पैसे पर काम करें।

स्पीकर साहब, अब मैं सो ाल वैलफेयर डिपार्टमैंट के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। विड्डो होम अलाटमैंट होनी है। मिनिस्टर साहब ने भी ए योरैन्स दी हैं अब भी उन्होने कहा कि कोि ा ा करेगें । मैं उनका म कूर हूं। गरीबों की तरफ जयादा ध्यान दिया जाये। इन गरीब विड्डोज को जो 20–25 रह रही है, इनको अलाटमैंट कर दी जाये। ओल्ड एज पैन ान जो आजकल

25 रूपये है, इसको भी 35 रूपये कर दिया जाये तो बड़ा अच्छा होगा।

सिविल सप्लाई डिपार्टमैंट के बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि काफी देर से जो आफिि ायल खाली बोरी रिप्लेसमैंट के बारे में सस्पैंडिड है, उनको बहाल किया जाये। जिनकी गलती है उनको सजादी जाये। जो ठीक है उनको बहाल किया जाये ताकि उनके दिमाग में भी सैटिसफैक ान आये। जिनकी बहुत कम रिप्लेसमैंट है, कम से कम उनको तो जल्दी से री–इनस्टेट कर दिया जाये।

स्पीकर साहब, समाज के अन्दर सारे भारत में और हरियाणा में खास कर लेबर एरिया में मजदूरों में हाहाकार मची हुई है। मैं व्हीट के मुताल्लिक फरीदाबाद के बारे में कहना चाहता हूं । फरीदाबाद दिल्ली के नजदीक है। वहां पर मजदूरों की आबादी बहुत है। वहां पर आटा कम मिलता है। अगर हमारी सरकार ऐसे मजदूर वर्ग की तरफ ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। उनको ज्यादा से ज्यादा आटा दिया जाये ओर उनकी तसल्ली करायी जाये। फरीदाबाद से लोगों को गुड़गांव नहीं जाना पड़ेगा। दो डी0एफ0एस0ओ0 गुड़गांव में बैठे हैं। दो की वहां क्या जरूरत है? एक फरीदाबाद से होडल तक दे दिया जाये तो लोगों का काफी भला होगा। यह एडमिनिस्ट्रे ान की बात है।

इन्डस्ट्री और एग्रीकल्चर के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं। ठीक है कि काफी हद तक पानी कम हो गया। बिजली में काइसिज आ गया है। हमारी सरकार अच्छे ढंग से चल रही है। जितनी भी बिजली उपलब्ध हो सकती है, लेने की कोि ा ा कर रही है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देहाती भाइयों को डे–टाईम में बिजली दी जाये और फैक्टरीज में राम को दी जाये। डे–टाईम में बिजली देनेसे किसान अपनी खेती मे पानी अच्छी तरह से दे सकते है। फैक्टरीज में रात को देने से लेबर वेजिज लौस न होगा।

बिल्डिंग और रोड के मुताल्लिक इतना ही कहना चाहता हूं। कोई भी रोड बनाते समय पता नहीं ठीक प्लानिंग नहीं होती है या क्या कारणहै, स्ड़कों में कट पड़ जाते है। पानी किनारे पर आ जाता है, बंडज टूट जाते हैं। तो इनकी प्लानिंग ठीक होनी चाहिए। सही रोड बनाये जाये। जब तक प्लानिंग पूरी तरह से न हो तब तक रोड भाुरू न की जाये। इतनी मेरी दरखासत है, सुझाव है। अगर सड़क बन कर टूट जाती है तो स्टाफ वालों का फर्ज है कि आते–जाते वक्त देखें कि कहां पर रिपेअर की जरूरत है। जहां पर रिपेअर की जरूरत हो,वहां पर फौरन रिपेअर कर दी जाये ताकि सड़क का ज्यादा डेमेज न हो। टूटने पर मरम्मत की जाती है तो ज्यादा खर्च करना पड़ता है। स्पीकर साहब, मेरे यहां एक पाली रोड है।उसके बारे में मैं सन 1972 से यहां हाउस में चिल्ला रहा हूं।उस रोड के बारे में हाउस में अ योरैन्स भी है,

उसकी थोड़ी सी साईड बाकी है। अगर फाइनैन्स डिपार्टमैंट से या मार्किटिंग कमेटी से कहीं से भी थोड़ा बहुत भी फन्ड मिल जाये तो यह लिंक रोड पूरी हो जायेगी। दूसरे बल्लभगढ़ की लिंक रोड है। यह हरियाणा बनने से पहले की बनी हुई है। किसानों की इस रोड के लिए सख्त डिमांड है। अगर इस रोड को भी पूरा कर दिया तो बड़ी कृपा होगी।

स्पीकर साहब, एजुके ान की एक बात रह गई है वह भी अर्ज कर देता हूं। फरीदाबाद सारे हरियाणा के अन्दर बहुत बड़ा एरिया है। यह सारे भारतवर्श में बड़ा म ाहूर इलाका है। वहां पर बी0ए0 तक की एजुके ान कोई मायने नहीं रखती है। ठीक हैं, इसके लिये यूनिवर्सिटी के कुछ रूल्ज होगें लेकिन यह भी तो सरकार ही बनाती है। रोज नये–नये एक्ट और बिल हमारे सामने आते है ओर हम रोज पास करते है। मेरा इस बारे में निवेदन है कि एम0ए0 तक ऐजूके ान आजाद हिन्हदुस्तान में फरीदाबाद के लोगों को इवनिंग क्लासिज द्वारा दी जाये। वहां पर इवनिंग कालेज हैं। अगर इसके लिये बिल्डिंग की जरूरत है तो वहां पर जो मिडल स्कूल या हायर सैंकंडरी स्कूल की बिल्डिंग हैं, उनमें क्लासिज चालू की जा सकती है। (घंटी)

स्पीकर साहब, मैं जल्दी ही खत्म कर रहा हूं। मैंने सुबह क्वै चन आवर में भी कहा था और अब भी जोरदार तरीके से कहना चाहता हूं कि एक लेबर कोर्ट और एक लेबर ट्रिब्यूनल से काम नही चलता है। लेबरर्ज को दिक्कत पे ा आती है। काफी

समय तक केस का फैसला नहीं हो पाता है।इसलिए मेरा निवेदन है कि लेबर कोर्ट और लेबर ट्रिब्यूनल एक–एक और चाहिये।

स्पीकर साहब, फरीदाबाद में कंज्यूमर स्टोरज की इलैक ान हो रही है। लेटैस्ट स्कीम के मुताबिक लोगों को पलवल जाना पड़ेगा। यह एडमिनिस्ट्रे ान की बात है। जब इलैक ान फरीदाबाद में हो रही है तो स्क्रुटनी और विदड्राल के लिए पलवल जाना पड़ेगा जबकि इलैक ान फरीदाबाद में हो रही है। इसके लिए फरीदाबाद में ही आफिस बनाया जाये ताकि लोगों को पलवल न जाना पड़े।

फरीदाबाद कम्पलैक्स का एरिया बहुत बड़ा है। वहां पर दो या तीन लोकल बसें चलती है, उनसे गुजारा नहीं होता है। कम से कम वहां पर पांच लोकल बसें होनी चाहिये। वहां पर सारे एरिया में लोकल बस बड़े अच्छे तरीके से चल सकती है। अगर सरकार दूसरी बात कर दे तो और भी अच्छा रहेगा। लोकल बस को वहां से वापिस ले लें और वहां पर कम्पलैक्स में मिनी बसें चलायी जायें। वहां कम्पलैक्स वालों को इजाजत दे दी जाये तो वे खुद मिनी बस खरीद सकते है। वहां पर जो लोकल बस चलती हैउसको वापिस ले लें। (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई) डिप्टी स्पीकर सहिबा, टूरिजम डिपार्टमैंट हरियाणा में बहुत अच्छा काम कर रहा है। हरियाणा में बड़ी अच्छी–अच्छी जगह बनायी गयी है लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये सारी चीजें भाहर में ही है, देहाती भाई देखते ही रहते है। हमारे यहां भी देहातों में कोई

अच्छी चीजें बनायी जायें ताकि वे भी ऐन्टरटेनमैंट कर सकें। भााम को, राम को अच्छे हालात देख सकें। इसलिये टूरिजम डिपार्टमैंट देहातों में भी कोई ऐसे कार्यक्रम अपनाये जिससे कि देहातों को भी फायदा हो जाये।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब मैं लोन्ज डिपार्टमैंट को एक सुझाव देना चाहूंगा।

एक आवाजः भाराब की मांग कर लो?

श्री के0एन0गुलाटी0: आपकी अपनी नीति है, मेरी अपनी नीति है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, लोन्ज एण्ड ऐडवान्सिज के मुताल्लिक मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार की यह पालिसी अच्छी है कि वह लोन देती है। इससे पब्लिक के कई किस्म के इन्ट्रैस्ट्स पूरे होते हैं। मैं यह अर्ज करूंगा कि जो लोन्ज डिपार्टमैंट है, वह गवर्नमेंट ऐम्पलाईज को बिल्ट–अप हाउसिज के लिये ओर प्लाट्स के लिये तेजी से लोन दे।।उनकी ऐप्लीके ान की तरफ जल्दी ध्यान दिया जाना चाहिए और लोन के लिये जो डेट फिक्स की होती है, उसके अन्दर ही गवर्नमैंट ऐम्पलाईज को लोन दे दिया जाना चाहिए ताकि वे भी हमारी सो ालिजम की पालिसी का फायदा उठा सकें ओर अपना एक हाउस ओन कर सकें। गवर्नमैंट ऐम्पलाईज के साथ ही मैं एम0एल0एज0 के लिये भी कहना चाहता हूं। मैं खुद एक विधायक हूं। किराये पर रहताहूं और मेरी कोई जायदाद नहीं है। इसलिये

मेरी अर्ज यह हे कि एम0एल0एज0 को विल्ट–अप हाउसिज के लिये लोन मिलना चाहिये क्योंकि प्लाट हम बना नहीं सकते, कभी सीमेन्ट की कमी है तो कभी ईन्टों की कमी है। एम0एल0एज0 को भी बिल्ट–अप हाउसिज के लिये लोन सैक ान कर दिया जाये ताकि हम भी कोई रैडीमेड हाउस लेकर हाउस–ओनर बन सकें। इन अल्फाज के साथ मैं चेयर को धन्यवाद देता हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया गया।

चौधरी दल सिंहः डिप्टी स्पीकर साहिबा, आनरेबल मैंबर श्री गुलाटी ने यह कहा है कि उनके पास मकान नहीं है। मैं उन्हें आफर करता हूं कि मैं उन्हें एक एकड़ जमीन मुफ्त देता हूं, वे आये और उसमें रहे जायें।.....(ाोर व व्यवधान).....

श्री ओम प्रका ा गर्गः डिप्टी स्पीकर साहिबा, चोधरी दल सिंह जी जो जमीन गुलाटी साहब को आफर कर रहे है, क्या उसे वहां के हरिजनों को आफर करेगें?

चौधरी दल सिंहः मैनें पहले ही हरिजनों को 20 बीघे जमीन आफर कर रखी है। आप फिक न करो।

श्री रामधारी गौड(गोहाना): उपाध्यक्ष महोदया, एप्रोप्रिए ान बिल के जरिये हाउस से यह मांग की गयी है कि कल जो रकम पासकी गयी है उसको खर्च करने की सरकार को इजाजत दी जाये। उपाध्यक्ष महोदया, आप जानती है कि हमारी जो डिमान्डज हैं, इनमें ज्यादा रकम वही है जो विकास के कामों

में लगायी जायेगी। इससे नेक काम ओर क्या हो सकता है? फिर हाउस इसके लिये इजाजत क्यों नहीं देगा? मैं फाइनैंस मिनिस्टर साहब को मुबारिकबाद देना चाहता हूं कि वे टैक्स फ्री बजट जाये है और इसमें से भी बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे कामों के लिये खर्च होगा जिससे हरियाणा की उन्नति होगी और आमदनी बढ़ेगी। इससे लोग खु ाहाल होगें। मेरेविचार में कुछ ऐसी चीजें है जिनके लिये और पैसा चाहिये क्योंकि इस एप्रोप्रिए ान बिल में उनके लिये कम पैसा रखा गया है। मैं हाउस को यह बताना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार ने पानी के लिये बिजली के लिये और खाद वगैरा देने के लिये बहुत अच्छे उपाय किये है लेकिन आज जमीन की हाजत ऐसी हो गयी है कि वह छोट–छोटे टिब्बों में बंट कर रह गयी है। अब जमीन इकोनौमिक नहीं है। इसलिये कोई न कोई ऐसी तजवीज सोची जाये या कोई ऐसाबिल लाया जाये जिससे कि 10 एकड़ से नीचे जमीन की तकसीम न हो सके। देहातों में ऐसा देखा गया है कि एक–एक फैमिली के पास दो–दो , तीन–तीन बीघे या एक–एक एकड़ जमीन भी नहीं रह गयी है। आप ही बताइये कि जिस घर में या जिस फैमिली में 10 आदमी हो और उनके पास एक यादो एकड़ जमीन हो तो वह कैसे काम चला सकते है। जमीन की फ्रैगमैंटे ान होते–होते बहुत नीची आ गयी हैं इसलिये मेरी अर्ज यह है कि 10 एकसड़ से नीचे जमीन की तकसीम नहीं होनी चाहिए। आप कहेगें कि अगर तकसीम नहीं होनी चाहिये तो फिर क्या होना चाहिए? मैं यह कहूगा कि कोई परिवार बे ाक फैमिली के ढंग से अलग हो जायें लेकिन वह खेती

इक्ट्ठी करें। उनको जमीन को बांटने की अलालत नहीं होनी चाहिए। इससे कया होगा? इससे अच्छे ढंग से खेती हो सकेगी और उत्पादन जयादा होगा। मैं आपके जरिये हाउस से एक बात और कहना चाहता हूं कि जब तक हम इन्टैंसिव कल्टीवे ान नहीं करेगें तब तक पैदासवार का बढ़ना बहुत मु कल है। जैसे मैंने अभी बताया है, जमीन के बहुत छोटे–छोटे टुकड़े हो गये है और हम जिस पुराने ढंग से खेती करते जारहे है, उससे काम नहीं चलेगा। हमें कोई न कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हम अब भी देहातों में यह देखते है कि जमीदार कहीं से बीज ले कर बो देताहै लेकिन वह बीज काम का नहीं होता। उसके बाद चाहे कितनी ही अच्छी खद डालें, कितना ही पानी दें लेकिन फसल अच्छी नहीं होती। हम जो पानी देते है ओर बिजली खर्च करते है, वह सब बेकार हो जाती है। यह सब बीज के खराब होने की वजह से होता है। मेरी गुजारि ा यह है कि ऐसी कोई पाबन्दी होनी चाहिए कि फाउन्डै ान सीड के अलावा कोई और दूसरा बीज न बोआ जाये क्योंकि बीज की वजह से पैदावार में कमी पड़ जाती है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हरियाणा के अन्दर कम से कम 7–8 लाख एकड़ भूमि ऐसी है जिसमें सेम हो गयी है, थूड़ या कल्लर हो गयी हैं । मेरा कहने का मतलब यह है किकम से कम 7–8 लाख एकड़ भूमि ऐसी है जिसमें बीमारी भुरू हो गयी है। और वह जल्दी ही सेम या थूड़ हो जायेगी क्योंकि उसमें ऐसी बीमारी लग चुकी है। इसलिये मेरी अर्ज यह है कि इसके रिक्लेमे ान के लिये जो पैसा रखा गया है, वह बहत थोड़ा

है और जो समय मांगा गया है, वह बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूं कि रिक्लेमे ान के लिये वार–फुटिग पर काम होना चाहिए। जल्दी से जल्दी जमीन को रिक्लेम करके किसानों को वापिस दिया जाये क्योंकि एक कहावत है:–

ता तरयात अज़ ईराक आवरदा समद मार गजिन्दा मुर्दा भवदः ।

ऐसा न हो कि जब तक वह दवा ईराक से लायी जाये तब तक सांप का काटा हुआ मर ही जाये। ऐसा न हो कि हम 10 साल लम्बी स्कीम बनायें ओर उससे पहले ही हमारा बहुत नुकसान हो जाये। कुछ ऐसी फैमिलीज भी है जिनके पास कोई ऐसे साधन नहीं है जिससे कि वे अपनी जमीन ठीक कर सके। खेती के अलावा उनका कोई और धन्धा नहीं है। देहातों में इसके अलावा एक बात और है देहातों में जाइयें। बहुत बड़ी पापुले ान ऐसी है जिसके लिये कोई भी काम काज नहीं है। वे क्या काम करें,उनको पता नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप भी अपने हल्के में जाती होगी? आप हर जगह एक ही बात देखेंगी कि लोग यह कहेगें कि ये बच्चे है, इनको कहीं नौकरी दिलाओ। इनकों कहीं काम दिलाओ। मेरा कहने का मतलब यह है कि देहातों में बेकार इतने हो गये है कि जब आप जायें तो सिवाय इस काम के कि इसको लगवा दो, उसको लगवा दो, और कोई बात नहीं होती। बेकारी को खत्म करने के लिये वहां पर दस्तकारी का होना जरूरी है। जमीन को हम बढ़ा नहीं सकते लेकिन आबादी बड़ी तेजी से बढ़ती

जा रही है। आज किसान की हालत ऐसी हो गयी है कि उसके घर में अपने बच्चे ही खाली बैठे है। अब जबकि दसवीं पास करने के बाद नौकरी तो मिलती ही नहीं है तो आखिरकार वे खेती ही करेगें। जब जमींदार के पास इतना काम भी नहीं है कि वह अपना गुजाराचला सके तो जिसके पास जमीन नहीं है जो लैंडलैस या भूमिहीन है, आप ही सोचिये उनका क्या हाल होगा? इसलिये मेरा कहना यह है कि जब तक देहातों में दस्तकारी नहीं होगी तब तक कुछ सुधार नहीं हो सकता। अब क्या होता है? हम लोग लोन देते है। उस लोन का क्या होता है? जो हजार–दोहजार रूपया लोन मिलता है, उसको लेने में ही कम से कम सौ–दौ सौ रूपया खर्च हो जाता है। अगर किसी गरीब आदमी को पैसा मिल भी जाता है तो उसके लिये कोई गाइडैन्स नहीं हैं वह बेचारा एक तरफ पैसा लिये होता है तो दूसरी तरफ घर वाले आकर खड़े हो जाते है कि अब तो सरकार से पैसा मिल गया है, कुछ दे दो। कुछ पैसा वह ले जाते है। बाकी कुछ पैसा जो बचता है, वह दूसरे धन्धे में लग जाता हैं इसलिये उस पैसे की वापसी जो है, वह बड़ी मुि कल हो जाती है। मैंने खुद ऐसे आदमी देखे है जो इस वजह से हवालात में बैठे हुये है क्योंकि वे लोन का पैसा वापिस नहीं दे सके। इसकी वजह क्या थी? न तो उसकी गाइडैन्स मिली, न उसको कोई साधन मिले, इसलिये जो लोन उसको मिला, वह जाया हो गया। इसके लिये दो–तीन डिपार्टमैंट बहुत अच्छी मदद दे सकते है। कोआप्रेटिव डिपार्टमैंट और इंडस्ट्रीज डिपार्टमैंट इस ओर बहुत अच्छी मदद दे सकते है। कोआप्रेटिव सोसाइटीज बनायी

जायें और इन्डस्ट्रीज डिपार्टमैंट को कहा जाये कि वह ऐसी सोसायटीज को लोन दे। देहातों में कुछ ऐसी दस्तकारियां हैं जिनमें बास्केट मेकिंग का, टोकरी बनाने का, मूढ़े बनाने का, निवाड़ बनाने और कई किस्म की चीजें बनाने का काम हो सकता है। दरियां बनाने का भी काम हो सकता ळ। देहात के अन्दर छोटे घरेलू काम धन्धे कायम किये जाये तभी देहात के लोगों में भाहरों की तरफ आने की भावना कम हो सकती है। जो लोग देहात से भाहरों मे आते है उनको न यहां पर मकान मिलते है और न कोई दूसरी सहूलियतें मिलती है। अगर वे सहूलियतें उनकों देहात में ही दे दी जाएं तो बहुत अच्छा हो और इससे जो भूमिहीन लोग है या छोटे जमींदार जिनके पास जमीन थोड़ी है ओर कुनबा ज्यादा है, उनका गुजारा हो सकता हैं उनको दस्तकारी में ही लगाकर दे ासे बेरोजगारी खत्म हो सकती है। जब लोगों को काम धन्धे नहीं मिलेगें तो मुल्क में अ ाान्ति फैलेगी और फिर मुल्क की तरक्की नहीं हो सकेगी। सबसे बड़ी बात जो मैंने बताई है वह फैंगमैंटे ान आफ लैंड होल्डिग के बारे में बताई है।

एक ओर विशय में मैं बोलना चाहता हूं। वह कानून तो सैन्ट्रल गवर्नमेंट का है, हरियाणा सरकार का नहीं है ओर वह है लड़कियों को जमीन दैने का। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इससे बहुत झगड़े पैदा होते है। काफी लिटिगे ान हो रही है। कम से कम जिसके पास थोड़ी जमीन है उसमें से तों लड़कियों को न दी जाए। इसकों बचाने के लिए कुछ किया जाये। हम यह चाहते है

कि लड़कियां को सहलियतें पहुचें। आप जानती है कि हमारेसमाज का एक पुराना सिस्टम था कि जब तक लड़कियां जिन्दा है, उनके बच्चे जिन्दा है , उसको आए साल भाई या बाप अपनी आमदनी में से कुछ न कुछ देता रहता था। कभी भात दिया जाता है , कभी छूछक दिया जाता है। वह प्रथा अब खत्म होती जा रही है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो जमीन में लड़कियों का हिस्सा है, यह खत्म होना चाहिए और मैंने यह तजवीज भी दी थी कि दस एकड से कम जमीन को आप तकसीम न होने दें।(घंटी)

उपाध्यक्षः गौड़ साहब, आप कितना समय और लेंगे?

श्री रामधारी गौड़ः मेरे एक– दो प्वांयट और है। जैसे मैंने अभी बताया, बिजली पैदा करने के लिए थर्मल प्लांट की बात कोई नई नहीं है। यह सरकार इसके लिए बहुत कुछ कर रही है। बोर्ड की तरफ से फरीदाबाद में, व पानीपत में काफी काम हो रहा है ओर यह सरकार आगुमैंटे ान कैनाल के जरिये पानी बढ़ाने की भी काफी कोि ा ा कर रही है। तो बिजली और पानी के लिए बहुत कुछ हुआ है। लेकिन कुछ जगह पानी खारा है, उसको भी इस्तुमाल किया जा सकता है। मीठे पानी में खारे पानी का कुछ हिसस मिलाकर नहरों में डाल दिया जाये। मुझे उम्मीद है कि अगर आठ–दस हिस्सा खारे पानी का मीठे पानी मिलाकर इस्तेमाल किया जाये तो उससे कोई नुक्सान नही ंहोगा बल्कि वह खाद का काम देगा। इरीगे ान छिपार्टमैंट को यह तजुर्बा करना चाहिए कि किस मिकदार में खारे पानी में मीठापानी मिलाया जा सकता है।

अगर दसवां हिस्सा भी पानी का बढ़ जाये तो कितना अनाज पैदा होगा इसका आप अन्दाजा लगा सकते है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप जल्दी कर रही हैऔर टाईम भी कम है लेकिन मै फाइनैन्स मिनिस्टर साहब को मुबारिकबाद देता हूं। इस बिल को पास करने में हमें कोई इतराज नहीं हैं बल्कि विकास के काम पर इतना पैसा खर्च हो रहा है, इससे खु ाी है। मैं एक बर फिर मुबारिकबाद देता हूं और अपना स्थान लेता हूं।

श्री हरि सिंह(सम्भालका): डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपका म कूर हूं कि आपने सारे कैंडिडेट्स में से वाकई मुझे ही अच्छा समझा और टाईम दिया। मैं यह वि वास दिलाता हूं कि इस तरफदारी करने के लिये मैं म कूर हूं और मैं आपकी घंटी बजने से पहले ही बैठ जाऊंगा, मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूगां। डिप्टी स्पीकर सहिबा, मैं आज दो–चार प्वायंटस का आपकी मारफत इस सदन में इजहार करूंगा ओर सारे मैंबरों से यह रिक्वैस्ट करूंगा कि वे इन बातों पर अमल करें। अगर वे अमल करेंगे तो हरियाणा जो आज के दिन है, एक साल के बाद ही इससे दस गुणा और ज्यादा तरक्की कर जाएगा। मैंने यहां पर तीन साल के अर्से में देखा है कि लोग यहां पर फिजूल की और खामखाह की बात करते है औरएक दूसरे पर कीचड़ उछालते है। जनता हमको अपना प्रतिनिधि चुनकर चहां भेजती है। अगर हम यहां नुक्ताचीनी न करके सुधार का काम करें तो जयादा अच्छा रहें। मैंबर साहिबान यह कहते रहते है कि ऐसा या वैसा होना

चाहि, सरकार को ऐसा करना चाहए, जनता के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। इस किस्म की बहुत लम्बी–चौड़ी बातें यहां की जाती है। अगर वह वाकई दिल से ऐसी बातें करते है तो उनको चाहिये कि वे आदमी अपने ख्यालात को जिसको वह अच्छासमझते है, उनको प्रेक्टिकल भोप दें हर आदमी प्रैक्टिकल होना चाहिये। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी चाहता है कि करप् ान नहीं होनी चाहिये तो उस आदमी को सब से पहले अपनी गिरेबांन में मुंह डालकर देखना चाहिये और अगर वह करप्ट है तो उसको करप् ान छोड़ देनी चाहियें।जबवह करप् ान छोड़कर ईमानदारी से चलेगा तो उसके आसपास में रहने वाला आदमी जो उसको देखेगा, उसकी तरक ईमानदार होने की कोि ा ा करेगा। दूसरी बात जो है वह यह है कि लोग कहते है कि आबादी बढ़ती जा रही है, फैमिली प्लानिंग करनी चाहिये। इसलिये मेरा कहना है कि पहले तो आदमी को अपने उपर कन्ट्रोल करना चाहिये और फिर दूसरों को कहना चाहिये। कहा जाता है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक् ान इतनी होनी चाहिये। सरकार को यह करना चाहिए, वह करना चाहिए। मेरा कहना है कि इस काम में भी आदमी को प्रैक्टिकल होना चाहियें। थ्योरैटीक्ल बातों से काम नहीं चलता और न ही जबानी बातों से प्रोडक् ान बढ़ने वाली है। अगर हम थ्योरेटिक्ल घोड़े दौड़ाते रहेगें तो इससे पैदावार नहीं बढेंगी। अगर हम वाकई चाहते है कि प्रोडक् ान बढ़े तो प्रैक्टिकल डिमौन्सट्रे ान देकर लोगों, को बताएं कि इसतरीके से पैदावार बढ़ सकती है। उनकों बताएं कि ऐसाी खाद होनी चाहिये इतनी

दफा डालनी चाहिये, इतनी दफा पानी देना चाहिये। गांवमें जो अनपढ़ जमींदार है उनकों समझाना चाहिये, रैलीज करनी चाहिये। गांव के लोगों को बताना चाहिये कि वह अपना बजट कैसे बनाए। फैमिली प्लानिंग कैसे करे। जितनी बातें उन गांव वालों को बताएं, खुद उससे दस गुणा अकेले करके दिखानी चाहिये कि ऐसे काम होता है। तब हरियाणा काफी तरक्की कर सकता है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अभी मैं पिछले दिनों इंडिया की पांच–छः स्टेटों के अन्दर घूम कर आया हूं। लेकिन जैसा ला एंड आर्डर यहां है, वैसा कहीं नही है। खेती की प्रगति और दूसरी चीजों की तरक्की जितनी हरियाणा में है, उतनी कहीं नही है। यह एक असलियत है कि हरियाणा वाकई एक प्रोग्रसिव स्टेट हैऔर इसने हर तरफ तरक्की की है। दूसरी स्टेटों में जाने से पता चलता है कि वाकईहमारी सराकर ने इतनी भारी तरक्की की है और अगर हम इसको ओर तरक्की की तरफ ले जाना चाहते है तो हमें प्रैक्टिकल आदमी बनना चाहिये। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज ही यहां क्वै चन आवर के समय सड़कों के बारे में बहस चल रही थी। जब यह सड़कें सरकार बना रही थी तब मैंने उनको देखा। जो दूसरे तीसेर फालतू किस्म के लोग थे वे कहते थे कि इन सड़कों के उपर तो एक इंचभी रोड़ी नहीं पड़ी है, स्पैसीफिके ांज के मुताबिक नहीं है। यह जो सड़कें बन रही है, ये बिल्कूल बकवास है। इन पर एक कस्सी भर मिट्टी डाली जाये तो एक रूपया कास्ट पड़ती है। मेरी समझ में नही आता कि किस आधार पर वे लोग ऐसी बे–बुनियाद बातें करते थे ओर आज सरकार से कहते

है कि यहां पर सड़क बना दो, यह एक सड़क ठीक करवा दो, वह सड़क ठीक करवा दो। आज अगर सरकार ने दूसरी चीजों को इसके मुकाबले में तरजीह देकर अपनी अटैं ान की डायव र्ान नहरों और बिजली पर कर दी है तो इसमें कौन सी बुरी बात कर दी है? डिप्टी स्पीकर साहिबा कई लोगों का तो यह रवैया ही रहा है कि उन्होने हर बात का क्रिटीसिजम करना है। चाहे सरकार कुछ भी करे, उन्होने तो सरकार के खिलाफ ही कहना है, ठीक रास्ते पर तो चलना ही नहीं है, हमे ाा ही गलत रास्ते पर चलना है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जा सकता है? लेकिन अफसोस यह है कि अगर वे लोग कोई प्रैक्टीकल सुझाव दें तब तो सरकार भी उन सुझावों पर विचार करे। वे तो हमे ाा थियोरैटीकल घोड़े ही दौड़ाते रहते है। कम से कम उन्हें प्रैक्टीकल चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिये। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर वे कोई प्रैक्टीकल काम करेगें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं (इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए) हर लाइफ एक मिसालों में मिसाल बनकर सामने आएगी तो उसकी बात सरकार भी सुनेगी और जनता भी सुनेगी और इस प्रान्त का, इस दे ा का हर तरह से फायदा भी होगा। इन भाब्दों के साथ, स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहां पर बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

चौधरी राम लाल वधवा(करनाल): स्पीकर साहब, बजट अब दूसरी और आखिरी स्टेज में है। सबसे पहले बजट पे ा

हुआ। फिर सप्लीमैंट्री डिमांडज आई और अब एप्रोप्रिए ान बिल आया। सरकार ने खर्च के लिये यहां पर कुछ अपनी मांगे रखी है मैं उन पर कुछ सुझाव दूंगा। मैं आ ाा करता हूं कि सरकार मेरे उन सूझावों पर अव य विचार करेगी और उनको लागू करने की चेश्टा करेगी। सब से पहले, स्पीकर साहब, जहां तक बिल्डिंग्ज और रोड्ज का ताल्लूक है, उसके अन्दर जो डिमान्डज 114691670 रूपये की मैंने देखी है, उसमें तीन मदें है। पब्लिक वकर्स के लिये जो रूपया दिया गया है, उसकी फिगर्ज मैंने देखी है, 85 लाख 20 हजार रूपये। यह रूपया तो दफ्तरों और रैस्ट हाउसिज की कन्स्ट्रक ान के लिये खर्च हो राह है और एक करोड़ रूपया जनरल मैन्टीनैन्स के उपर खर्च किया गया है। एक लाख रूपया रैस्ट हाउसिज में फर्नीचर के लिये, 53 लाख रूपया म ाीनरी की खरीद के लिये और बाकी का सारा रूपया आप देखें कि जितना खर्च कियागया है, वह ऐसटैबलि ामैंट के उपर खर्च किया गया है।

स्पीकर साहब, इसके साथ–साथ इन्होने हाउसिंग के लिए 1953000 रूपये की मांग की है। कुछ रूपया स्लम क्लीरैन्स के लिये ओर एक लाख रूपया हाउस साइट्स फार लैन्ड– लैस वर्कर्स के लिये मांगा गया है और बाकी का सारा खर्चा ऐसटैबलि मैन्ट के उपर किया गया है। तो मैं आपकी मारफत, स्पीकर साहब, सरकार से यह कहूंगा कि गरीब आदमी के साथ यह इतना बड़ा मजाक क्यों किया जा रहा है? एक लाख रूपये से

तो एक से तो एक मामली बस्ती की भी स्लम कलीयरैन्स नहीं हो सकेगी। और फिर इस में से लैन्ड लैस वर्कर्ज के लिये कितने मकान बनेगे? इससे आगे इन्होने 49304000 रूपये की रा ि ा की रोडज एण्ड ब्रिजिज के लिये मांग की है। इसके अन्दर वर्कस जो है, वह बोर्डर रोडज स्ट्रेटेजिक रोडज के लिये तो केवल 30 हजार रूपया रखा है और भोश एक लाख रूपये के करीब मैन्टीनैन्स के ऊपर रखा गया है। डिस्ट्रिस्ट और अंदर रोडज के लिये 1 लाख 25 हजार रूपया रखा गया है पर रोड्ज की मैंन्टीनैन्स के उपर 2 लाख रूपये की रा ि ा रिजर्व की गई है। स्पीकर साहब, तो कहने का मतलब यह है कि इसके अन्दर सड़कें की जरूरत है, वहां के लिये इतनी थोड़ी रा ि ा से आधा मील सड़क भी नहीं बन सकेगी। तो मैं आपकी मारफत सरकार से कहूंगा कि इन सभी स्कीमज के लिये पैसा बहुत थोड़ा रखा गया है और ऐस्टैवलि ामैन्ट पर बहुत ज्यादा खर्च करने का इरादा है। अगर कोई सड़कें वगैरह बनाने का इरादा नहीं है तो इतने बड़े ऐसटैबलि ामैंट रखने की क्या जरूरत है? स्पीकर साहब, सरकार मेरे इस सुझाव पर विचार करे कि जो रोड्ज अधूरी पड़ी है , टूटी हुई हैं, बजाये इसके कि नई सड़के बनाई जांए, पहले उन सड़कों को पूरा किया जाए।

स्पीकर साहब, इसके साथ–साथ जहां सरकार के लिये जनरल एडमिनिस्ट्रे ान के अन्दर पैसा खर्च करना जरूरी है, वहां मैं सरकार से यह कहूंगा कि सरकार यह देख ले कि जो

एस0डी0एम0, जी0ए0 और डी0 सीज0 को जुडि ियल टाइप पावर दे रखी है, अभी–अभी उन्हे रैन्ट कन्ट्रोल की पावर दी गई है, उन्होनें इसके बाद कितने केसिज डिसाइड किये है? स्पीकर साहब, बजाये इसके की जुडीि ायरी की कोई में ये केसिल डिसाइड हो जाये, होता क्या है आज हालत यह है, मैं आपको करनाल की बाबत ही बताता हूं कि करनाल में केसलि की संख्या बहुत बढ़ गई है। 40–40 केसिज होते है। मुन् ाी वगैरह वहां बैठे है। तारीखों पर तारीखें दिये जा रहे है लेकिन सुनवाई कोई नहीं होती है। इससे लोगों को बड़ी परे ाानी होती है। मैं तो यह कहूंगा कि जुडीि ियल कोर्ट की जो पावर्ज है, वह वापस जुडीि ायरी को दी जाएं जिससे कि लोगों को भी रिलीफ मिले।

इसके आगे स्पीकर साहब, मैं म्युनिसिपल कमेटियों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। म्यूनिस्पिल कमेंटियों में जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाये हुये है, वे पार्ट–टाइम लगाये हुये है तो मैं सरकार से कहूंगा कि वह इस बात पर गौर करे। वहां पर कोई काम काज नहीं हो रहा है। एस0डी0एम0 वगैरह वहां पर घण्टा–आध घण्टा के जिये जाते है। कोई उनके काम की और चैक करने वाला है नहीं। वहां पर बड़ा भ्रश्टाचार हो रहा है, इसलिये म्युनिस्पिल कमेटियों में होल–टाईम एडमिनिस्ट्रेटर लगाये जायें ताकि कमेटियों का काम सुचारू रूप से चलता रहे। इसके साथ–साथ सरकार को यह चाहिये कि वह भीघ्राति ाी म्युनिस्पिल कमेटियों के चुनाव करवाये और जितनी जल्दी हो सके। पब्लिक

के नुमाइन्दे वहां पर बैठायें ताकि काम ठीक व सही ढंग से चल सके। इसके साथ–साथ मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि सेल्ज टैक्स का जहां तक ताल्लुक है, आजकल उसकी लिमिट 40 हजार रूपये तक है ओर जो व्यापारी सेल्ज टैक्स पे करता है, उसको लाइसैन्स लेना पड़ता है। आजकल के वक्त में जबकि महंगाई बढ़ गई है, चीजों के भाव बहुत चढ़ गये है, इसमें छोटे–छोटे व्यापारी भी आ जाते है, दुकानदार भी आ जाते है, अतः यह 40 हजार की सेल्ज टैक्स की लिमिट बढाकर 1 लाख कर दी जाये ताकि उन लोगों को परे ाानी न हो।

स्पीकर साहब, हमारी हरियाणा सरकार ने 500 करोड़ रूपये के लगभग जो बजट पे ा किया है, उस में प्रोफै ानल टैक्स का भी जिक्र जाता है। उससे सरकार को भाायद उतनी आमदनी नहीं होती जितनी कि लोगों को परे ाानी होती है। यह जो टैक्स है, यह 800 रूपये आमदनी के लोगों से लेकर 15000 तक की आमदनी वाले लोगों के उपर लगाया जाता है। उसके अन्दर कई एम्पलाइज भी आते है। छोटे–छोटे दुकानदार भी आ जाते है, तो मैं सरकार से आपके द्वारा रिकवैस्ट करूंगा कि इस प्रोफै ानल टैक्स को खत्म कियाजाए। इसके साथ–साथ प्रोपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स का जिक्र कर रहा हूं। इस के बारे में कई बार इस सदन के अन्दर कई मैंबर साहेबान ने भी कहा है कि एक ही प्रोपर्टी पर दो प्रकार के टैक्स नहीं होनेचाहिये। इसलिये सरकार लोगों की सहूलियत के लिये इस पर विचार करे। इन

दोनों टैक्सिज के बारे में असैसमैंट के तरीके भी अलग–अलग है, और डिपाटमैंट भी अलग है। मैं तो यह कहूंगा कि प्रापर्टी टैक्स चाहे 10 की बजाये 12 परसेन्ट कर दें लेकिन लोकल बाडीज को उस में भोयर देकर एक ही डिपार्टमैंट के अन्डर यह काम दे दिया जाये। एक ही जायदाद के उपर दो प्रकार के टैक्स नहीं होने चाहिये। इसके साथ–साथ जहां तक ऐजुके ान का संबंध है, इसके अन्दर 319553450 रूपये के खर्चे की स्वीकृति सरकारइस सदन से मांग रही है और हमको इसे स्वीकार करना ही है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि 32 करोड़ रूपया खर्च करने के बाद हम इस हरियाणा में से कितनी अन–एम्पलाएमैंट दूर कर पाए है और कितनी एजुके ान लेकर आते है वे आते ही नौकरियों की तला ा करते है। अंग्रेज ने अपनेवक्त में यह सिस्टम आफ ऐजुके ान लागू किया था क्योंकि उसको सर्वेन्ट चाहिये थे। उस समय तो ऐजुके ान ही नौकरी देने के लिये दी जाती थी। लेकिन 27 साल के बाद भी हम उस ऐजुके ान के सिस्टम को बदल नहीं सके। इस सारे ढांचे की डिवैल्पमेंट, विकास तरक्की के जितने भी कार्य हम करना चाहते है उसकी भावना जो है वह एक ही जगह आकर केन्द्रित होती है। आज जो आने वाली नसल है उनके अन्दर ज्यादा से ज्यादा एम्पलाएमैंट हो और वह अपने पैरों पर आप खड़ी हो तो उस नौकरियों की ओर न जाकर अपने हाथ से काम धंधा करने काउत्साह लाना पड़ेगा और इसके लिये हमें सिस्टम आफ ऐजुके ान को बदलना पड़ेगा। 32 करोड़ रूपया हरियाणा राज्य हर साल ऐजुके ान पर खर्च करे तो आप अन्दाजा

लगाएं कि 27 साल में हमने कितना रूपया खर्च किया ओर इतना रूपया खर्च करने के बाद भी आज हम देखते है कि हमारे पास अन–एम्पलाएमैंट कितनी है। इसलिये मैं सुझाव दूंगा कि प्राइमरी क्लास से ही कोई ऐसी चीज रखनी चाहिये जिससे कि छोटे बच्चों की मनोस्थिति को बदला जाए कि नौकरी की तरफ नही दौडना हे बल्कि उसे अपने हाि से काम धंधे करने है। फिर उसके बाद मिडल क्लास से उनको काम धंधे करने के तरीक सिखाये जाने चाहियें। जैसे साबून बनाने का, जुते बनाने का ओर कई टैक्नीकल काम है, ऐसी ि ाक्षा देनी चाहिये। अगर ऐजुके ान के सिस्टम को इस तरह से बदल किया जाए तो सारे प्रान्त का अच्छे ढंग से विकास हो सकता हैं और आने वाले नौजवान सड़कों के चक्कर लगाने की बजाये अपने काम धंधे करेगें इसलिये सरकार से मेरा निवेदन है कि वह इस और ध्यान दे। इसके बाद मैं अर्बन डिवैल्पमैंट पर आता हूं। इसके लिये सरकार 7290440 रूपये की स्वीकृति मांग रही है। इसमें ग्रान्ट इन एउ टू म्युनिसिपैल्टीज 5 लाख रूपये है ओर ग्रान्ट इन एड टू इम्प्रवमैंट ट्रस्टस यह 55 हजार रूपये है । तो 5 लाख 55 हजार को छोडकर बाकी 67 लाख रूपया अर्बन डिवैल्पमैंट के महकमें पर, उनके टी0ए0 ओर मोटर गाड़ियों पर खर्च करने की बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह महकमे की डिवैल्पमैंट हो रही है या अर्बन डिवैल्पमैंट हो रही है? अर्बन डिवैल्पमैंट तो तब होगी जब आप म्युनिसिपैल्टीज को एड करेगें। आप देखें कि करनाल में सीवरेज की स्कीम को चालू हूये कई साल हो गये है। जो भाहर के लिये स्कीमें थी, उनको

बाहर ले जाया जा रहा है।.....(घंटी).....। इसके आगे इस अर्बन डिवैल्पमैंट के अन्दर कैपिटल आउटले में 10 करोड 50लाख रूपये, प्लानिंग के उपर 6 करोड 60 लाख रूपये ओर ऐस्टैबलि ामैंट के उपर 75 लाख रूपये और म ाीनरी इक्विपमैंट पर 15 लाख रूपये ओर अदर ऐक्सपैंडीचर 3 करोड़ रूपया हैं तो यह रूपया जो दफ्तरों की तामीर पर लगा रहे है, अगर यही रूपया अर्बन डिवैल्पमैंट के लिये म्युनिसिपल कमेअियों ओर इम्प्रूवमैंट ट्रस्टों को दे दिया जाए तो अच्छी डिवैल्पमैंट हो सकती हैं इसके बाद लेबर और एम्पलाएमैंट की बात है। इसके लिये सरकार 11540820 रूपये मांगती है लेकिन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्ट के उपर सिर्फ 84680 रूपये खर्च हो रहे है। आज कल लेबर बढ़ गई है और इसके कारण इनके झगडे भी बढ़ गये है। आज किसी को नौकरी से निकाला जा रहा है, किसी को वैसे तंग किया जा रहा है, तो ये सारे केस लेबर कोटर्स में ही आते है। आज आप देखें कोर्ट मे ं40 केस लगे हुये है लजेकिन हियरिंग मु ि कल से दो की हो पाती है। इसलिये सरकार इस तरफ ध्यान दें। मैंने पहले भी कहा था कि मिनिमम बेजिज ऐक्ट और पेमैंट आफ वेजिज ऐक्ट , इंडस्ट्रियल डिसप्यूट ऐक्ट, वर्कमैन कम्पनसै ान ऐक्ट और मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्ज ऐक्ट है। अलग–अलग जगह इनको फैला रखा है। हर एक जिले में क्योंकि कोर्ट तो सिर्फ दो जगह ही हैं इसलिये एक अफसर को जगह–जगह भेजने की बजाए अगर हर एक जिले में एक–एक सै ान जज को इस काम के लिए लगा दिया जाए तो लेबर को भी सुविधा रहेगी

और सरकार का भी खर्चा बचेगा। (घंटी) ट्रांसपोर्ट के बारे में मुझे इतना ही कहना है कि उसके अन्दर भी घपले चलते हैं और सरकार इस बात को स्वीकार भी करती हैं। इस सिलसिले मैं मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि डिस्ट्रिक्ट जैवल पर ए परमानैंट कमेटी बनाई जाए जो हर महीने डिपो का देखें। तो स्पीकर साहब, इसके साथ ही ..... (घंटी) ..... बस जी, मैं आखिरी बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्षः इसके लिए दो घंटे का टाईम फिक्स है। श्री गर्ग।

श्री ओम प्रका ा गर्ग (थानेसर): स्पीकर साहब, आपकी मार्फत मै दो चार बाते ही अर्ज करना चाहता हूं। इस बजट के अन्दर अधिकतर रूपया एग्रीकलचर के लिए रखा गया है। क्योंकि यह सब भाइयो का पता है कि आज दे ा में ज्यादा उन्नति करने की जरूरत है इसलिए हमारी गवर्नमैंट ने एग्रीकल्चर पर ज्यादा रूपया रखा है। इस रूपये से पानी और बिजली का इन्तजाम किया जायेगा। बिजली और पानी का इन्तजाम होने से जहां खेती को बढ़ावा मिलेगा, वहां किसान को भी फायदा होगा। इंडस्टरी को जब बिजली अच्छी तरह से मिलेगी तो जहां इंडस्ट्री के मालिक को फायदा पहुंचेगा। वहां इंडस्टरी में काम करने वाले लेबर को भी फायदा होगा। मेरे से पहले बोलने वाले मेरे भाई ने बोलते हुये कहा कि लम्बी–लम्बी तारें लगा दीं, खम्बे लगा दिये लेकिन बिजली का इंतजाम नहीं किया। इन्होंने यह भी कहा कि इतनी देर सरकार क्या करती रही? तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिस

वक्त पंजाब और हरियाणा बना, उस वक्त की गवर्नमैंट में वह सदस्य आई0पी0एम0 होते थे। जिस वक्त बिजली का बंटवारा हुआ तो वे ब।टवारा करने वालों में से थे। तो यह गलती मेरे उस दोस्त ने भी की थी। तो जहां तक बिजतल कि उत्पादन का सवाल है, उत्पादन की तरफ तभी जाया जाता है जब ज्यादा जरूरत हो जाती है। अब हमें बिजली की जरूरत ज्यादा हो गई है इसलिये हम ज्यादा पैदा करने की कोि ा ा कर रहे हैं लेकिन अगर हम पहले ही ज्यादा बिजली पैदा कर लेते तो इन्हाने यह कहना था कि इन्होने इतनी बिजली पैदा कर दी जितनी कि खर्च नहीं हो सकती और खमखाह में रूपया खर्च कर दिया। तो ये तो इनकी अपनी नुक्ताचीनी की बातें है। इससे पहले भाराब की बात की गई। आप देखें कि जब से ये भाई कांग्रेस से निकल कर दूसरी पार्टियों में गये है तभी से भाराब की खपत ज्यादा होने लगी है। इसकी वजह और क्या है? यही है कि ये सारा दिन इसी चक्कर में लगे रहते है कि कभी स्टुडैंटस को बहकाते है, कभी मुलाजिमों को बहकाते है और कभी किसान को बहकाते है। और बहकता कोई कब है?.....(विधन).....भाराब पी कर बहकते है। यह भाई राम लाल जी जो है, आप भी बहकते होगें, औरो को भी बहकाते है.....(हंसी).....। इनका बहमना तो मुनासिब है क्योंकि अगर इस किस्म का रोजगार उनका छूट जोय जिससे भााम को स्कॉच की बोतल आ जाती है, जो ओवर लोडिगं से सवारियां ज्यादा जाती थी, उससे आ जाती थी तो इनका बहकना तो जायज है, सही है.....(विघन)...मेरे कहने का मतलब यह है कि यह

इलजाम तो लगाते है गवर्नमैंट पर लेकिन मेहरबानी है इनकी खुद की इस बारे में । मेरे से पहले एक दोस्त उठे ओर कहने लगे कि जब सड़कें इतनी बनाई नहीं जा रही तो फिर इतने मुलाजिम क्यों रखे हुये है? इनका कहने का भाव यह नही है जो यह कहते है बल्कि यह चाहते है कि जब गवर्नमैंट कुछ मुलाजिमों को निकाल दगी तो फिर वे उनके पास जायेगें ओर ये उनको बहकायेंगें कि आओ भाराब पीयो और एजीटे ान करो। .....(हंसी)..... दरअसल इनको कोई काम चाहिये और काम भी वह जो तामीरी न हो। इनको ऐसे काम से कोई कतलब नहीं जिससे दे ा का भला हो, प्रदे ा का भला हो। जो भला इन्होने किया है, वह आप सब के सामने है। यह तो गड़बड़ करना–करवाना चाहते है लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ऐसे है ओर उनकी सरकार ऐसी है कि चह चला नहीं पाते है। यह ठीक है कि यह भाराब का प्रचार करनें में बिल्कुल कायमयाब हुये है, लोगों के दिमाग को इन्होने बिगाड़ा है लेकिन गवर्नमैंट का भला जरूर किया है क्योंकि भाराब से सरकार की आमदनी बढ़ा दी है। अगर यह प्रचार करने की बजाये गांव–गांव में जा कर लोगों को समझाये कि भाराब न पियो, यह बुरी चीज है तो बात समझ में आ सकती है लेकिन यह भाई यहां कुछ कहते है और बाहर जा कर कुछ कहते है, कुछ प्रचार करते है, मेरे एक दोस्त यहां है जो अपने आपको किसान कहते है। वह हमे ाा यही बात करते है कि किसान को गेंहूं की उपज का रेट पूरा नहीं मिलता, ज्यादा नही मिलता। एक तरफ तो रेट बढानें की बात करते है ओर दूसरी तरफ कहते है कि सरकार ने मंहगाई

बहुत बढ़ा दी लेकिन यह भाई इस बात को नहीं समझते कि जब अनाज का रेट बढ़ेगा तो क्या मंहगाई बढ़ेगी या घटेगी? इनकी ऐसी बातं कहने की भावना यह है कि दे ा के लोग खराब बने, गलत किस्म की बातें करे ताकि इन भाइयो को मौका मिले कि वह उन को बहका कर गलत रास्ते पर डाल सकें और गवर्नमैंट के खिलाफ कर सकें। फिर यह महात्मा गांधी जी के आद र्ा की भी बातें करते है लेकिन आप देखें कि जब से ये दोस्त इन बैंचिज से उन बैंचिज पर गयें है तब से भाराब की खपत बढ़ी है क्योंकि इन्होंने लोगों को बहकाने के लिये, गलत रास्त पर डालने के लिये इस बात का ही प्रचार किया।

अब मैं अपने हल्का के बारे में दो–चार बातें कहना चाहता हूं। मैं अर्ज करता हूं कि गवर्नमैंट का ध्यान हर मामला में हरियाणा की समुचे तरक्की की तरफ है और मेरे ये भाई इस बात से बहुत चिन्तित है क्योंकि इस गवर्नमैंट को इस बात का कतई ख्याल नहीं कि इस हल्का में तरक्की करनी है या दूसरे हल्का में नहीं करनी है। चाहे विरोधी दल वाजों का हल्का है या सरकारी पक्ष वालों का हल्का है, सरकार ने बगैर किसी भेदभाव के विकास के काम किये है। तो इनको इस बात की भी चिन्ता है कि कोई बात बहकाने के लिये मिल नहीं पा रही हैं। मैं हस्पतालों की बात करता हूं। हरयिाणा में बहुत सारी जगहों में बड़े–बड़े हस्पताल बनाये गये है जो पाच–पांच सौ ओर हजार–हजार बैड्ज के है। नारायणगढ़ जैसी जगह पर आप देखें कितनी भाानदार बिल्डिंग

बनाई गई है, जिसकी इनआग्रे ान के बारे में नारायणगढ़ के भाई कभी सोच ही नहीं सकते थे कि वहां इतना बढ़िया हस्पताल बन सकता है। इसी तरह मैं अर्ज करता हूं कि कुरूक्षेत्र मं भी एक बहुत आला हस्पताल बन रहा है। लेकिन मै यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस वक्त हस्पतालें की फैसिल्टीज की बहुत जरूरत है जैसे कि छोटे–छोटे कस्बों में इन फैसिल्टीज को देने की बहुत जरूरत है। ऐसा ही एक कस्बा लाडवा है। वहां पर एक छोटी सी लेकिन अच्छी डिस्पैंसरी है। उस में एक डाक्टर और एक लेडी डाक्टर है। वहां पर लोगों ने अपनी तरफ से कुछ प्राइवेट वार्डज एगैरा बनवाये है। मेरे ख्याल में उन पर बीस हजार रूपया लगा होगा। लोगों ने दान में एक रैफ्रिजीरेटर भी दिया जो पांच हजार का होगा ओर दूसरी चीजें, पंखे वगैरा भी दिये है। यह कहने से मेरा मतलब यह है कि गवर्नमैट के पास फंडज की कमी है इसलिये ऐसी जगहों में आली ाान इमारतें बे ाक न बनायें, उन पर बे ाक पैसा न खर्च करें और वहां पर छोटी–छोटी बिल्डिंग्ज में ही वह सारी फैसिल्टीज दे दें जो बड़े हस्पतालों में दी जाती हैं। हमारे लाडवा में लैबोरेटरी नहीं है, ऐक्स–रे प्लांट नहीं है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि लम्बी–चौड़ी इमारतें बनाने की बजाये छोटी बिल्डिंग्ज में ही सारी फेसिल्टीज दे दें। जब कभी वक्त आयेगा ओर फंडज हो जायेगें तो बड़ी बिल्डिग्ज भी बना लेना लेकिन अब छोटी बिल्डिग्ज में ही बड़े हस्पतालों वाली सहूलियतें दे दी जाये। दूसरी बात यह है कि हरियाणा में सीड कारपोरे ान बनाई गई है। यह बहुत अच्छी बात की गई है। इस बारे में मैं यह

अर्ज करना चाहता हूं कि पिपली के मुकाम पर सीड प्रौसैंसिंग प्लांट लगाया जाना चाहिये क्योंकि वह मुनासिब जगह है। यह कुरूक्षेत्र और करनाल के बीच है और दोनों जिले एग्रीकल्चर के लिहाज से मेरे ख्याल में हिन्दुस्तान भर में अव्वल है। सड़कों के बारे में बहुत बड़ा प्रोग्राम चला था और उस वक्त मेरे यह भाई बड़े परे ाान थे। कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे। लेकिन अब रोड्ज का काम कुछ रूक गया। कुछ तो मेरे दोस्तों ने रूकवा दिया, हाई कोर्ट से स्टे ले आये ओर इस वजह से काम रूका पड़ा है। मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि कम से कम जो रोड्ज में बीच में गैप रह गये है, उनको पूरा कर दिया जाये। अगर सात मील लम्बी कोई रोड बनी है ओर उसके बीचमें एक किलोमीटर या सौ मीटर का गैप रह जाता है तो वह सात की सात मील की रोड बेकार है। इसलियै मेरी प्रार्थना है कि यह जो गैप है, कम से कम यह जरूर ठीक करायें जायें। अब मैं टूरिज्म के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। इस बारे में हरियाणा ने बहुत तरक्की की है, इस में कोई भाक की बात नहीं। हमारे हरियाणा में पहले कोई जानता ही नहीं था कि टूरिजम होता क्या है। अब आप देहली से चलें तो रास्तें में देखें टूरिस्टस के लिये कितने सुन्दर स्थान बन गये है लेकिन पिपली के मुकाम को जब देखते है तो कुछ मजेदार बात नहीं लगती है। तो मेरी अर्ज है कि टूरिजम के प्वांयट आफ व्यू से पिपली को खास तौर पर से खूबसूरत स्थान बनाया जाये। अब मैं ट्रांसपोर्ट पर आता हूं। इस में बहुत विकास का काम हुआ है, और हमारे भाई राम लाल जी को इस बात का बहुत दुख है।

कहते है, यह लगा दो, वह लगा दो, सुपरवाइजर लगा दें, भाायद इनका ख्याल हो तो इनको ही बिठा दो। (हंसी) जहां इतना बड़ा काम होता है, उसमें गड़बड़ भी हो जाती है और ओवरलोडिंग भी होती है। ओवरलोडिंग के बगैर काम भी नहीं चलता हैं, न कंडक्टर का चलता है और न ही सवारी का चलता है। सवारी जो नीचे खड़ी होती है वे कहती है कि किसी तरह से अन्दर घुसा जाये कंडक्टर अन्दर खड़ा समझता है कि मंहगाई का जमाना है। कर्नल साहब ने इन्तजाम तो बहुत बढ़िया किया है और ट्रांसपोर्ट को अच्छे ढंग से चला भी रहे है। इस में भाक की बात नहीं। ट्रांसपोर्ट में यह है कि आखिरी टाइम्ज लौस मे जाते है क्योकिं गड़बड़ आखिरी टाईम में ज्यादा होती है ओर वह टाईम अक्सर बन्द भी हो जाते है क्योंकि लोस में जाते है और समझा यह जाता है कि सवारी कम मिलती है। इस में असल में ऐसी बात नहीं है। लौस नहीं हेाता है। दूसरी बात हो जाती हैं । बस स्टैंडों के लिए जमीनें ली जा रही है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बस स्टैंडों के लिये जल्दी जमीनें लेकर बसें खड़ी करने का इन्तजाम जरूर कर देना चाहिये।

17.00 बजे

दूसरी बात मैं हरिजनों के बारे मे कहना चाहता हूं। जो हरिजन बे–जमीन है ,बेसहारा लेाग है, उन को गाय भैंस खरीदने के लिये सरकार की कर्जा देने की जो स्कीम है, वह बहुत अच्छी है क्योंकि इससे उनका दूध का मसला हल हो जाता है

जिसकों बेच कर वे गुजारा करते है। लेकिन उस कर्जे का तभी फायदा हो सकता है अगर सरकार प ुओं के चरने के लिये चरागाहें प्रोवाइड करें। चरागाहें तो क्या होगी, उन के पास तो चारपाई डालने के लिए भी जमीन नहीं है, इसलिये गवर्नमैंट उन बेजमीन लोगों को जमीन देने का इन्तजाम करें। पहले तो चरागाहें होती थी लेकिन अब नहीं है। जहां सरकार उनके लिये कर्जा देती है वहां चरागाहों का इन्तजाम करना भी जरूरी है। जब तक कौमन–चरागाहें नहीं होगी, यह स्कीम कामयाब नहीं हो सकती।(घन्टी)

स्पीकर साहब, एक बात और अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि प्रौपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स को अगर इक्ट्ठा कर दिया जाये तो कोई हर्ज की बात नहीं है। कुरूक्षेत्र में ऐसे आदमी है जिन पर यह टैक्स लगा दिया। इनके पास एक–एक कच्चा कोठा है जिसमें 5 रूपये महीना किराये पर भी नहीं रहा जा सकता। जो आदमी यहां बैठे है वे तो मुफ्त भी नहीं रह सकते । इसलिये मेरी सरकार से अर्ज है कि प्रोपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स को इक्ट्ठा कर दिया जाये। इसमें अर्ज की कोई बात नहीं है।। एक और बात है ओर वह यह है कि म्युनिसिपैलिटी में होल टाइम ऐडमिनिस्ट्रेटर होना वाकई बहुत जरूरी है। जब तक होल टाईम ऐडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा, मयुनिसिपलिटी का सुधार नहीं हो सकता। (घन्टी)

स्पीकर साहब, सब जानते है कि कुरूक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट नया बना है लेकिन वहां पर जुडीि ायल कोर्ट नहीं है। मिन्नी–सैक्रेटेरियट का प्रोग्राम मुझे ठण्डा पड़ता नजर आता है, इसलिये वहां पर टैम्पोरेरी जुडीि ायल कोर्ट का इन्तजाम किया जाये ताकि पब्लिक को सहूलियत हो सके। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके इलावा, स्पीकर साहब, पीने के पानी की बहुत दिक्कत है। ठीक है, हमें यह पता नहीं था कि बारि ा न होने की वजह से इतनी तकलीफ हो जाएगी। कई सालों से बारि ा न होने की वजह से देहातों में पानी बहुत नीचे चला गया है। तीन–तीन, चार–चार साल से लगातार बारि ा नहीं हुई। नलके तो लगें हुये है लेकिन पानी नेचे चले जाने के कारण उनमें पानी नहीं आता। अब लोग बिजली की तरफ देखते है कि कब आती है। इसलिये मेरे कहने का मतलब यह है कि सुबह और भााम कम से कम एक घन्टा पानी के लिए जरूर बिजली मुहैया की जाये। एग्रीकल्चर के पर्पज के लिए जो एम0आई0टी0सी0 के ट्यूबवैल लगे हुये है। अगर इनके साथ दो–दो, चार–चार गांवों की इक्ट्ठी वाअर सप्लाई स्कीम बना दी जाये तो यह मसला हल हो सकता है। हमारे यहां छोटे–छोटे गांव है जो एक–एक मील के फासले पर है। अगर आप इस को कन्सीडर कर लें और ऐसी वाटर सप्लाई स्कीम बना दी जाये तो उनका पर्पज हल हो सकता है। एम0आई0टी0सी0 के ट्युबवैल बेकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे पानी नहीं देते बल्कि उनको बिजली नहीं मिलती। मेरे ख्याल में आप सात–सात, आठ–आठ, दस–दस गांवों की

इक्ट्ठी टंकी बना दे तो पर्पज हल हो सकता है। (घन्टी) हमारे यहां थोड़े–थोड़े फासले पर छोटे–छोटे गांव है । (घन्टी) स्पीकर साहब, आप घंटी बजा रहे है इसलिये मुझे बैठना ही पड़ेगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री अध्यक्षः अब भााह हकूमत राय बोलेगें। आप पांच मिनट बोल लीजिये।

भााह हकूमत राय(पानीपत): स्पीकर साहब, मैंने बजट पर भी हिस्सा नहीं लिया और आज बोलने वाले भी बहुत कम है, इसलिये थोड़ा टाईम और दे दें। स्पीकर साहब, कई दिनों से मेरे साथियों ने बजट पर ओर डिंमाड पर बहस में हिस्सा लिया। हर सदस्य को, जैसा उसका सोचने का तरीका है, उसके मुताबिक पूरी आजादी है कि वह अपने ख्यालात का इजहार करे। इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ सदस्य विरोधी पार्टी के होने के नाते फिजूल आलोचना करते है ओर सरकार की प्र ांसा से दुखी होते है। यह सब जानते है कि 1968 के बाद जब से हरियाणा की बागडोर चौधरी बंसी लाल के हाथ में आई है, क्या–क्या तरक्की हुई? 1968 के पहले ओर बाद के फर्क को आप देखें तो महसूस करते है कि नुमायां तरक्की हुई है। लेकिन अपनी जुबान से इसका जिक्र करना वे मुनासिब नहीं समझते। हमें इस बात का अफसोस नहीं है, कि ये जरूर प्रं ासा करें, मगर एक अच्छी बात से जानबूझ कर आंखें मूंद लेना कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसी बातों का विरोध करना

जो असल में अच्छी है, लोगों को बहकाने के लिए अच्छी बातों को गलत बताना, कोई भाोभा की बात नहीं है। मेरे एक दोस्त ने कहा था कि बजट थोथे आंकडों का पुलंदा है। बजट के आंकड़े तो सही है। बड़ी सोच समझ कर लिखे गये है। उनको थोथा बताना ठीक नहीं है। मैं उन का क्या कहूं? वे अपने आपको पुराना पार्लियामैंटेरियन समझते है। उन्होनें कहा कि वे इस बात से इन्कार नहीं करते, तारें है, खम्भे है, लेकिन बिजली नहीं है। उन्होनें यह भी कहा की नहरें है, ट्यूबवैल है, लेकिन पानी नहीं है। यह तो बिल्कुल हकीकत के उलट है। स्पीकर साहब, नहरें भी है, टयूबवैल भी है ओर पानी भी है, तारें भी है ओर उनमें बिजली भी है, मगर एक बात आप जरूर मानेगें कि बिजली उतनी नहीं जितनी हमारी खपत है। जितनी खपत है उतनी बिजली मिलती नहीं है। इसके अलावा हमारे इरीगे ान एंड पावर मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में खुले लफ्जों मे कहा था कि हमारी खपत इतनी है और हमे मिलती इतनी है। जो बिजली मिलती है उसका ज्यादा हिस्सा सरकार ने एग्रीकल्चर को देने की कोि ा ा की है ताकि हमारी पैदावार ज्यादा हो। पैदावार के लिहाज से आत्मनिर्भर होने के बाद ही हम दूसरे प्रान्तों को सप्लाई कर सकते है। पहले ऐसा होता था कि अपने खाने के लिए भी अनाज हरियाणा में पैदा नही होता था। आंकड़े इसके गवाह है। यह हकीकत है कि जब से हम पंजाब से अलविदा हुये है जब से हरियाणा वजूद में आया, उस वक्त से पहले हम बाहर से अनाज मंगवाते थे ओर आज बावजूद इन कठिनाइयों के कि कई सालों से बारि ा नहीं हुई, बिजली

कम पैदा हुई, इस वर्श भी हमने अनाज बाहर के प्रान्तों को दिया है। यह गौरव की बात है। इतनी कठिनाइयां होने के बावजूद भी हमारे पड़ोसी राज्यों को हमारे यहां से फालतू अनाज गया है। इसमें हमारी बड़ी भाान है। अनाज की बढ़ोतरी करने के लिए सरकार ने प्रयत्न किये है, इसमें सन्देह नहीं, मगर कुदरत से किसी का मुकाबला नहीं होात। पहले बारि ा वक्त पर होती थी मगर आज दो–तीन साल से बारि ा नहीं होती। सरकार ने अपने जराये से, बैंकों से कर्जा लेकर, ट्यूबवैल लगाकर, जो आबपा ाी के साधन जुटाये थे, उन के लिए बिजली की कमी है। बिजली के साधन बहुत कम हैं। इतना होने के बावजूद भी सरकार सोई हुई नहीं है सरकार सोचती रहती है। 60–60 मैगावाट के दो यूनिट फरीदाबाद मे लगाये है। सिंचाई मंत्री ने बताया था कि फरीदाबाद के पहले यूनिट से जो चालू हो गया है, 40 मैगावाट बिजली मिलनी भाुरू हो गई है। मेरे भाई भाायद पानीपत गये भी न हों लेकिन यहां कह दिया कि काम बड़ी सुस्त रफतार से हो रहा है। कितनी लाईनें वहां बिछ चुकी है, सरकार कितनी तेजी से उस काम में जुटी हुई है, यह उन्हे नहीं पता है। सरकार की यह कोि ा ा है कि जल्दी से जल्दी यह थर्मल प्लांट चालू हो। मगर जो लोग वहां गयें ही नहीं, जिन्होनें जाने का कश्ट किया ही नहीं, वे अगर कहते है कि एक–एक साल में एक–एक थर्मल प्लांट खड़ा कर दो तो उचित नहीं है। आखिर म ाीनरी फिट करनी है, लाईनें बिछाने के लिए, दूसरे साधनों के लिए टाईम लगेगा। सरकार जितनी कोि ा ा कर रही है उसकों देखते हुये मैं

सरकार की सराहना करता हूं। काम भ्रारू किया हुआ है और उससे कुछ बिजली मिलनी भ्रारू हो गई है। तो मैं समझता हूं कि सरकार अपने तौर पर बड़ा यत्न कर रही है कि किसान ओर इंडस्ट्रियलिस्ट को बिजली पूरी मिले ताकि अनाज और औद्योगिक वस्तओं की पैदावार जयादा बढ़े। तो स्पीकर साहब, बिजली जुटाने के लिए सरकार जो साधन अपना रही है, वे ठीक है। लेकिन जैसा मेरे एक भाई ने कल यहां कहा था, मैं भी उस सिलसिले में आपके द्वारा सरकार से एक अर्ज करना चाहता हूं। मैंने भी अपने यहां के पानीपत कोआप्रटिव भ्रूगर मिल के जनरल मैनेजर से दरियाफ्त किया था और उन्होनें मुझे बताया है कि मार्च के बाद मिल बंद हो जाती है । लेकिन अगर सरकार चाहे तो मार्च के बाद भी वे पन्द्रह हजार यूनिट बिजली डेली सप्लाई कर सकते है। तो मेरी अर्ज यह हे कि अगर सरकार ऐसा प्रबन्ध कर ले ओर मार्च के बाद जब वह मिल बंद हो जाये वे बिजली देना भ्रारू कर दे तो मैं समझता हूं कि हमारे उस औद्योगिक नगर के लिये, इंडस्ट्रियल टाऊन के लिए इतनी बिजली बहुत है। उससे उसके सारे उद्योग चल सकते है। उम्मीद है सरकार इस ओर ध्यान देगी। स्पीकर साहब, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। वैसे तो हमारे मिनिस्टर साहब ने वाजेह कर दिया था कि हम सबसे पहले प्रायरिटी एग्रीकल्चरिस्ट्स को देते है ओर उसके बाद उद्योग को और खास तौर पर उस उद्योग को देते है जिसने ऐक्सपोर्ट का माल तैयार करना होता है। यह उनकी बड़ी सराहनीय बात थी। मगर मेरा ख्याल है, अगर मैं गुस्ताखी

नहीं करता, इसमें बिजली वाले नीचे वाले कर्मचारी ओर अधिकारी अमल नहीं करते। कैसे नहीं करते? इसकी मैं एक मिसाल देता हूं।

श्री अध्यक्षः मिसाल देने में टाईम बहुत लगेगा, आप जल्दी किजिये।

भााह हकूमत रायः पानीपत में एक स्टील प्लांट है जो माल ऐक्सपोर्ट करता है। यह बात हरियाणा के क्रेडिट में जाती है क्योकि इससे सरकार को फारेन ऐक्सचेंज मिलता है। उसने इराक को साठ लाख रूपये का पाईप 31 मार्च तक देना किया है। दस लाख रूपये का माल तो जा चुका है लेकिन पचास लाख रूपये का माल अभी नहीं दिया गया है। अगर यह माल उस तारीख तक नहीं दिया गया तो जो पैनल्टी उन्होनें रखी है, वह देनी पड़ेगी। इससे न उनको फायदा होगा ओर न सरकार को ही लाभ होगा। इसलिये मेरी गुजारि ा है कि अगर उनको डेली आइ घंटें बिजली मिल जाये तो उनका काम आसानी से चल सकता है। स्पीकर साहब, यही नहीं, ऐसे–ऐसे उद्योग भी पानीपत में हैं जहां चादरें, टैपिस्ट्री और गलीचे आदि भी बनते है। .....(विघन) चाहे उनकी सारी चीजें खड्डियों में बनती है लेकिन सूत बनाने के लिए ओर फिनि िंग के लिए उन्हें भी बिजली की दरकार है। बिजली न मिलने से उनका काम भी रूका पड़ा है। उनरका माल भी बाहर नहीं जा सकता जब तक उन्हे भी बिजली न मिले। इसलिये मेरी गुजारि ा है कि अगर हम भाूगर मिल वाली बिजली हासिल कर

सकें तो उससे हमें बहुत सहायता मिलेगी। स्पीकर साहब, इंडस्ट्री डिपार्टमैंट वाले खड्डी वालों को बहुत लिबरली कर्जा देते है। यह बड़ी अच्छी बात है। पानीपत दस्तकारी का भाहर है। छोटी दस्तकारियां इसमें बहुत है। आप यह बात सुरकर हैरान होगें कि इस वक्त कोई बीस हजार खड्डिया वहां है, जिनमें से तेरह हजार इंडस्ट्रीज डिपार्टमैंट से रजिस्टर्ड है ओर बाकी सात हजार में इंडिविजुअली लोग काम करते है। इनमें से पचास परसैंट तो कोआप्रटिव सोसायटी के तौर पर काम कर रहे है ओर कोआप्रेटिव सोसाइटीज सरकार की तरफ से सस्ते सूद पर कर्जा भी लेती है। कोआप्रटिव बैंक्स, सैन्ट्रल कोआप्रेटिव बेंक्स, और दूसरे बैंक्स से भी वे कर्जा सस्ते सूद पर लेती है। लेकिन बिजली की कमी की वजह से उन सब का काम भी रूक गया है। अगर यह बिजली मिल जाये तो इनका काम भी चाहे वह फिनि ंग का है या चाहे सूत बनाने का है, चाहे उन का है या दूसरा नं0 2 का है आसानी से चल सकता है।

स्पीकर साहब, हमारी सरकार की तरफ से भाौप्स ऐक्ट लागू है। बहुत अच्छी बात है। मगर भाौप्स ऐक्ट कहां लागू होना चाहिये– जहां पर मुलाजिम हों, दुकानों में लोग काम करते हों। जैसे मैंने पहले कहा, वहां बीस हजार के करीब खड्डियां है। उनमें हजारों यू0पी0 से आये हुये लोग काम करते है। सूत रंगने वाली ओरतें काम करती है। ये उजरत पर काम करते है, डेली वेजिज पर वे काम नहिं करते । उनका ठेका होता है। उनका यह

हिसाब होता है कि एक खेस बनेगा तो इतने पैसे मिलेगें और इतने खेस बनेगें तो इतने पैसे बलेगें । लेकिन उन पर भी भाौप्स ऐक्ट लागू है। उनको भी भाौप्स इंस्पैक्टर आये दिन तंग करते है। भाौप्स ऐक्ट लागू रहे मगर जहां उनके भाो रूम्ज है वहां पर रहे। उन दस्तकारों परख जो मेहनत करते हैख जो दस बार घंटे लगा कर के अपनी मजदूरी पूरी करते है, यदि यह ऐक्ट लागू हो तो इससे उनके काम में रूकावट पैदा होती है। वे यदि सामत बजे आएं, एक बजे छुट्टी कर लें, फिर तीन बजे आयें ओर सात बजे चले जाये , तो इससे तो उनका पेअ नहीं भरता। इस भाौप्स ऐक्ट की वजह से उन्हें बड़ी परे ाानी होती है। इस परे ाानी से बचने के लिए ख्डडी वालों को भी ओर लेबर को भी अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ इस्पैक्टर्ज को देना पडता है। मैं समझता हूं कि यदि यह लानत उन खड्डियों से खत्म हो जाये तो यह करप ान वाली बात जिसका रोज यहां चर्चा होता है, खत्म हो जाएगी क्योंकि उन मजदूरों को कुछ देना नहीं पड़ेगा।..... (घंटी).....

स्पीकर साहब, केवल एक मिनट और लूंगा। पुलिस थाना सिटी की बिल्डिंग की हालत बड़ी खस्ता है। एस0एच0ओ0 का क्वार्टर गिर चुका है। वह आजकल एस0एच0ओ0 थाना सदर की बिल्डिंग में रहता है। अगर किसी ने उससे ि ाकयत करने जाना हो कोई इमीजिएट नेचर की ि ाकायत हो , तो लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसके रहने के

लिये मकान कोई नहीं है। इसी तरह से पुलिस कांस्टेब्ल्ज के लिए भी जगह नहीं है। इसलिये मैं गुजारि ा करूंगा कि जितना पैसा इस पुलिस की मदद में रखा गया है इसमें से कुछ पैसा पुलिस स्टे ान सिटी की बिल्डिंग को मुरम्मत करवाने पर फौरी तौर पर खर्च किया जाये।

स्पीकर साहब, बोलने को तो अभी बहुत सी बातें थी लेकिन चूंकि आगे आप बोलने की आज्ञा नहीं दे रहे इसलिये इन भाब्दों के साथ ही आपका धन्यवाद करते हुये मैं अपनी जगह लेता हूं।

श्री अध्यक्षः मित्तल साहब, आप कितना वक्त लेगें?

वित्त मंत्री(श्री राम सरन मित्तल): जितना आप देगें।

श्री अध्यक्षः श्री अमर सिंह, केवल पांच मिनट के लिए।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, दो मैंबर जनसंघ के है , तीन बी0एल0डी0 के है। जितना टाईम उनकों दिया गया है उतना टाईम मुझे दे दें क्योंकि हमारी पार्टी से तो कोई बोला ही नहीं है और न ही बोलेगा।

श्री अध्यक्षः आर्डर प्लीज। साढ़े पांच बजे मैं गिलोटीन एप्लाई कर दूंगा। उससे पहले फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने भी बोलना है। इसलिये आप केवल पांच मिनट ही बोलिये।

श्री अमर सिंह(बवानीखेड़ा अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, सदन में ऐप्रोप्रिऐ ान बिल(नं02), 1975, जेरे बहस है। इस बिल के जरिये, स्पीकर साहब, यह सदन 4841163806 रूपये वर्श 1975–76 में खर्च करने की स्वीकृति सरकार को दे रहा है। स्पीकर साहब, सदन में कई दिनों से बजट पर बहस होते हुये तरह–तरह की बातें आई है लेकिन मेरी विचारधारा के अनुसार इस ऐप्रोप्रिए ान बिल को और इस साल 1975–76 के बजट को अगर किसान बजट कहा जाये तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। इस ऐप्रोप्रिए ान बिल के जरिये इरीगे ान डिपार्टमैंट को 526409495 रूपये, ऐग्रीकल्चर डिपार्टमैंट को 91613300रूपये, कोआप्रटिव डिपार्टमैंट को 322363490 रूपये और एजुके ान डिपार्टमैंट को 319550450रूपये दिये जा रहे है। इससे जाहिर है स्पीकर साहब कि जो मेजर हैडज है, जिनसे किसान को ओर दस्तकार को तरक्की मिलती है इन्सान को रोटी रोजी मिलती है, उन पर जयादा पैसा खर्च करने का सरकार ने फैसला किया है। यह एक सराहनीय कदम है। स्पीकर साहब, चूंकि समय थोड़ा है इसलिये मैं तीन–चार हैडज के तहत ही अपनी राय जाहिर कंरूगा। आज सरकार को दो तरफा चैलेन्ज का सामना करना पड़ रहा है। एक साईड में तो राईल इन प्राइसिज, राईज इन अनऐम्पलायमैंट, इन्क्रीज इन पापुले ान, कुरप् ान और जनरल डिग्रेडे ान इन करैक्टर है और दूसरी तरफ चैलेंज है फ्रस्ट्रेटिड पालिटीि ायन्ज ओर रीऐक्ानरी फोर्सिज की तरफ से। आज फ्रस्ट्रेटिड पालिटीि ायन्ज और रीऐक्ानरी फोर्सिज ने अपना

तालमेल बनाकर एक जिहाद जम्हूरियत के विरूद्ध खडा किया है क्योकिं आज की हकूमत में वे कुर्सी को अपना नहीं सके, कुर्सी को जम्हूरियत के रास्ते से अपना नही सके तो उनकी यह प्लानिंग है कि किसी तरीके से इस राइज इन प्राइसिज के दौर में, राइज इन अन–एम्पलामैंट में दे ा के दौर में दे ा की जमूहुरियत को किसी तरह चैलेन्ज करके कुर्सी को हथिया लें। इनकी चुनौती सरकार के सामने है। बहुत सारी बातें भारत साकार के नोटिस में है और उनमें यह भी बात है। स्वीकर साहब, बहुत जनये, त्यादा बवा को गर्म कर दिया जाये ता नजीता अच्छा नहीं हो सकता। जिस तरह से पिछले दिनों से बिहसार में आन्दोलन चल रहा है, जिस तरह से सरगर्मी नजर आ रही है उस वहस से तो हरियाणा दूर है। मेरी ता गुजारि ा है कि स्पोर्टसमैन सिपरिट होनी चाहिए। जिस भावना से दे ा को आजाद कराया था, उसी भावना से अब भी काम किया जाना चाहिए। जिस स्पिरिट से भाहिदों की कुर्बानियां दी थी, उसी भावना से ही पैसा भी खर्च होना चाहिए। सरकारी म ाीनरी जो कुछ पैसा बचा सकती है, इकोनामिक ढंग से खर्च कर सकती है उसे खर्च करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वे रास्ते अपनाये जायेगें। यह जा चैलेन्ज है, इस चैलेन्ज का मुकाबला किया जाये। हरियाणा प्रान्त ता भाान्तिर्पिय प्रान्त है। यहां पर भी स्टुडैन्टस को बहकाने की बात की गई है। हमाने हरिजन नेता आउस के अन्दर और हाउस के बाहर भी इस बात को हवा देने की कोि ा ा करते है कि हरिजनों के लिये कुछ नहीं हुआ। मैं यह मानता हूं कि जितना होना चाहिये था उतना

नहीं हुआ। वे ये सब बातें आज तो कहने वाले बन गये है लेकिन वे तो सन 1952 से सन 1968 तक राज की गद्दी पर रहे है। मिनिस्टर भी रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे लेकिन उन्होने कोई स्थायी प्रोग्राम हरिजनों के कल्याण के लिए नहीं बनाया। मैं सन 1962 से 1967 तक इस सदन का मैंबर रहा हूं। इन्होने उस टाईम पर हरिजनों के लिए कोई काम नहीं किया। उस टाईम पर तो वे काटने को दौड़ते थे । वे कहते थे कि क्या हरिजन–हरिजन बना रखा है? उनके बारे में कुछ नही ंसुझता था। आज जब कुर्सी नहीं है तो उनको याद आता है तो मैं गनीमत समझता हूं। अब एक्सप्लाएटे ान के ढंग से उन्हें हरिजनों की बात यादा आती है, कंस्ट्रेक्टिव ढंग से नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जहां पर ये चुनौती है वहां पर उसके साथ ही सरकार को भी बेहतरीन तरीके से चलना चाहियें। एग्रीकल्चर के विकास के बारे में बजट पर बोलते हुये मैने बताया था ओर सुझाव भी दिया था। अब मैं इन्डस्ट्र के बारे में बोलना चाहता हूं। गावों के अन्दर भी स्माल स्केल, विलेज इन्डस्ट्री यूनिट लगाये जाने चाहियें। दो ही तो भाोबे हैः एक दस्तकारी और दूसरा जमीन जिससे किसी को रोजगार मिल सकता है। जमीन का सीना चीर कर जमीदार अनाज पैदा करता ह। उसकी रोटी उससे जुडी हुई हैं आज जमीन की तरफ लैन्डलैस लोग क्यों आकर्शित है? उसका सबसे बड़ा कराण यह है कि उन्हें जमीन के सिवाय रोटी का रोजगार नजर नहीं आता है। लैन्डलैस दूसरे उधोग धन्धों में नही जाते है। आज इन्डस्ट्री मिनिस्टर महोदय ने ए योरैन्स दी है। अब हरिजनों को

कनस्ट्रेक्टिव लाइन पर लगाने वाले कम है। वे बहकानेवाले लोग जमीन का केवल जिक्र करके रह जाते है असलियत पर नहीं पहुचतें। आज जरूरत इस बात की है कि स्माल स्केल यूनिअ गांव–गांव में दे कर उनकों लाभ पहुचाया जाये। आज गांव में बिजली है। बिजली के क्राइसिज है, कट है, क्योंकि इन्द्र महाराज की निगाह कुछ कड़ी है इसलिये नहरों में दरियाओं में पानी नहीं है। तो इस कारण से हमें कट का मुकाबला करना पड़ रहा है। लेकिन यह हकीकत है कि गांव –गांव में बिजली है। जिस तरक एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढाने के लिये ट्युबवैल काइस्तेमाल किया जता है। उसी तरीके से दस्तकारी का, उधोगों का इस्तेमाल किया जाये। ब्लाकवाइज यूनिट बना दिये जायें। लैन्डलैस एग्रीक्लचरिस्ट को एजुकेट करें। उनको यह बतायें कि इस लोन के पैसे को किस यूनिट में लगाये। उनको यह बताया जाये कि इस लोन के पैसे को किस यूनिट में लगायें। उनको यह बताया जाये कि इतना पैसा तो फाइनैन्शल कारपोरेशन लगायेगी और इतना पैसा आप लगायें जिससे आपकी स्थायी रोजी कमाने का धन्धा बन सके। (घंटी) स्पीकर साहब आप जल्दी करते है तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्षः मिनिस्टर साहब ने रिप्लाई देना है, उसके लिये भी तो वक्त देना पड़ेगा।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब आप इजाजत दे तो दो मिनट और बोल लेता हूं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि

कोआप्रटिव डिपार्अमैट के तहत जो पैसा खर्च करना है वह 322369490रूपये है । इस बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसे मैथड अडोप्ट कियो जाये कि आइडैंटिटी कार्ड ओर फोटो देख कर पैसा डिस्ट्रिब्यूट किया जाये। किसानों की लैन्ड के हिसाब से एग्रीकल्चर सर्विस पास बुक बनी हुई है। उस एग्रीकल्चर सर्विस पास बुक को इस्तेमाल करने के लिए उसी के हिसाब से उनके खाते खोल दिये जाये। उसमें उसका फोटो लगा दिया जाये। उसका डारैक्ट लिंक कोआपरेटिव बैंक से बना दिया जाये। आठ–आठ ओर दस–दस गांवो में कोआप्रेटिव बैंक बना दिये जाये। लैंड मुकर्रर कर दी जाये कि पांच एकड़ पर 10 हजार रूपये कर्जा मिलेगा और दस एकड़ पर 15 हजार रूपये कर्जा मिलेगा ओर 18 एकड़ पर 20 हजार रूपये कर्जा मिलेगा। जितनी किसी की जमीन होती है वह पास बुक में दर्ज होती है। बीच के बिचौले जो एग्रीकल्चर इन्सपैक्टर वगैरह है, ये सब हट जायेगे। किसानो का सीधा लिंक बैंक के साथ हो जायेगा।

अब मैं थोड़ा सा मैडीकल के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। हास्पिटल्ज की हालत अब कुछ ठीक है। बहुत सारी जगहों पर नये हास्पिटल भी खोले है, डिस्पैंस्रीज भी अपग्रेड हुई है लेकिन स्पीकर साहब मैं आपकी मार्फत अर्ज करनाचाहता हूं कि मैडीसन्ज की बहुत बुरी हालत है।वहां पर दवाईयां और पट्टिया तक नहीं मिलती जो कि बहुत मामूली सी चीज हैं मैडीसन्ज तो मिलती ही नहीं है। इसलिये मेरी सरकार से गुजारि ा है कि इस ओर ध्यान

दे। इन छोटी–छोटी चीजों का तो आम लोागें को जरूर फायदा होना चाहियें। (घंटी) एक मिनट और लुंगा। अभी खत्म करता हूं।

ट्रांसपोर्ट के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूं। हमारी रोडज ट्रांसपोर्ट ने ानेलाइज हो चुकी है। बसों की हालत बहुत खराब है। इस बारे में कर्नल साहब से सुझाव देनाचाहता हूं। एक तो बेहतरीन तरह के वर्क ाप बनाये जाये ओर उनमें ट्रेन्ड फिटर रखें जायें दूसरे मोबाइल वर्क ाप भी साथ रहने चाहिये। सिरसा से दिल्ली के लिए मोबादल वर्क ाप चालू की जाये। अगर कोई बस रास्ते में ब्रेक–डाउन होगी तो उसको वह उसी वक्त सम्भाल लेगी। कहने को तो बहुत सी बातें रह गयी परन्तु आपकी घन्टी का ध्यान राते हुये मैं अपना स्थान लेता हूं। आपका बहुत–2 धन्यवाद जो अपने मुझे समय दिया।

वित्त मंत्री(श्री राम सरन चन्द मित्तल): अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिए ान बिल पर चौधरी दल सिंह के सिवाये बाकी ओर किसी तरफ से कोई क्रिटिसिज्म वाली बात नहीं है। चौधरी दल सिंह जी ने एक बात में स्वीपिंग स्टेटमैंट दी। उन्होने कहा कि पिछले पांच–छः साल से जब से यह गवर्नमैंट पावर में आयी हे तबसे किसानो के लिए कोई तरक्की नहीं हुई। ऐसे इम्पोर्टट प्वांयट पर एक बड़ा ब्लैक और असटोनि िंग स्टैटमैंट दिया है। उन्होने यह कहा कि किसानों की हालत खराब है और इस सरकार ने उनकी हालत सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है पता नहीं वे कहां से फिग्र्ज ले आये। मैंने इसके बारे में

कल फिग्र्ज कोट की थी। उन फिग्र्ज को रिपीट नही करूंगा लेकिन दो–चार दूसरी चीजों के बारे में जिनकों उन्होने रैफर किया है उनके बारे में फिग्र्ज मेरे पास है। ट्रैक्टर्ज के बारे में इन्होने यह कहा है कि ट्रैक्टर्ज की तादाद कुछ भी नहीं बढ़ी लेकिन इसके बारे में हरियाणा गवर्नमैंट की जो पब्लि ाड स्टेटमैंट है, उससे मैं बता देता हूं। वे कह रहे थे कि ट्रैक्टर्ज नहीं बढ़े आप इन फिग्र्ज को सुनिये कितने ट्रैक्टर्ज बढ़े है, सन् 1966–67 में 4803 ट्रैक्टर्ज थे, सन् 1967–68 की फिग्र्ज मेरे पास अवेलेबल नहीं है जब कि चौधरी दल सिंह इन–पावर थे। उस टाईम पर नहीं बढ़े होगें क्योंकि सिवाय'' आया राम गया राम'' के और कुछ नहीं होता था। यही किस्सा होता रहा। सन 1968–69 के अन्दर 9403, 1971–72 में 15680 और 1972–73 मै 19414 ट्रैक्टर्ज थे। अब आप देखिये कंहा 1966–67 के अन्दर 4803 ट्रैक्टर्ज थे ओर कहां 1972–73 के अन्दर 19414 ट्रैक्टर्ज थे। मैंने यह इसलिये बतलाया है कि ट्रैक्टर्ज सिवाय खेती के ओर किसी काम तो आते नही इसलिये जो ये ट्रैक्टर्ज बढ़े है, इनसे यह साफ जाहिर है कि हम जरायत के अन्दर तरक्की कर रहे है। फर्टीलाइजर कन्जम्प ान के बारे में भी उन्होने बहुत कहा। इसकी फिगर्ज ले लीजिये। 1966–67 के अन्दर 67000 टन्ज, 1968–69 के अन्दर 235000 टन्ज, 1971–72 के अन्दर 410000टन्ज, 1972–73 के अन्दर 470000 टन्ज। अब आप ही देखिये 1966–67 के अन्दर इसकी कन्जम्प ान आधे लाख सेकुछ ज्यादा थी और 1972–73 के अन्दर हमारी कन्जम्प ान 470000 टन्ज हो गयीं मैं यह इसलिये कह रहा

था कि जो फिगर्ज उन्होने कोट की, वे ठीक नहीं थी। हमारी सही हालत यह है, जो मैने बतायी हैं हाई–इलिंडग वैरायटीज के अन्डर जो जमीन थी , उसकी फिगर्ज मैं हैक्टेयर्ज में बताता हूं। 1966–67 के अन्दर 16000 हैक्टयर्ज और 1972–73 के अन्दर 1325000 हैक्टेयर्ज अब आप बताइये, कहां सोलह हजार और कहां सवा तेरह लाख ओर फिर यह कहते है कि पिछले पांच–छः साल के अन्दर ऐग्रीकल्चर की कोई तरक्की नहीं हुई । फूडग्रेन्ज की प्रोडक ान की बात भी इन्होने कही। फूडग्रेन्ज के नीचे टोटल एरिया ओर फूडग्रेन्ज की प्रोडक ान यानि कितना फूडग्रेन्ज पैदा हुआ है, यह मैं बता देता हूं। 1966–67 के अन्दर 2592000 टन्ज और 1971–72 के अन्दर 4543000 टन्ज फुड–प्रोडक ान है। अब बताइये कितना डिफरैन्स है? कहां 25 लाख और कहां 45 लाख? करीब–करीब डबल हो जाती है। फिर ये कहते है कि साहब तरक्की नहीं हुई। एरिये की बात लीजिये। 1966–67 के अन्दर 3520000 हैक्टैयर्ज और फिर 1972–73 के अन्दर 3968000 हैक्टेयर्ज। आप ही देखिये कितना फर्क पड़ गया है। मुझे यह इसलिये कोट करना पड़ा है क्योंकि अगर न कहा जाता तो भाायद वे यह समझते कि हमारी बात सही है और वे इसका उल्टा अर्थ निकाल लेते। एरिये के अन्दर, फुड–ग्रेन्ज की क्वांटिअी के अन्दर ट्रैक्टर्ज की तादाद के अन्दर और फर्टीलाइजर की कन्जम्प ान चानि हरेक बात के अन्दर बहुत ज्यादा बढोतरी हुई है ओर एग्रीकल्चर के उपर बहुत रूपया खर्च हो रहा है। अभी हमारे साथी चौधरी अमर सिंह जी ने बतलाया है कि एग्रीकल्चर के अन्दर,

पावर के उपर और इरीगे ान के उपर कितना रूपया खर्च किया जा रहा है लेकिन इनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। इनका तो एक स्वीपिंग स्टेटमैंट हो गया कि कुछ नहीं किया और फिर सुजैस्ट क्या करतेहै कहते हैं कि गवर्नमैंट को रीजाइन कर देना चाहिये। मैं इनको बता दूं कि आपको ओब्लाइज नहीं किया जायेगा...(व्यवधान)... इसके अलावा उन्होने एक बात यह कही कि यहां पर बहुत हैवी टैक्सिज लगे हुये है। कल मैंने इस बारे में फिग्र्ज कोट की थी। मैं दोबारा उस पर कहने की जरूरत महसूस नहीं करता। इंडियाके अन्दर तमाम स्टेटस के साथ आप मुकाबला कर लीजिये। हमारे यहां टैक्स जयादा नहीं है। (चौधरी चांद राम जी की और से व्यवधान) आज चौधरी दल सिंह जी यहां बैठे है, मैं इसलिये यह बात फिर कह रहा हूं। आप तो कल थे नहीं इसलिये मैंने यह मुनासिब नहीं समझा कि आपकी बात का जयादा जवाब दिया जायै। हैवी–टैक्से ान के जवाब में मैंने कल फिगर्ज कोट की कि पंजाब, जिसकों सबसे बड़ी प्रौसपरस स्टेट कहा जाता है, वहां पर टैक्सिज ज्यादा है। हमारे यहां पंजाब से कम टैक्से न है। दूसरी स्टेट्स से तो हमारा मुकाबला ही नहीं हो सकता। इसके बावजूद यह कहा जाता है कि हैवी–टैक्से ान, हैवी टैक्से ान। तो यह ठीक नहीं है। इसके बारे में मुझे इतना ही कहना था। इसके अलावा मुझे एक बात और कहनी है। चौधरी रामलाल जी ने ऐजुके ान के बारे में कहा। मैं उनकी इस बात को कुछ इद तक ऐप्रि ीयेट करता हूं कि एजुके ान के लिये लड़को का कुछ माइन्ड इस तरह से चेन्ज करना चाहिये कि वे

क्लैरीकल साईड की और न जायें । लेकिन मैं आपके द्वारा उनको प्रार्थना करूंगा कि अगर वे लड़कों को ऐक्पलायट न करें तो वे ठीक तरह से पढेगें। .....(व्यवधान)..... जो यह लड़को को ऐक्सप्लायट किया जाता हैं इससे वे एजेके ान में ज्यादा खराबी करते है। .....(व्यवधान) ऐजुके ान के उपर रिफार्म्ज के लिये एक कमेटी बनी हुई हैै। आप यह भी जानते है कि इस बारे में कमेटियां ओर कमी ान्ज बनते ही रहते है और चन्जिज होती ही रहती है लेकिन क्रकोडाइल टीयर्ज बहाने का क्या फायदा? मेरे कहने का मतलब यह है कि जो ऐजीटे ानल आप्रोच है, वह ठीक नहीं है। ऐजुके ान का मतलब यह नहीं कि लड़कों को ऐक्सपलायट करके फायदा उठायें। लडकों को बहका करके ऐजीटे ान करवाना कोई अच्छी बात नहीं है। .....(व्यवधान).... हमारे कई मित्रों ने बहुत अच्छे सुझाव रखे है और अपने हल्के की भी बहुत सी बातें कही है। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था और अब भी यही निवेदन है कि उन्होने जितनी भी बातें कही है, उनकी हरेक बात पर विभाग पूरा विचार करेगें और जो उचित कार्यवाही होगी, वह पूरी की जायेगी। इतना ही निवेदन करके मैं आपके द्वारा सदन से यह कहूगा कि इस बिल को पास कर दिया जाये।

Mr. Speaker: Question is-

that the Haryana Appropriation (No.2) Bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: The House will now take up the Bill clause by clause.

Clauses 2 & 3

Mr. Speaker: Question is-

That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.

The motion was Carried

Schedule

Mr. Speaker: Question is-

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That clause I stand part of the Bill

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

The enacting formula be the enacting formula of the Bill

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That title be the title of the Bill

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

Shri Ram Saran Chand Mittal: Sir, let me first move the motion.

श्री अध्यक्ष: गिलोटीन लगने के बाद मैं ही मो ान पुट करूंगा।

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation (No.2) Bill be passed.

The motion was carried.

अनुपूरक अनुमान(तीसरी किस्त) 1974–75

Mr. Speaker: According to the previous practice, all the Demands for Supplementary Grants will be deemed to have been read and moved.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 11303160 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 3-Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 39726610 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 4 – Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 690930 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 5- Excise and taxation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 728780 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No.6- Finance.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 244410 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 8- Buildings and roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 27976790 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No.9 - Education.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 13-Social Welfare and Rehabilitation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in

the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 17-Agriculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 159650 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 20-Forest.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 48426420 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 15-Irregation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4500000 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 16-Industries.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 48362800 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 22-Co-Operation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 6158800 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 23-Transport.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 27801930 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 25- Loans and Advances by State Government.

(No member reose to speak)

Mr. Speaker: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 11303160 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 3- Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 39726610 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 4- Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 690930 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 5- Excise and Taxation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 728780 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 6- Finance.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 244410 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 8 – Buildings and Roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 27976790 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 9- Education.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 13- Social Welfare and Rehabilitation.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 17- Agriculture.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is –

That a supplementary sum not exceeding Rs. 159650 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 20- Forest.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 48426420 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 15- Irrigation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4500000 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 16-Industries.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 48362800 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 22- Co-Operation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 6158800 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 23 - Transport.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 27801930 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 25- Loans and Advances by State Government.

The motion was carried.

वर्श 1969–70 के अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगो पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker: All the demands will be deemed to have been read and moved.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 177621 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 9- Land Revenue.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 12877 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 14- Stamps.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 28487 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 25- Supplies & Disposals.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 920715 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 43-44 Irrigation, Navigation. Embankment and Drainage Works (Commerecial and Non Commercial).

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1505593 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of Charges on Irrigation Establishment.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1132949 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 50- Public Works.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 591672 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of Charges on Buildings and Roads Establishment.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1338172 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 64-Famine Relief.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 3156964 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 65- Pension and other Retirement Benefits.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 2468 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 67- Privy Purses and Allowances of Indian Rulers.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 25072605 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 98- Capital Outlay on Multipurpose River Schemes.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 71102 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 120- Payment on Commuted Value of Pensions.

कृशि मंत्री(चौधरी भजन लाल): यह तो पुरानी चीज है, इस पर कोई क्या कहेगा?

वित्त मंत्री(श्री राम सरन चन्द मित्तल): इस पर किसी ने क्या बोलना है, आप इसको पुट कर दो।

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs. 177621 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 9- Land Revenue.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 12877 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 14- Stamps.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 28487 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 25- Supplies & Disposals.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 920715 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-

70 in respect of 43-44 Irrigation, Navigation. Embankment and Drainage Works (Commerecial and Non Commercial).

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1505593 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of Charges on Irrigation Establishment.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1132949 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 50- Public Works.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 591672 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of Charges on Buildings and Roads Establishment.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1338172 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 64-Famine Relief.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 3156964 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 65- Pension and other Retirement Benefits.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 2468 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-

70 in respect of 67- Privy Purses and Allowances of Indian Rulers.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 25072605 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 98- Capital Outlay on Multipurpose River Schemes.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 71102 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 120- Payment on Commuted Value of Pensions.

The motion was Carried.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 2.00 P.M., Tomorrow.

17:42 P.M.

(The Sabha then adjourned* till 2-00 P.M. on Thursday, the 16th January, 1975)